भरण-पोषण का हक

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण-पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण-पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकार को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का उत्तरोत्तर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब हम 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता के चलते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेदन के बाद भी महिला को भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। निस्संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले का मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाकशुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण-पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन-यापन का संकट बड़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाकशुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाकशुदा बेटियों का जीवन-यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागत योग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था। जिसके बाद देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला था। निस्संदेह, चार दशक बाद अब भारतीय समाज में लैंगिक समानता को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया है।

नए बजट से मध्यम वर्ग को राहत का सवाल

डॉ. जयंती लाल भंडारी

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आयी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश की जा सकती है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र था कि मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाएगा।

गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के समय आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई २है। साल 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और बीते 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019-20 में 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह 2020-21 में कुछ घटा। लेकिन 2021-22 में 14.08 करोड़ रुपये, 2022-23 में 16.64 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।

ऐसी मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहतों से लाभान्वित किया जा सकता है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह धनराशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिए घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं जहां आमदनी कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। वेतनभोगी वर्ग द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी कर दाता वर्ग द्वारा चुकाए गए आयकर से काफी अधिक होता है।

नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्सपेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। इसके साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।

निःसंदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान संभव है। महत्वपूर्ण यह भी कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा महंगी कारें खरीदी, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे वहीं वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर विदेश यात्राएं कीं। जाहिर है पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियां और विदेश यात्राएं संभव हैं। लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। बता दें कि वर्ष 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शून्य आयकर देयता बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। वहीं अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहीत किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है।

उम्मीद करें कि इस बार वित्त मंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

सुधारवादी मसूद की ईरान में ताजपोशी

अरूण नैथानी

लेखक व साहित्यकार

ईरान में वर्ष 1997 से लेकर 2005 तक सुधार वादियों की हुकूमत रही है। अब तक यह होता रहा है कि कोई सुधारवादी यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकन दर्ज कराता तो कट्टरपंथियों के वर्चस्व वाली हाई प्रोफाइल गार्डियन काउंसिल उसे खारिज कर देती। इससे सुधारवादी कट्टरपंथियों के उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं कर पाते। दरअसल, ईरान में कट्टरपंथी सिद्धांतवादी उग्र इस्लामी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की निर्णायक भूमिका रहती है। बेहद ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके इशारों पर ही चलती है, जिसके चलते कट्टरपंथियों ने सुनियोजित तरीके से सुधारवादियों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सुधारवादी चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। वर्ष 2009 के विरोधों का आईआरसीजी और इसकी मिलिशिया इकाई बासीज ने बेरहमी से दमन किया था। फिर ईरान में पश्चिम का विरोध, पूरबी देशों का समर्थन, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और फिर महिलाओं पर प्रतिबंधों का दौर सामने आया। महसा अमिनी की संदिग्ध मौत के बाद यह उग्र विरोध पूरे ईरान में देखा गया। मानवाधिकार संगठन अनेक किशोरों समेत पांच सौ लोगों के इस दमन में मरने के आरोप लगाते रहे हैं।

पांच दशक से कट्टरपंथियों की गिरफ्त में रहने वाले ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन की जीत ने नई इबारत लिखी है। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका व इजराइल के निशाने पर रहने वाला ईरान पहले ही कड़े प्रतिबंधों के चलते आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में कट्टरपंथी सईद जलील को हराने वाले वाले मसूद पेजेशकियन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे कट्टरपंथियों की खिलाफत करके पूर्व के बजाय पश्चिम से बेहतर रिश्ते बना पाएंगे? इस चुनाव में मसूद ने हिजाब कानून की सख्ती खत्म करने का वादा मतदाताओं से किया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में युवाओं के वोट उन्हें मिले। उल्लेखनीय है कि हिजाब विरोधी महसा अमिनी की हिजाब का विरोध करने पर जेल में हुई संदिग्ध मौत के बाद देश में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों के मरने की खबर थी।

बहरहाल, पेशे से सर्जन रहे पेजेशकियन वर्ष 1997 की उदारवादी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वे राष्ट्रपति हसन रूहानी के समर्थक थे। वर्ष 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिये पश्चिमी देशों से हुई परमाणु संधि के वे सूत्रधार भी रहे हैं। दरअसल, पेशे से चिकित्सक मसूद पेजेशकियन, वर्ष 1994 में एक सड़क दुर्घटना में पत्नी व बेटी की मौत के तीन साल बाद राजनीति में आए। उन्होंने पारिवारिक दबाव के बावजूद दूसरी शादी नहीं की और बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी।

एक उदारवादी नेता के रूप में पहचान बनाने वाले नेता मसूद पेजेशकियन ने ईरान के लोगों से कहा कि ह्यमैं आपको अकेला नहीं छोडूंगा, आप भी मुझे अकेला न छोड़ना।ह्व यही वजह है कि दूसरे चरण में उन्हें पर्याप्त मत मिले और ईरान के हर शहर में उनकी जीत का जश्न मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद ईरान में नये सिरे से चुनाव हुए। बहरहाल, मसूद की जीत को ईरान में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

बहरहाल, मसूद पेजेशकियन ऐसे समय में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं जब इजरायल व हमास के बीच जारी युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। ईरान के लिए यह इसलिए मुश्किल का समय है क्योंकि हमास के सिर पर ईरान का हाथ रहा है। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला और वैश्विक समुद्री व्यापार के लिये खतरा बने यमन के हूती लड़ाकों को ईरानी समर्थन के आरोप पश्चिमी देश लगाते रहे हैं। वहीं पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते ईरान बड़ा आर्थिक संकट भी झेल रहा है। हालांकि मसूद पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध बनाने के पक्षधर हैं और पूर्वी देशों रूस व चीन से सुरक्षित रिश्तों की वकालत करते हैं।

उल्लेखनीय है कि ईरान में वर्ष 1997 से लेकर 2005 तक सुधार वादियों की हुकूमत रही है। अब तक यह होता रहा है कि कोई सुधारवादी यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकन दर्ज कराता तो कट्टरपंथियों के वर्चस्व वाली हाई प्रोफाइल गार्डियन काउंसिल उसे खारिज कर देती। इससे सुधारवादी कट्टरपंथियों के उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं कर पाते। दरअसल, ईरान में कट्टरपंथी सिद्धांतवादी उग्र इस्लामी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की निर्णायक भूमिका रहती है। बेहद ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके इशारों पर ही चलती है, जिसके चलते कट्टरपंथियों ने सुनियोजित तरीके से सुधारवादियों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सुधारवादी चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। वर्ष 2009 के विरोधों का आईआरसीजी और इसकी मिलिशिया इकाई बासीज ने बेरहमी से दमन किया था। फिर ईरान में पश्चिम का विरोध, पूरबी देशों का समर्थन, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और फिर महिलाओं पर प्रतिबंधों का दौर सामने आया। महसा अमिनी की संदिग्ध मौत के बाद यह उग्र विरोध पूरे ईरान में देखा गया। मानवाधिकार संगठन अनेक किशोरों समेत पांच सौ लोगों के इस दमन में मरने के आरोप लगाते रहे हैं। फिर इंटरनेट पर सेंसरशिप, सामूहिक गिरफ्तारी, मुकदमे व फांसी का दौर ईरान ने देखा, जिससे ईरान के युवाओं में आक्रोश की लहर देखी गई।

बहरहाल, देश में जारी घुटन के बीच सुधारवादी पूर्व राष्ट्रपति मो. खातमी ने चुनावों को लेकर रणनीति बदलने का निर्णय किया और सक्रिय होकर मसूद पेजेशकियन के समर्थन में प्रचार किया। हालांकि, पहले दौर में चुनाव बहिष्कार के चलते सिर्फ चालीस फीसदी मतदान में राष्टपति पद के किसी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिल पाया था। अंततः दूसरे चरण में मसूद पेजेशकियन राष्ट्रपति चुन लिए गये। अब उन्होंने पश्चिम से बेहतर संबंध बनाकर ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने का विचार बनाया है। साथ ही सुधारवादी नेताओं का नेटवर्क बनाकर आगे की रणनीति बनानी शुरू की है। इसमें सुधारवादी नेता जवाद जरीफ भी शामिल हैं। जरीफ अकादमिक जगत में सक्रिय रहे हैं। मसूद पेजेशकियान ने अपने घोषणापत्र में घोषणा की थी कि उनकी विदेश नीति पश्चिम व पूरब से सामंजस्य बनाकर चलने वाली होगी, जिससे देश का आर्थिक संकट खत्म किया जा सके। मकसद यही है कि पश्चिमी देशों से परमाणु मुद्दे पर एक सकारात्मक समझौते तक पहुंचना ताकि आर्थिक प्रतिबंधों को कम किया जा सके। हालांकि, कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ईरान के राजनीतिक तंत्र के पास वह ताकत नहीं कि विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन किया जा सके, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की भूमिका होती है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

संपादकीय

मोदी का सफल रूस दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सफल रूस यात्रा की अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच आजमाई हुई दोस्ती को और मजबूत किया है। साथ ही भारत ने यह भी जता दिया है कि वह किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करता तथा उसे संतुलन बनाना आता है। इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके देश के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से नवाजा तथा अपने व्यक्तिगत अतिथि का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री मोदी रूस में 26 घंटे रहे। पुतिन की मेहमाननबाजी ने उन चर्चाओं को भी खारिज कर दिया है, जिसमें यह माना जा रहा था कि रूस और भारत के बीच दोस्ती में अब पहले जैसी गरमाहट नहीं रह गई है। मोदी ने पुतिन के साथ चार औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंग कीं। अब सवाल यह है कि इस यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ? इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मोदी की यात्रा के दौरान उन भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है, जिन्हें नौकरी देने के बहाने रूसी सेना के साथ यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया था। इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन एक बात मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में साफ-साफ कही कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, 'आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए आपके आभारी हैं।' पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि मोदी की बातों का पुतिन पर कितना असर होगा और मोदी की यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में वास्तव में क्या भूमिका होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए भी थीं, क्योंकि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को ही चुना। साथ ही ढाई साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी का यह पहला रूस दौरा था। इस यात्रा पर वैश्विक मीडिया में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी की रूस यात्रा से वैश्विक मंच पर रूस को अलग-थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिशें कमजोर हुई हैं। इससे भारत के प्रति यूक्रेन की नाराजगी बढ़ी है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। बीबीसी हिंदी ने लिखा कि मोदी के ताजा रूस दौरे से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोदी की मौजूदगी पुतिन के लिए फायदे का सौदा हो सकती है? वॉयस ऑफ अमेरिका ने लिखा है कि मोदी इस यात्रा के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत-रूस संबंध महत्वपूर्ण हैं और रूस-चीन की बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खास बात यह है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यह बैठक तब हुई, जब वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा चीन, रूस-भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज दिखाई देते हैं।

भारत एक महाशक्ति क्यों बनेगा?

यह राष्ट्र दुनिया के भविष्य को संवारने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसकी आंतरिक चुनौतियां विकट हैं

मार्टिन वुल्फ

मेरा यह अटूट विश्वास है कि 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमारा देश 'विकसित भारत' होगा।÷ कुछ इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देशवासियों को संबोधित किया था। क्या उनकी इस आकांक्षा का पूरा होना संभव है? हां। क्या यह यथार्थवादी है? नहीं, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि भारत उस समय तक एक महाशक्ति बन जाएगा, जिसकी अर्थव्यवस्था एक पैमाने पर अमेरिका जितनी बड़ी होगी। तो, भारत उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? दुनिया के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं?

मैंने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी में दिए गए व्याख्यानों में भारत के आर्थिक भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किए थे। मैंने भारत की तुलना आईएमएफ द्वारा ÷विकसित÷ देशों की श्रेणी में शामिल किए गए सबसे गरीब देश, ग्रीस से करके एक उच्च आय वाला देश बनने की चुनौती का उदाहरण दिया था। वर्ष 2023 में, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) पर भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रीस की प्रति व्यक्ति जीडीपी के एक चौथाई से थोड़ा कम था। यदि ग्रीक की प्रति व्यक्ति जीडीपी मात्र 0.6 प्रतिशत (यह आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुसार 1990-2029 का रुझान है) और भारत की 4.8 प्रतिशत (इसका 1990-2029 का रुझान) की दर से बढ़ती है, तो 2047 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रीस की केवल 60 प्रतिशत ही होगी। यदि 2047 तक इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को ग्रीस की जीडीपी के बराबर आना है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष करना होगा। विकास की वह दर 1990 से 2012 के दौरान चीन के विकास दर की तुलना में बहुत कम नहीं होगी, जब उसने 9 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वार्षिक विकास दर हासिल की थी।

भारत वर्ष 2047 तक आखिरकार कैसे एक 'विकसित' देश बन सकता है : संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 1.67 अरब हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी 1.32 अरब और अमेरिका की आबादी 380 मिलियन होगी। अपनी आबादी के चार गुना से भी अधिक होने के कारण भारत के लिए अमेरिका में होने वाले कुल आर्थिक उत्पादन की बराबरी करना कठिन नहीं होगा। वास्तव में यदि भारत की जीडीपी वर्ष 2047 तक केवल 5 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ती है (जो कि 1990-2029 में 6.3 प्रतिशत की इसकी सालाना रुझान दर से काफी कम है), और अमेरिकी जीडीपी 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ती है (जो कि समान आधार पर 1990-2029 में इसकी रुझान दर है), तो भारत की अर्थव्यवस्था (पीपीपी पर) काफी बढ़कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएगी।

हालांकि, अमेरिका तब भी तकनीकी रूप से कहीं अधिक विकसित होगा और उसकी उत्पादकता भी कहीं अधिक होगी। भारत की विनिर्माण क्षमता भी संभवतः कभी भी चीन की बराबरी नहीं कर पाएगी- जीडीपी में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी न केवल चीन से बहुत कम है, बल्कि यह पहले से ही घटती जा रही है। फिर भी विशाल

आकार काफी मायने रखता है- अपनी विशाल आबादी और विशाल अर्थव्यवस्था की बदौलत भारत एक महाशक्ति होगा, जो वैसे तो चीन या अमेरिका से हर लिहाज से बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन निःसंदेह भारत एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा।

पीपीपी पर भारत की जीडीपी वर्ष 2050 तक अमेरिकी जीडीपी की बराबरी कर सकती है: इसे सुनिश्चित करने में आखिरकार कौन बाधक हो सकता है? इसका एक कारण वैश्विक आर्थिक विकास में छाई सुस्?ती हो सकती है, जिसका उल्लेख आईएमएफ के अप्रैल 2024 के विश्व आर्थिक आउटलुक में किया गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के संभावित पुनर्निर्वाचन के कारण संरक्षणवाद के काफी बढ़ जाने से ही यह संरचनात्मक सुस्?ती काफी हद तक बढ़ सकती है और इसका प्रतिकूल प्रभाव भी बेहद ज?यादा हो सकता है (चीन में आर्थिक सुस्?ती के साथ-साथ वहां की आबादी के स्?वरूप में प्रतिकूल बदलाव भी पहले से ही नजर आ रहा है)। आने वाले वर्षों में जलवायु संकट आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, और इसके साथ ही व्यापक रूप से मानव कल्याण भी प्रभावित हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह तर्क दिया था। इसके अलावा महाशक्तियों के बीच युद्ध भी कल्पना से कोसों दूर नहीं है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों को आशा है कि आर्टिफि?शियल इंटेलिजेंस आर्थिक विकास को नए सिरे से काफी तेज गति प्रदान करेगा। हालांकि, इस पर संशय है।

भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि अब चीन से आगे निकल गई है: एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीयों को अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक उत्पादन से कम से कम दोगुनी गति से बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि यदि व्यापार अनुपात में गिरावट की स्थिति नहीं आने देनी है, तो इसके निर्यात को भी वैश्विक उत्पादन से कम से कम दोगुनी गति से बढ़ना होगा- अन्यथा, अर्थव्यवस्था और भी अधिक बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी।

सौमित्र चटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यन ने हाल ही में एक शोधपत्र में व्यापार के प्रति किसी भी नए तरीके की विमुखता के खिलाफ तर्क दिया है। वे इस व्यापक धारणा का उल्लेख करते हैं कि ÷भारत एक बड़ा देश है, जिसका बाजार बड़ा है।÷ लेकिन व्यापक स्तर की गरीबी को देखते हुए, व्यापार योग्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए वास्तविक बाजार का आकार सकल घरेलू उत्पाद के 15 से 45 प्रतिशत के बीच है।

भारत चीन की तुलना में बहुत कम औद्योगीकृत रहा है: कुछ लोग, पुनः तर्क देते हैं कि ÷निर्यात, भारतीय विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा है।÷ लेकिन निर्यात वास्तव में महत्वपूर्ण रहा है, केवल इसलिए नहीं कि वे आवश्यक आयातों के लिए भुगतान करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं और वैश्विक जानकारी तक पहुंच की सुविधा देते हैं। अंत में, लोग तर्क पेश करते हैं कि ÷वैश्विक अवसर गायब हो रहे हैं।÷ लेकिन व्यापारिक निर्यात (अंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को छोड़कर) में भारत का हिस्सा 2022 में मात्र 2.2 प्रतिशत था, जबकि चीन का 17.6 प्रतिशत था। यहां तक कि वाणिज्यिक सेवाओं का भारतीय निर्यात भी विश्व के कुल निर्यात का केवल 4.4 प्रतिशत था, जो अमेरिका के 12.8 प्रतिशत और चीन के 6 प्रतिशत हिस्से से बहुत कम है।

विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है : इसके अलावा, एक बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत के पास शक्तियां हैं। यह ÷चीन प्लस वन÷ की दुनिया में एक स्वाभाविक ÷प्लस वन÷ है। भारत के पश्चिम के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसके लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण भी है कि बाकियों के लिए यह मायने रखता है। यह उस स्थिति में तो हो ही सकता है, जिसे आईएमएफ विश्व अर्थव्यवस्था में ÷कनेक्टर देश÷ कहता है। वास्तव में, यह घरेलू और वैश्विक स्तर पर व्यापार के उदारीकरण का नेतृत्व कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। भारत को अपने प्रवासी समुदायों का भी लाभ हासिल है, जो विशेष रूप से अमेरिका में अत्यधिक प्रभावशाली हैं। यही नहीं, भारत के मानव संसाधन इसे समय के साथ अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और उन्नत करने की क्षमता प्रदान करते हैं। उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। संक्षेप में, किसी देश का आकार उसके महत्व को बढ़ाता है। दुनिया भारत को सीमित नहीं कर सकती है, बल्कि यह उसके भविष्य को आकार दे सकती है और उसे ऐसा करना ही चाहिए।

यदि भारत तेज गति से विकास चाहता है तो उसे सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले व्यापार का अनुपात ऊंचा रखना होगा : हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भारत खुद को कैसे प्रबंधित करता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां आंतरिक हैं- स्थिरता बनाए रखना, शिक्षा में सुधार, कानून के शासन को बनाए रखना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, निवेश के लिए सबसे बेहतर वातावरण प्रदान करना, आंतरिक निवेश को प्रोत्साहित करना, और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अपने बदलाव की गति को तेज करना।

हाल के चुनावों ने मुझे और अधिक आशावादी बना दिया है। देश में स्थिर सरकार बनी रहनी चाहिए। लेकिन मोदी की बीजेपी के रुख में बदलाव आया है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार को भारत की अपने सांस्कृतिक संघर्षों के बजाय अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के कल्याण की दिशा में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी करेगा। भारत दुनिया में एक प्रभावशाली और बेहद महत्वपूर्ण स्थिरीकरण शक्ति हो सकता है। हम सभी को आशा करनी चाहिए कि यह समय की जरूरतों के अनुरूप काम करेगा।

***

अध्यात्म

अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र है

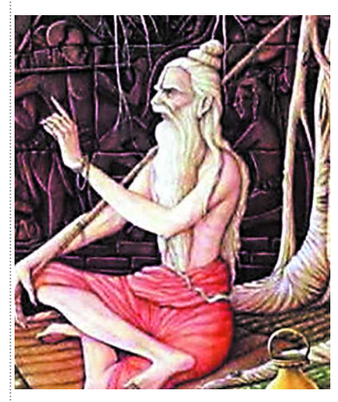

एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे धर्मराज उनके कर्मों का लेखा-जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा- मैं अपना निर्णय तो सुनाउंगा लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूं, कह सकते हो। डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे उसे इसका पछतावा भी हो रहा था अतः, अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराज- मैंने जीवन भर पापकर्म किए जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे आप जो दंड दें, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला महाराज- मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला सदैव सत्कर्म ही किए इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख-साधनों का शीघ्र प्रबंध करें।धर्मराज ने दोनों की बात सुनी फिर डाकू से कहा- तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा- महाराज! इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ वह क्षुब्ध होकर बोले- निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मर कर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, और तप को पूर्ण करो। उसी तपस्या में फल है, जो अहंकार रहित होकर की जाए अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र है और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार बनता है झूठे दिखावे तप नहीं हैं, ऐसे लोगों की गति वही होगी जो साधु की हुई।

हाथरस जैसे हादसों में महिलाएं ही शिकार क्यों?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संभाग के अंतर्गत हाथरस ज़िले के सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलराई गांव में 2 जुलाई को भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक कथित बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मृतक श्रद्धालुओं की संख्या 121 से पार हो चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 121 मृतकों में केवल महिलाओं की संख्या 112 बताई जा रही है जबकि शेष 9 मृतकों में सात बच्चे और दो पुरुष थे। वहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने निश्चित रूप से उस कहावत को बलवती कर दिया है कि औरत का पीर कभी भूखा नहीं मरता।

निर्मल रानी

आज हमारे देश में बाबाओं की बाढ़ सी आई हुई है। सोशल मीडिया के इस युग में अनेक बहुरूपिये क़िस्म के स्वयंभू बाबा प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हुये हैं। ऐसे कई स्वयंभू बाबा कैमरे के सामने कई बार अपनी मूर्खता व अज्ञान का प्रदर्शन करते भी देखे जा चुके हैं। परन्तु इसके बावजूद वहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और इस भीड़ में सबसे अधिक संख्या निश्चित रूप से महिलाओं की होती है। और कहना ग़लत नहीं होगा कि इनमें अधिकांशतः अनपढ़,अज्ञानी व अशिक्षित महिलायें ही अधिक होती हैं। और पुरूषों में ज़्यादातर पुरुष भी वही होते हैं जो अपने घर परिवार की महिलाओं के आग्रह पर उनके साथ आते हैं।

आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब कोई बाबा या प्रवचनकर्ता किसी नये स्थान पर जाकर सत्संग आयोजित करता है तो उस बाबा के पहुँचने से पहले उसकी मार्केटिंग टीम के सदस्य वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सबसे पहले अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं से संपर्क करते हैं। और आयोजन से पहले उन्हीं महिलाओं को सजधज कर आने के लिये कहा जाता है। फिर यही महिलायें श्रद्धापूर्वक अपने सर पर कलश रखकर नगर भ्रमण करती हैं। प्रायः कलश भी महिलायें अपना ही लेकर आती हैं। महिलाओं की इस कलश यात्रा के दो पहलू हैं। भोली भाली धर्मभीरु महिलायें तेज़ धूप, सर्दी व बारिश की परवाह किये बिना पुण्यार्थ के फेर में सिर पर क्लश रखकर एक ही शारीरिक स्थिति में घंटों तक उस कलश यात्रा का हिस्सा बनी रहती हैं। तो दूसरी तरफ़ चैन से कहीं ए सी में बैठे बाबा जी के प्रवचन व उनकी नगर उपस्थिति का मुफ़्त में प्रचार हो जाता है। अब यदि कलश यात्रा के दौरान किसी महिला का स्वास्थ्य बिगड़ जाये या कोई हादसा हो जाये तो इसका ज़िम्मेदार कौन है कुछ नहीं पता।

हाथरस भगदड़ निश्चित रूप से देश की भगदड़ की कोई पहली घटना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भगदड़ केवल भारत में ही मचती हो। दुनिया के कई देशों में भगदड़ व जान-माल के नुकसान होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 30 अक्टूबर 2022 की रात में दक्षिण कोरियाई राजधानी सियोल में हैलोवीन समारोह के दौरान भगदड़ मची भगदड़ में 151 लोगों की मौत हुई थी। अप्रैल 1989 में ब्रिटेन में शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच इंग्लिश एफ़ ए कप सेमीफ़ाइनल मैच के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 96 लोग मारे गए थे। जुलाई 1990 में सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान मक्का के पास अल-मुआइसिम सुरंग के अंदर, ईद-उल-अज़हा के दौरान भगदड़ में 1,426 हाजी कुचलकर मर गए।सऊदी अरब में ही मई 1994 में भी हज के दौरान दमरात ब्रिज के पास भगदड़ में 270 लोगों की मौत हो गई। फ़रवरी 2004 में भी ज़मारात पुल के पास हुई भगदड़ में 251 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इसी तरह अप्रैल 1998 में भी सऊदी अरब में भगदड़ की घटना में 191 हाजियों की कुचलकर मौत हो गई थी। मई 2001 में अफ़्रीक़ा में अकरा के मुख्य फुटबॉल स्टेडियम में मची भगदड़ में कम से कम 126 लोग मारे गए थे इसी तरह अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया के एक फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ में कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई थी।

इसी तरह हमारे दश में भी भगदड़ की अनेक घटनाएं घटी हैं परन्तु इनमें सर्वाधिक घटनायें केवल मंदिर या धर्म अथवा धार्मिक स्थलों से जुड़े आयोजनों की ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के मंधारदेवी मंदिर में 2005 में हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत हो गयी थी। इसी तरह 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में भी एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मच गयी थी जिसमें 162 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में सिंहस्थ कुंभ मेले में 27 अगस्त 2003 को पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए थे । 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी । भक्तों में उस समय कृपालु महाराज द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने की होड़ मच गयी थी। देश में ऐसी और भी अनेकानेक घटनाएं धार्मिक आयोजनों व धर्मस्थानों पर होती रही हैं।

ऐसे हर हादसे के बाद एक सवाल हर तरफ़ उठने लगता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकार,प्रशासन, प्रवचनकर्ता (बाबा) आयोजनकर्ता या फिर ख़ुद जनता और जनता में भी ख़ासकर महिलायें? ऐसे हादसों के बाद प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि प्रशासन पर्याप्त प्रबंध नहीं करता। प्रायः आशा से अधिक लोग आते हैं जिससे लोगों के बैठने निकलने आने जाने में दिक्क़त होती है। ना ही मौक़े पर एंबुलेंस रहती है, ना ही फ़ायर ब्रिगेड की टीम ना ही भीड़ के अनुसार पर्याप्त सुरक्षाकर्मी। अब यदि कोई अफ़वाह फैल जाये,कोई अनहोनी हो जाये और भगदड़ मचे तो उसे कौन और कैसे नियंत्रित करेगा? हाथरस हादसे में 121 मृतकों में केवल महिलाओं की संख्या 112 आने के बाद एक अलग ही बहस छिड़ गयी है। लोगों में आम चर्चा है कि यहाँ भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि 'महिलाएं ढोंगी बाबाओं से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। इस हादसे के बाद हाथरस ज़िले के अनेक गांवों में महिलाओं के प्रति घृणा की लहर पैदा हो गई है।

पुरुष महिलाओं पर बाबा का अनुयायी होने का आरोप लगा रहे हैं और इस तरह की राय व्यक्त कर रहे हैं कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए। इलाक़े के तमाम लोग यह कहते सुने गये कि अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सत्संग में नहीं जातीं तो यह घटना नहीं होती। महिलायें ही बाबा के चरणों की धुल (रज) लेने के लिये अनियंत्रित हो गयीं जिससे भगदड़ मच गयी। लोगों का यह भी कहना था कि 'महिलाएं हमेशा आस्था में डूबी रहती हैं और चूँकि वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं इसलिये आसानी से किसी के भी झांसे में आ जाती हैं।आश्चर्य तो यह भी है कि दर्जनों ढोंगी बाबाओं के कुकर्मों का भंडाफोड़ होने के बाद तथा कई स्वयंभू अय्याश व्यभिचारी बाबाओं के जेल में सड़ने के बावजूद महिलाओं का इनसे मोह भांग होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे हादसों का एक पहलू यह भी है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

आपका दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आपको आय के नए-नए स्रोत मिलेंगे।

वृषभ

आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी।

मिथुन

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आप जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो आपको उसमें कोई भारी नुकसान हो सकता है।

कर्क

आज का दिन साझेदारी में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा।

सिंह

आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। करियर में भी आज आपको अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है।

कन्या

आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपने यदि किसी से कुछ पुराना कर्ज लिया था, तो उसे भी आप आसानी से उतार पाएंगे।

तुला

आज का दिन आपके लिए किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको किसी धन संबंधित मामलों मे सावधान रहकर काम करना होगा।

वृश्चिक

आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में आपकी खुशियां बढ़ेंगी और दोनों के बीच प्रेम गहरा होगा।

धनु

कुछ मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती है। नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग के लोगों को सावधान रहना होगा।

मकर

आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें, नहीं तो उनमें आपको कोई समस्या खड़ी हो सकती है। आप जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं।

कुंभ

आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को लाभ मिलेगा। किसी अनजान व्यक्ति से लेनदेन करने से बचें।

मीन

आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

सुभाषित *यदि तुम सूरजकी तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरजकी तरह जलना सीखो।*
❑ **चाणक्य नीति**

अग्निवीरोंको आरक्षण

अग्निवीरोंको लेकर पिछले कुछ महीनोंसे जारी बहसके बीच स्वराष्ट्र मंत्रालयने गुरुवारको एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो अग्निवीरोंके भविष्यके हितमें है। अग्निवीरोंका प्रकरण देशकी सुरक्षा व्यवस्थासे जुड़ा है और इसको लेकर अनेक भ्रांतियोंको फैलाया जा रहा है। इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनानेकी कोशिशें भी जारी है। अग्निवीर योजनाको पूरी तरहसे खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके गुण-दोषपर चर्चा की जा सकती है जिससे कि भविष्यमें उसका निराकरण किया जा सके। संशोधन और परिमार्जनके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इसी क्रममें स्वराष्ट्र मंत्रालयने अर्धसैनिक बलों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में जवानोंके दस प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरोंके लिए आरक्षित करनेकी घोषणा की है। सीआईएसएफकी महानिदेशक नीना सिंहका कहना है अग्निवीरोंके बारेमें स्वराष्ट्र मंत्रालयका यह फैसला अहम है। पूर्व अग्निवीरोंको शारीरिक जांचके दौरान आयु सीमामें छूटके अतिरिक्त अन्य रियायतें भी मिलेंगी। भर्तीके पहले सालमें आयु छूट पांच-पांच वर्ष होगी, जबकि बादके वर्षोंमें यह तीन वर्ष होगी। इसका एक बड़ा लाभ यह भी है कि सीआईएसएफको भी पहलेकी तुलनामें प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिलेंगे। ऐसी स्थितिमें अग्निवीरोंके बारेमें नकारात्मक चर्चाओंका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार सीआरपीएफके महानिदेशक अनीस दयाल सिंहने भी कहा है कि अग्निवीरोंको शामिल करनेकी सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। भर्तीके नियमोंमें आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं। इन्हें आयु सीमाके पांच और तीन वर्षकी छूट दी जायगी। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक नितिन अग्रवालने भी आश्वस्त किया है कि कम अवधिके प्रशिक्षणके बाद हम इन्हें सीमाओंपर तैनान करेंगे। अग्निवीर योजनाके बारेमें संसदमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी बयान दे चुके हैं और उन्होंने भ्रांतियोंको दूर करनेका भी प्रयास किया है। वस्तुत: देशमें पहली बार अग्निवीर योजना दो वर्ष पूर्व २०२२ में शुरू करनेकी घोषणा की गयी थी। इसके तहत तीनों सेनाओंमें युवाओंको भर्ती करनेकी योजना है। भर्तीकी उम्र १७ वर्षसे २१ वर्ष निर्धारित की गयी है। भर्ती मात्र चार वर्षोंकी अवधिके लिए होगी। ऐसे जवानोंको अग्निवीर कहा जायगा और इनमेंसे २५ प्रतिशतको अगले १५ वर्षोंके लिए सेनामें शामिल किया जायगा। शेष ७५ प्रतिशतको एक मुश्त राशि देकर बाहर किया जायगा और यह राशि लगभग २२ लाख रुपये होगी जिससे पूर्व अग्निवीर किसी भी रोजगार या कार्यके लिए पूंजीके रूपमें इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए अग्निवीर योजनाके तहत भर्ती होना एक अच्छा और सुरक्षित अवसर है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है।

खुदकुशीमें वृद्धि चिन्तनीय

देशमें खुदकुशीके बढ़ते मामले गम्भीर चिन्ताका विषय है। इससे भी बड़ी चिन्ताकी बात तो यह है नाबालिग बच्चोंमें आत्महत्याकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो देशके भावी कर्णधार हैं। दिल्ली पुलिसके आंकड़ोंपर गौर करें तो यह चौंकानेवाला है। इसके अनुसार साल २०१४ से २०१८ के बीच १८ वर्षसे कम उम्रके बच्चोंकी आत्महत्याके १४० मामले दर्ज किये गये हैं, जो सामाजिक विघटन और तेजीसे फैलती सामाजिक विकृतियोंका संकेत है। सर्वोच्च न्यायालयने खुदकुशीके बढ़ते मामलेको सामाजिक मुद्दा बताते हुए केन्द्र सरकारसे जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रकी पीठने एक जनहित याचिकापर गुरुवार केन्द्रसे चार सप्ताहमें विस्तृत जवाब दाखिल करनेको कहा है जिसमें कहा गया है कि खुदकुशीके मामलोंकी बढ़ती संख्यासे निबटनेके लिए प्रभावी कदमोंकी जरूरत है। इस सम्बन्धमें शीर्ष न्यायालयने जनहित याचिकापर दो अगस्त २०१९ को केन्द्र और सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशोंको नोटिस जारी किया था। खुदकुशीकी सोचवाले व्यक्तियोंको काल सेण्टर एवं हेल्पलाइनके माध्यमसे मदद और परामर्श उपलब्ध करानेकी परियोजना शुरू करनेके लिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंको निर्देश देनेकी याचिकाकर्ताकी मांग उचित और खुदकुशीके मामलोंको कम करनेकी दिशामें प्रभावी प्रयास है। आम तौरपर खुदकुशी अवसादग्रस्त व्यक्ति अथवा ऐसी समस्यामें उलझा व्यक्ति ही करता है जिसके सामने मृत्युके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है लेकिन नाबालिगोंका खुदकुशी करना हैरान करनेवाली है। इसके कारणोंपर गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। इसके लिए समाज पूरी तरह जिम्मेदार है, वह चाहे परिवार हो, शिक्षा संस्थान हो अथवा परिवेश हो। इसमें व्यापक सुधारकी गुंजाइश है, जरूरत है इसपर ध्यान केन्द्रित करनेकी तभी बच्चोंको इस तरहके कड़े कदम उठानेसे रोका जा सकता है।

लोक संवाद

मणिपुरके हालात

महोदय,-नरेंद्र मोदीके नेतृत्ववाली सरकारके पिछले दशकके शासनकी एक उल्लेखनीय विशेषता राजनीतिक विरोधियों और मीडिया द्वारा किसी भी सवालका तिरस्कार करना और बिना कोई औचित्य पेश किये कुछ निश्चित रुख अपनाना था।ऐसा ही एक मुद्दा उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुरसे जुड़ा है। यह छोटा राज्य एक सालसे अधिक समयसे जल रहा है, जिसमें २०० से अधिक लोगोंकी जान चली गयी और हजारों लोग घायल हो गये, लेकिन केन्द्रने इसपर बहुत कम ध्यान दिया है। एन. बीरेन सिंहके नेतृत्ववाली भाजपा सरकारको बर्खास्त करनेकी बजाय, जिसका पूर्वाग्रह स्पष्टसे अधिक रहा है, विपक्षी दलों, विशेषज्ञों और मीडियाके बार-बार कहनेके बावजूद केन्द्र सरकार राज्यमें विस्फोटक स्थितिकी उपेक्षा कर रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने कई पड़ोसी राज्योंका दौरा किया लेकिन मणिपुरसे दूर रहे।उन्होंने संसदके भीतर और बाहर राज्यके घटनाक्रमपर पूरी तरह चुप्पी बनाये रखी। हालके लोकसभा चुनावोंके बाद संसदमें अपने पहले भाषणके दौरान उन्होंने राज्यकी स्थितिका पहला उल्लेख किया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है और उन्हें राज्यके दौरके साथ-साथ स्थितिको नियंत्रित करनेमें पूरी तरहसे विफलताके लिए मणिपुरमें भाजपा सरकारको बर्खास्त करनेकी घोषणा करनी चाहिए थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैतेई और कुकी-नागा आदिवासियोंके बीच प्रतिद्वंद्विता और तनावका एक लंबा इतिहास रहा है। मणिपुरमें दो प्रमुख समुदायोंके सदस्योंके बीच झड़पें हुई हैं लेकिन मौजूदा संकटका कोई सानी नहीं है। राज्य सरकारको मैतेइयोंको आदिवासी दर्जा प्रदान करनेके लिए उच्च न्यायालयके निर्देशके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। आदिवासियोंको डर था कि यदि मैतेइयोंको भी अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया तो उनके लिए आरक्षण कम हो जायगा। राज्यके अधिकांश हिस्से समय-समयपर कर्फ्यूमें रहते हैं और इंटरनैट सुविधाएं लम्बे समयतक बंद रहती हैं। दोनों समुदायोंके हजारों निवासी राहत शिविरोंमें रह रहे हैं और अपने घर वापस जानेमें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। नागा बहुल इलाकोंमें राज्यको जोड़नेवाले मुख्य राजमार्गपर आर्थिक नाकेबंदीके कारण खाद्यान्न और पैट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओंकी आपूर्ति गम्भीर रूपसे बाधित हो गयी है। मुख्य मंत्री, जो बहुसंख्यक मैतेई समुदायसे हैं, जो कुकी-नागा आदिवासियोंके साथ हिंसक झड़पोंमें शामिल है, अल्पसंख्यक समुदायके बीच विश्वास पैदा नहीं करते हैं। आदर्श रूपसे उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था और किसी तटस्थ और सभी वर्गों द्वारा सम्मानित माने जानेवाले व्यक्तिको उनकी जगह लेनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति निश्चित रूपसे कानून और व्यवस्थाको बहाल करनेके लिए एक मजबूत राज्यपालकी नियुक्तिके साथ केन्द्रीय शासन लागू करना उचित होगा। मोदी सरकार, जो गैर-भाजपा दलोंके नेतृत्ववाली राज्य सरकारोंके खिलाफ आक्रामक रही है, मणिपुरमें अपनी ही अक्षम सरकारके साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर रही है। इन दावोंमें कुछ सचाई हो सकती है कि म्यांमार और चीन समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन हिंसा रोकनेमें राज्यकी ओरसे पूरी विफलताके लिए यह कोई बहाना नहीं है। राज्यके प्रभावित निवासियोंको अधिक आश्वस्त महसूस होगा यदि प्रधान मंत्री स्वयं उनसे मिलने जायं और बीरेन सिंह सरकारको बर्खास्त करनेका आदेश दें। राज्यपालको क्षेत्रके विशेषज्ञोंके सहयोगसे मणिपुरमें मौजूदा गतिरोधसे बाहर निकलनेका रास्ता खोजनेकी कोशिश करनी चाहिए। **-विपिन पब्बी, वाया ईमेल।**

अफगानी महिलाओंकी दुर्दशा

इस समय अफगान सिविल सेवामें बची-खुची महिलाएं ही हैं। उनका मासिक वेतन मात्र पांच हजार रुपये है। भारतीय मुद्रामें समायोजित करें तो यह केवल पांच हजार ८८३ रुपये बनेगा। इतनेमें महिला सिविल सेवा कर्मीको अपना घर-परिवार चलाना है। भारतमें कामवाली बाई भी इससे कहीं ज्यादा कमा लेती है।

❑ **पुष्परंजन**

अफगानिस्तानमें औरतोंका जो हाल इस्लामिक अमीरातने किया है, उसपर चिंताजनक रिपोर्ट आयी है। संयुक्त राष्ट्रकी रिपोर्टमें कहा गया है कि अगस्त, २०२१ में सदाचारका प्रचार और बुराईकी रोकथामके लिए मंत्रालय (एमपीवीपीवी) की स्थापनाके बादसे तालिबानने डरका माहौल पैदा किया है। इस रिपोर्टमें मोरल पुलिसके तौर-तरीकोंपर भी सवाल किया गया है। आप वेस्टर्न हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। एमपीवीपीवीने एक रूढ़ीवादी ड्रेस कोड भी लागू किया है, जो इस्लामी पोशाकको एक दैवीय दायित्वके रूपमें संदर्भित करते हैं। तालिबान सरकारने महिलाओंके लिए पुरुष एस्कॉर्ट अनिवार्य करनेके फैसलेका बचाव करते हुए कहा कि वे उनके सम्मान और शुद्धताकी रक्षाके लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) की रिपोर्ट १५ अगस्त, २०२१ से ३१ मार्च, २०२४ तक अमीरातमें मानवाधिकारकी स्थिति और मंत्रालयकी कारगुजारियोंपर केंद्रित है। तालिबान सरकारके प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिदने मंगलवार देर रात कहा कि यूएनएएमए रिपोर्ट, अफगानिस्तानको पश्चिमी नजरियेसे आंकनेकी कोशिश कर रही है, जबकि यह एक इस्लामी समाज है। पुरुषों और महिलाओंके साथ शरिया कानूनके अनुसार व्यवहार किया जाता है, यहां कोई उत्पीड़न नहीं होता है।

यूएनएएमएने १५ अगस्त, २०२१ से ३१ मार्च, २०२४ के बीच १०३३ लोगोंका दस्तावेजीकरण किया, जिसमें ८२८ महिलाएं एवं २०५ पुरुष शामिल थे। इनका जोर-जबरदस्तीका दस्तावेजीकरण किया, जहां अमीरातकी मोरल पुलिस और एमपीवीपीवीने निर्देशोंके कार्यान्वयनके दौरान बल प्रयोग किया। अफसोस अफगानिस्तानका जो अकादमिक क्लास है, वह भयसे अमीरातके पक्षमें भी बयान देता है। इनमें काबुल विश्वविद्यालयके व्याख्याता मोहम्मद ऐमल दोस्तयारका बयान उल्लेखनीय है। दोस्तयार कहते हैं दुर्भाग्यसे यूएनएएमएकी हालिया रिपोर्ट वास्तविकताओंपर आधारित नहीं हैंय सदाचार मंत्रालय इन निर्देशोंको प्रभावी ढंगसे लागू करता है। सदाचार मंत्रालयके डिप्टी मोहम्मद फकीर मोहम्मदीने कहा कि हमने तो बल्कि ४६०० महिलाओंको विरासत प्रदान की है। इस्लामिक अमीरात महिलाओंके अधिकारोंके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सारे लोग अमीरातके सितमके आगे सिजदा नहीं करते। धार्मिक विद्वान खलील-उर-रहमान सईदने बयान दिया, दुर्भाग्यसे हमारे देशमें महिलाएं अपने बुनियादी और मानवीय अधिकारोंसे वंचित हैं, जिसमें विरासत, शिक्षा, काम और जीवनसाथी चुननेका हक भी शामिल है। एक अन्य धार्मिक विद्वान हसीबुल्लाह हनफीने महिलाओंको विरासत, शिक्षा, शादीके अधिकारसे इनकार, जबरन विवाह और महिलाओं और लड़कियोंको शादीमें मुआवजेके रूपमें देनेकी प्रथाके बारेमें चिंता व्यक्त की है। तालिबानने इस समय इतनी गुंजाइश दी है कि जो लड़कियां छठी कक्षा पास करनेके बाद स्कूल नहीं जा सकतीं, वह घर बैठे सिलाई-कढ़ाई और कालीन बुनाई, पैकेजिंग करें। उसके लिए कार्यशालाएं खोली गयी हैं।

अर्थ मंत्रालयके प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब कहते हैं, अब संबंधित मंत्रालयोंने आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रोंमें महिलाओंके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं। न केवल काबुल, बल्कि देशके विभिन्न प्रांतोंमें भी, छात्राओंने सिलाई, पेंटिंग, कालीन बुनाई और कढ़ाई जैसे व्यवसायोंको सीखनेकी ओर रुख किया है, ताकि अपने परिवारको सपोर्ट कर सकें। लेकिन मुल्ककी महिलाएं ऐसे हालातको कुबूल करनेके पक्षमें नहीं दिखतीं। इसी हफ्ते अदबी लेखिकाओंने काबुलमें एक कविता गोष्ठी आयोजित की और इस्लामिक अमीरातसे छठी कक्षासे ऊपरकी लड़कियोंके स्कूलोंको फिरसे खोलनेका आग्रह किया। विभिन्न प्रांतोंसे राजधानीमें एकत्र हुईं इन कवयित्रियों और लेखिकाओंने कहा कि लड़कियोंको स्कूल जानेसे रोकना इस्लामी कानून और मानवाधिकार मानदंडोंका उल्लंघन है। एक प्रस्तावमें उन्होंने कहा कि लड़कियोंके स्कूलोंको बंद करनेका कोई धार्मिक औचित्य नहीं है।

कार्यक्रमके आयोजकोंमेंसे एक, ओगीने सवाल किया, हमारा पाप क्या यही है कि हम पुरुष नहीं हैं। अफगानिस्तानमें लड़कियोंके स्कूल बंद हुए ९९२ दिन हो गये हैं। अब भी स्पष्ट नहीं है कि वे फिरसे कब खुलेंगे और भविष्यमें लड़कियोंके लिए क्या होगा। छात्राएं अपने अनिश्चित भविष्यको लेकर तनावमें रहती हैं। उनके लगभग छह महीनेके लिए विश्वविद्यालयोंमें जानेपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने इस्लामिक अमीरातसे छात्राओंके लिए विश्वविद्यालयोंको फिरसे खोलनेका आह्वान किया। एक छात्रा खुजास्ता पूछती है, परीक्षाएं शुरू हो गयी हैं और लड़कोंको परीक्षा देने और अपने विश्वविद्यालयोंमें जानेकी अनुमति है, लेकिन लड़कियोंको अनुमति नहीं है। क्यों। कारण क्या है।

तालिबानने विगत दो वर्षोंमें ८० फतवे जारी किये हैं, इनमेंसे ५४ सीधे तौरपर महिलाओंको निशाना बनाते हैं। वर्ष २००४ में नये संविधानमें लैंगिक समानता सुनिश्चित की गयी और अफगान महिलाओंके लिए संसदमें २७ प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयीं। २०२१ तक अफगान महिलाओंने संसदमें २४९ मेंसे ६९ सीटें हासिल कर ली थीं। ऐसे कानून मौजूद थे, जो महिलाओंको अपने बच्चोंके जन्म प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्रमें अपना नाम शामिल करनेकी अनुमति देते थे। वहां महिला मामलोंका मंत्रालय, एक स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग और महिलाओंके खिलाफ हिंसाको अपराध बनानेवाला कानून था। कानून, राजनीति, पत्रकारितासे लेकर फुटपाथों, पार्कों और स्कूलोंतक महिलाओंकी मौजूदगी थी।

अफगानिस्तानके पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजईने ट्वीटके जरिये आशा व्यक्त की कि लड़कियोंके लिए शिक्षाके द्वार तुरंत खोले जायेंगे। इस समय अमीरातका सबसे भरोसेमंद साथी है, वह अफगानिस्तानके सर्वोच्च नेताको महिलाओंको शिक्षा वाले सवालपर कितना समझा पाता है, इसका इंतजार है। परन्तु मुस्लिम वर्ल्ड दोहरा रवैया दर्शा रहा है। भारतीय मुस्लिम समाज अफगानिस्तानमें महिलाओंको शिक्षा और रोजगार मिलनेके सवालपर खामोश हो जाता है। शायद ही किसी मुस्लिम संघटन या धर्मगुरुका बयान इसपर आयेगा।

अफगानिस्तानके पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजईने जापानके विशेष प्रतिनिधि कानसुके नागाओका के साथ बैठकमें अफगानिस्तान और क्षेत्रकी मौजूदा स्थितिपर चर्चा की। करजईने ट्वीटके जरिये आशा व्यक्त की कि लड़कियोंके लिए शिक्षाके द्वार तुरन्त खोले जायेंगे। कतर, जो इस समय अमीरातका सबसे भरोसेमंद साथी है, वह अफगानिस्तानके सर्वोच्च नेताको महिलाओंको शिक्षावाले सवालपर कितना समझा पाता है, इसका इंतजार सभीको है। परन्तु इस सवालपर मुस्लिम वर्ल्ड दोहरा रवैया दरपेश कर रहा है। आप भारतीय मुस्लिम समाजको ही देख लीजिये, अफगानिस्तानमें महिलाओंको शिक्षा और रोजगार मिले, इस सवालपर सन्नाटा पसरा मिलेगा। शायद ही किसी मुस्लिम संघटन या धर्मगुरुका बयान आप देखेंगे।

फ्रांसीसी चुनावोंका सच

विश्वभरमें लोकतंत्र और बहुलतावादी संस्कृतिको दोहरे चरित्रवालोंसे खतरा है। दुनियामें जहां भी लैफ्टकी सरकार बनी, वहांकी उदारवादी व्यवस्थापर आघात हुआ और अंततोगत्वा वह समाजमें मानवाधिकार हननका प्रतीक बन गया।

❑ **बलबीर पुंज**

'लैफ्ट-लिबरल' कितना विरोधाभासी है, उसका जीवंत उदाहरण फ्रांसके हालिया संसदीय चुनावमें देखनेको मिल जाता है। जब पहले चरणके चुनावमें दक्षिणपंथी नैशनल रैली गठबंधनने वामपंथी दलोंके ऊपर निर्णायक बढ़त बनायी और उसकी प्रचंड जीतकी संभावना बनने लगी, तब इसी 'लैफ्ट-लिबरल' गिरोहके चेहरेसे लिबरल मुखौटा एकाएक उतर गया। वास्तवमें 'लैफ्ट-लिबरल' संज्ञा किसी फरेबसे कम नहीं। यह दो अलग शब्दोंको मिलाकर बना है, जिनका रिश्ता पानी-तेलके मिलन जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां वामपंथ होता है, वहां उसके वैचारिक चरित्रके मुताबिक हिंसा, असहमतिका दमन, मानवाधिकारोंका हनन और अराजक व्यवस्थाकी भरमार होती है। ठीक इसी तरह वामपंथ और एकेश्वरवादी दर्शनका गठजोड़ भी छलावा है। ऐसेमें एक लैफ्टका लिबरल होना असंभव है। इस पृष्ठभूमिमें फ्रांसका घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांसीसी संसदीय चुनावके पहले चरणमें लैफ्ट पार्टियोंके 'न्यू पॉपुलर फ्रंट' के पिछड़नेके बाद लैफ्टने 'एंटीफा' (वामपंथी समूह) और जेहादियोंके साथ मिलकर हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे अपने खिलाफ आये इस जनादेशको माननेको तैयार नहीं हुए। उन्होंने सड़कोंपर कब्जा करके कई निजी-सार्वजनिक संपत्तियोंको पैट्रोल-बमके इस्तेमालसे राख कर दिया तो सुरक्षामें तैनात सैंकड़ों पुलिसकर्मियोंपर टूट पड़े। इस दौरान दंगाइयोंने कई दुकानोंको भी लूट लिया, उनमें तोड़फोड़ की और स्थानीय भवनोंको बदरंग कर दिया।

अधिकतर फ्रांसीसी राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजेपर पहुंच चुके थे कि राष्ट्रवादी दलकी नेता मरीन ले पेनके नेतृत्वमें 'नैशनल रैली' और उसके सहयोगी २५०-३०० सीट जीत सकते हैं। उनका यह अनुमान इसलिए भी ठीक लग रहा था, क्योंकि इसी वर्ष हुए यूरोपीय चुनावमें भी मरीन नेतृत्वने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन 'नैशनल रैली' को किसी भी सूरतमें रोकनेके लिए पहले चरण अलग-अलग चुनाव लड़ने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नीत मध्यमार्गी 'इनसैंबल' और वामपंथी 'न्यू पॉपुलर फ्रंट' ने दूसरे चरणके आखिरी वक्तमें गठबंधन (रिपब्लिकन फ्रट) कर लिया। इसके तहत दोनोंने मिलकर अंतिम समयमें अपने कुल २१७ उम्मीदवारोंको मैदानसे हटा लिया, ताकि दक्षिणपंथ विरोधी वोट एकजुट रहे। परिणामस्वरूप नाटकीय मोड़के साथ 'नैशनल रैली' ऐसी पिछड़ी कि वह पहलेसे सीधे तीसरे स्थानपर खिसक गयी। भले ही दक्षिणपंथी नैशनल रैली चुनाव हार गयी, परंतु उसे सर्वाधिक ३७.१ प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ तो उसके विरोधी लैफ्ट गठजोड़ और मैक्रों नीत 'इनसैंबल' का मतप्रतिशत क्रमश: २६.३ प्रतिशत और २४.७ प्रतिशत ही रहा। फ्रांसकी ५७७ सदस्यीय नैशनल असैंबली (संसद) में तीनों प्रमुख गठबंधनोंमें से किसीको भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय द्वारा जारी नतीजोंके मुताबिक वामपंथी 'न्यू पॉपुलर फ्रट' सबसे ज्यादा १८८ सीट तो मध्यमार्गी 'इनसैंबल' को १६१ सीट और दक्षिणपंथी 'नैशनल रैली' १४२ सीट जीतनेमें सफल रही है। भारतमें भी 'लैफ्ट-लिबरल' का पाखंड फ्रांससे अलग नहीं है। यहां कांग्रेसके शीर्ष नेता और लोकसभामें नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधीको इसी श्रेणीमें रखना, गलत नहीं होगा। वे विशुद्ध वामपंथीकी तरह 'जितनी आबादी, उतना हक' नारा लगाते हुए हिन्दुस्तानके धनको पुर्नवतरित करनेकी बात चुके हैं।

इस संबंधमें ३१ मार्च २०२४ को दिल्लीके रामलीला मैदानमें विपक्षी दलोंकी 'लोकतंत्र-संविधान बचाओ' रैलीमें राहुलके उस वक्तव्यको याद करना स्वाभाविक हो जाता है, जिसमें उन्होंने देशको हिंसाकी आगमें झोंकनेका ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था 'मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। यदि हिन्दुस्तानमें मैच फिक्सिंग कर चुनाव भाजपा जीती और उसके बाद संविधानको उन्होंने बदला तो इस पूरे देशमें आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो। ये देश नहीं बचेगा।' दोबारा फ्रांसीसी चुनावकी ओर लौटते हैं। फ्रांसमें मरीन ले पेनको उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधीके रूपमें पेश किया जाता है। मरीन फ्रांसीसी सैकुलर मूल्यों और राष्ट्रीय पहचानकी रक्षाके लिए आप्रवासियों द्वारा बढ़ते अपराधके खिलाफ आक्रामक रही है। इसमें अक्तूबर २०२० में प्रवासी मुस्लिम द्वारा फ्रांसीसी शिक्षकका 'सिर तनसे जुदा' करनेकी घटना भी शामिल है। अब जो वाम-जिहादी समूह पहले चरणके फ्रांसीसी चुनावमें हारनेपर हिंसक हो गया था, वे दूसरे चरणके चुनावमें बढ़त बनानेके बाद हाथोंमें फिलिस्तीनी झंडा लेकर सड़कोंपर उतरे और अराजकता फैलाने लगे। स्थानीय मीडियाके अनुसार वामपंथी गठजोड़ द्वारा आयोजित कई 'विजय समारोहों' में फ्रांसीसी ध्वजों-झंडोंकी तुलनामें फिलिस्तीनी झंडे फहराते और 'गाजा-गाजा' नारे लगाते देखे गये थे। वर्ष १९९१ में वामपंथ नीत सोवियत संघके विघटनके बाद विश्वमें अमरीका और यूरोप सहित सत्ताके कई केन्द्र बन चुके हैं, जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली 'राज्यहीन' और 'बिना उत्तरदायित्व' वाला समूह भी शामिल है। किसी उपयुक्त संज्ञाके अभावमें इस वर्गको 'वोक' कह सकते हैं।

यह समूह छोटा, अति-मुखर और आक्रामक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियासे चुनी सरकारोंको उसके उन घोषित एजैंडेको लागू करनेसे रोकने और व्यवस्थाको पंगु करनेका प्रयास करता है। स्वघोषित 'लैफ्ट लिबरल' और 'वोक' मानकर चलते हैं कि शेष समाज निर्णय लेनेमें गैर-काबिल है, इसलिए उन्हें ही उनका भला करनेका दैवीय अधिकार प्राप्त है। पूरे विश्वमें लोकतंत्र और बहुलतावादी संस्कृतिको खतरा है तो वह दोहरे चरित्रवाले 'लैफ्ट लिबरल' से है। कोई हैरानी नहीं कि दुनियामें जहां-जहां लैफ्टकी सरकार बनी, वहांकी उदारवादी व्यवस्थापर आघात हुआ और अंततोगत्वा वह समाजमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारोंके हननके प्रतीक बन गया। भारतकी कालजयी उदारवादी परम्पराओंको इसी 'लैफ्ट लिबरल' और 'वोक' से भी सर्वाधिक खतरा है।

आत्मबोध

बेड़ी हनुमान

❑ **सुनन्दा पटनायक**

ओडिशा राज्यके पुरीमें स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, इतिहासके कारण तो मशहूर है ही, यहांपर स्थापित हनुमान जीकी मूर्ति भी बेहद खास है। दरअसल इस मंदिरमें हनुमान जी बेडियोंमें बंधे हुए हैं। जी हां, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि संकटमोचन कहे जानेवाले हनुमान जी स्वयं कैसे इस तरह बेडियोंमें बंधे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। पौराणिक मान्यताओंके अनुसार भगवान जगन्नाथके इस स्थानपर आनेके बाद सभी देवता, मनुष्य, गंधर्वोंकी इच्छा हुई कि वह भगवानके दर्शन करें। सभी भगवान जगन्नाथके दर्शनके लिए वहां पहुंचे। सभीको दर्शनके लिए जाते देख समुद्रके मनमें भी दर्शनकी लालसा हुई और उसने कई बार मंदिरमें प्रवेश करनेका प्रयास किया, जिसकी वजहसे मंदिर और भक्तोंको काफी नुकसान हुआ। जब समुद्रने कई बार मंदिर और वहां आनेवाले भक्तोंको हानि पहुंचायी तब सभी भक्तोंने भगवान जगन्नाथसे इस समस्याका समाधान करनेका आग्रह किया। क्योंकि समुद्रकी भगवानके दर्शनकी लालसाके चलते भक्तोंका दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ जीने हनुमान जीको समुद्रको नियंत्रित करनेके लिए नियुक्त किया। पवनसुतने समुद्रको बांध दिया। यही वजह है, पुरीका समुद्र शांत रहता है। माना जाता है कि हनुमान जी भगवान जगन्नाथके आदेशका पालन करते हुए दिन-रात समुद्रकी पहरेदारीमें लगे रहते थे, जिसके बाद समुद्रका मंदिरमें प्रवेश करना मुश्किल हो गया। समुद्रने बड़ी ही चतुराईसे हनुमान जीकी भक्तिका फायदा उठानेके लिए उन्हें ललकारा कि तुम प्रभुके कैसे भक्त हो, जो कभी दर्शनके लिए नहीं जाते। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथके अनुपम सौंदर्यको निहारनेका। तब हनुमानजीने भी सोचा कि बहुत दिन हो गये हैं, क्यों न आज प्रभुके दर्शन कर ही लें। कथाके अनुसार समुद्रके बहकानेपर हनुमान जी भी प्रभु जगन्नाथके दर्शनके लिए चल पड़े, तभी उनके पीछे-पीछे समुद्र भी चल पड़ा। इस तरह जब भी पवनसुत मंदिर जाते तो समुद्र भी उनके पीछे चल पड़ता। इस तरह मंदिरमें फिरसे क्षति होनी शुरू हो गयी। तब जगन्नाथ जीने हनुमानकी इस आदतसे परेशान होकर उन्हें स्वर्ण बेड़ीसे बांध दिया। कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरीमें सागर तटपर बेड़ी हनुमानजीका प्राचीन मंदिर वही है, जहां उन्हें भगवानजीने बांधा था।

समस्याओंकी जननी बनी बढ़ती जनसंख्या

❑ **अनुज आचार्य**

भारतमें आजादीके समय कुल जनसंख्या ३३ करोड़ थी जो २०११ की जनगणनाके मुताबिक बढ़कर १२५ करोड़ पहुंच गयी थी। कोरोना महामारीके चलते २०२१ की जनगणनाका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉकके अनुसार ५ जुलाई २०२४ को भारतकी जनसंख्या १४५२९६२४२१ थी, जिसमें ७५०२०२८३५ पुरुष आबादी (५१.६ फीसदी), महिला जनसंख्या ७०२७५९५३९ करोड़ (४८.४ प्रतिशत) थी और विश्वकी कुल जनसंख्या ८११९७०३९९९ थी। इंडिया स्टेट डॉट कॉमके अनुमानके अनुसार २०३० तक भारतकी कुल जनसंख्या १५३ करोड़ और २०५० तक १६८ करोड़तक पहुंच जायगी। विश्वकी दूसरी सबसे बड़ी आबादी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थावाले देश चीनने लम्बे समयतक एक बच्चा पैदा करनेकी नीतिको सख्तीसे लागू किया हुआ था। लगभग १४३ करोड़की आबादीवाले देश चीनमें अब वहांकी कम्युनिस्ट सरकारने तीन बच्चोंको अपनानेकी नीतिकी घोषणा की है। चीन जहां अपने यहां बढ़ती बूढ़ी आबादी और कम होती युवा श्रम शक्तिसे परेशान है तो वहीं भारतकी ६५ फीसदी युवा आबादी जहां भारतका संबल है तो वहीं देशमें बढ़ती बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतीका पर्याय भी है। भारतकी बढ़ती जनसंख्याका असर वैश्विक भूख सूचकांक २०२३ (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) की रिपोर्टमें भी देखा जा सकता है, जिसमें १२५ देशोंकी सूचीमें भारत १११वें स्थानपर है और भूखकी 'गम्भीर' श्रेणीमें है। इस इंडेक्समें भारतके पड़ोसी देशों- पाकिस्तान (१०२वें), बंगलादेश (८१वें), नेपाल (६९वें) और श्रीलंका (६०वें) ने भारतसे बेहतर स्थान हासिल किया है। विशेषज्ञोंने इसके लिए खराब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानीकी कमी, कुपोषणसे निबटनेका उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्योंके खराब प्रदर्शनको दोषी ठहराया है। एक अन्य रिपोर्टके अनुसार भारतकी १४ फीसदी आबादी कुपोषणकी शिकार है। वैश्विक भूख सूचकांकमें देशोंको चार प्रमुख संकेतकोंके आधारपर रैंकिंग दी जाती है- अल्पपोषण, बाल मृत्यु, पांच सालतकके कमजोर बच्चे और बच्चोंका अवरुद्ध शारीरिक विकास। बढ़ती आबादीके पीछे अशिक्षा, अंधविश्वास, परिवार नियोजनके तौर-तरीकोंमें जागरूकताका अभाव और स्वास्थ्यके प्रति लापरवाही जैसे बुनियादी कारण हैं। जनसंख्या वृद्धिके कारण नयी पीढ़ीको भविष्यके लिए बुनियादी जरूरतों और सुविधाओंकी कमीका सामना करना पड़ेगा।

आज भी भारतीयोंको बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट, भुखमरी, चिकित्सा सुविधाओं, कुपोषण, स्वच्छ पेयजलकी कमी, बिजली-पानीके संकट और गरीबीसे बुरी तरहसे जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आवासकी समस्या, गंदा पानी और कूड़ा कचरा जैसी समस्याएं अलगसे मुंह बाये खड़ी हैं। यदि समय रहते सरकारोंने आनेवाली पीढ़ियोंको सुंदर सुखी जीवन देनेके लिए अभीसे प्रयास शुरू नहीं किये तो भविष्यमें भावी पीढ़ियोंके समक्ष आपसी संघर्षकी परिस्थितियां निर्मित होना तय है।

इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रणके अभावमें देशकी आर्थिक स्थिति बिगड़नेसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जून २०२४ में बेरोजगारी दर बढ़कर आठ महीनेके उच्च स्तर ९.२ प्रतिशतपर पहुंच गयी, जो पिछले महीने सात प्रतिशत थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ोंके अनुसार जून २०२३ में यह दर ८.५ प्रतिशत थी। भारतमें ७० के दशकमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। उस समय भी महिलाओंकी नसबंदीपर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। आपातकालके दौरान व्यापक पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया था जिसमें एक सालके अंदर साठ लाखसे ज्यादा लोगोंकी नसबंदी कर दी गयी थी जिसका भारी विरोध भी हुआ था। यह वक्तका तकाजा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें जनसंख्या वृद्धिसे पैदा हो रही चुनौतियोंसे निबटनेके लिए एक सर्व स्वीकार्य कार्यक्रम सामने लेकर आयें, ताकि भारतीय लोग परिवार नियोजनको स्वेच्छासे अपनाकर देशको आनेवाली पीढ़ियोंके लिए रहने लायक बनानेकी दिशामें अपना योगदान दे सकें। सही तरीकेसे गर्भनिरोधक उपायों, गर्भपात, बन्धीकरण, एकल बच्चा पैदा करनेकी नीति और परिवार नियोजन आदि उपायोंसे ही जनसंख्या वृद्धिको रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एकल और दो बेटियोंवाले सरकारी कर्मचारियोंको प्रोत्साहन स्वरूप विशेष आर्थिक राशि प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेशमें इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजनाके तहत अब एक बेटीके बाद परिवार नियोजन अपनानेवाले परिवारको दो लाख रुपये मिलेंगे। वहीं दो बेटियोंके बाद परिवार नियोजन अपनानेपर अब एक लाख रुपये मिलेंगे।

इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवसका थीम है 'भविष्यकी पीढ़ियोंको सशक्त बनाना: सतत विकास और जनसंख्या रुझान।' जनसंख्या दिवस हमें याद दिलाता है कि समस्याओंको समझने, समाधान तैयार करने और प्रगतिको आगे बढ़ानेके लिए डेटा संग्रहमें निवेश करना महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण कानूनको लेकर पिछले कई दशकोंसे बहस चल रही है। १९७० के दशकसे हम सभी 'हम दो हमारे दो' का नारा सुनते आये हैं। हालांकि कभी भी किसी सरकारने जनसंख्या नियंत्रणके कानूनको लागू करनेकी हिम्मत नहीं दिखायी। जनसंख्या नियंत्रणपर कानून बनाने या इसका जब भी जिक्र होता है, तब हिंदू-मुस्लिम बहस छिड़ जाती है। कुछ मुस्लिम नेताओंका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिम विरोधी है। लेकिन यह समयकी मांग है कि भारतमें बढ़ती आबादीसे उत्पन्न हो रही चुनौतियोंसे निबटनेके लिए केन्द्र सरकारको जनसंख्या नियंत्रण कानूनको अनिवार्य रूपसे शीघ्र सिरे चढ़ाना होगा।

मोदी की रूस यात्रा रणनीतिक महत्त्व का साबित हुई

रूस के लिए मोदी की यात्रा रणनीतिक महत्त्व का साबित हुई। रूस का खास प्रयास पश्चिम के इस प्रचार को झुठलाने का है कि उसे अंतरराष्ट्रीय जगत में अलग-थलग कर दिया गया है। इस लिहाज से इस यात्रा का महत्त्व स्पष्ट है। भारत-रूस दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा को सफल बताया है। लेकिन सफलता को मापने के दोनों के संभवतः अलग-अलग पैमाने हैं। भारत की नजर में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में हुए समझौतों से देश को फायदा होगा। दोनों देशों ने 2030 तक सालाना आपसी व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का इरादा जताया है, जो फिलहाल 65 बिलियन डॉलर के करीब है। खबरों के मुताबिक रूस भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल देते रहने पर राजी हुआ है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में तकनीक ट्रांसफर जारी रखने पर भी रजामंदी हुई। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के सामने भारतीय नौजवानों को जबरन रूसी सेना में शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर पुतिन उन्हें जल्द वहां से मुक्ति देने पर सहमत हुए। इसके अलावा भारत के नजरिए एक सफलता यह भी है कि रूस ने अपने प्रतिष्ठित सम्मान- ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द अपोस्टल से मोदी को सम्मानित किया। विदेश में मोदी के ऊंच कद की छवि बनाना गुजरे दस साल में भारतीय विदेश नीति का एक खास प्रयास रहा है। इस सम्मान से इस कथा में एक नया पहलू जुड़ा है। उधर रूस के लिए यह यात्रा दूरगामी रणनीतिक महत्त्व का साबित हुई। पिछले सवा दो साल में रूस का खास प्रयास पश्चिम के इस प्रचार को झुठलाने का है कि उसे अंतरराष्ट्रीय जगत में अलग-थलग कर दिया गया है। जिस भारत में अमेरिका ने गुजरे वर्षों में खास रणनीतिक निवेश किया है, उसके प्रधानमंत्री मास्को जाकर पुतिन के गले लगें, तो उसका प्रतीकात्मक महत्त्व स्पष्ट है। रूस और चीन की फिलहाल कोशिश यह है कि भारत को जितना संभव है तटस्थ रखने का प्रयास किया जाए, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पश्चिमी रणनीति ऊहापोह की शिकार बनी रहे। इसीलिए चीन में मोदी की मास्को यात्रा का दिल खोल कर स्वागत किया गया है। बेशक, इस यात्रा से अमेरिका की तल्खी बढ़ी है, जो उसके विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से जाहिर हुआ है। तो कुल मिला कर दोनों पक्षों ने अपने हित साधे। फिलहाल इसमें वे सफल रहे हैं।

सरकार के शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय हो

मानसून की पहली बारिश में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल एक की पार्किंग एरिया में कैनोपी यानी छत गिर गई। इस हादसे में आठ गाड़ियां दब गईं। इनमें से एक गाड़ी टैक्सी थी, जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था और छत गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दिल्ली हवाईअड्डे के साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर और गुजरात के राजकोट हवाईअड्डे पर भी बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हुईं। जिस समय एक के बाद एक ये तीन घटनाएं हुईं उसी समय बिहार में पुल गिरने की खबरें आ रही थीं। एक पखवाड़े में कोई एक दर्जन पुल गिर गए। ज्यादातर पुल पुराने थे लेकिन कम से कम दो पुल ऐसे थे, जो अभी बन ही रहे थे। यानी निर्माणाधीन पुल गिरे। उसी समय या उससे थोड़ा पहले यह खबर आई थी कि मुंबई के जिस अटल सेतु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले उद्घाटन किया था उसमें दरारें आ गई हैं। हालांकि बाद में कहा गया कि दरार पुल पर नहीं, बल्कि एप्रोच रोड पर आई है। यह ऐसी सफाई थी, जिसमें पूरी व्यवस्था को बचाने का प्रयास साफ दिख रहा था। इससे कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंघा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें पांच लोग मारे गए। यह बिल्कुल उसी तरह का हादसा था, जैसा पिछले साल बालासोर में हुआ था, जिसमें करीब तीन सौ लोगों की जान गई थी। दोनों दुर्घटनाओं के समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही थे। ऐसी दुर्घटनाओं के समय मीडिया में यह बताने का प्रचलन रहा है कि कैसे एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। यह भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने भी एक हादसे के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन अब तो नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते! उनके राज्य में पिछले एक पखवाड़े में एक दर्जन पुल गिरे हैं। दो निर्माणाधीन पुल गिरे हैं। कुछ समय पहले 17 सौ करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उससे थोड़े दिन पहले गंडक नदी पर बना 264 करोड़ रुपए का पुल गिर गया था। उनके राज्य में शराबबंदी है और सैकड़ों लोग नकली शराब पीकर मर गए। लेकिन ऐसी किसी घटना के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ और न उन्होंने आगे आकर जवाबदेही स्वीकार की। यही हाल हवाईअड्डों की छत गिरने में है, यही हाल रेल दुर्घटनाओं में है और यही हाल बारिश में सड़कों के धंसने, पहाड़ टूटने, जंगलों में आग लगने जैसी घटनाओं में भी है।

रूस और ऑस्ट्रिया की यात्राओं से भारत की नई उड़ान

आरती कुमारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ-साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। इन दोनों देशों की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली होगी। दोनों देशों की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। सैन्य उत्पाद, व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन दोनों देशों में जो सम्मानभावना देखने को मिली, उससे यही कहा जा सकता है कि मोदी विश्व-नेता के रूप में स्वतंत्र पहचान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत के लिये शुभ है। निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में अपनी चमक के साथ आगे बढ़ते भारत के लिये रूस की यात्रा कई मायनों में बहुत उपयोगी एवं दूरगामी रही। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में हुए नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात थी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुतिन ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत-रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। भारत-रूस की दोस्ती की गर्माहट से चीन एवं पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है। यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दुनिया की नजरें लगी रही। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमरीका और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की स्थिति एवं उसकी बढ़ती ताकत का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमरीका की सधी प्रतिक्रिया सामने आयी कि इससे उसके भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही इससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो धुरवीय नहीं रही। अमेरीका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। वास्तव में इस आवश्यकता ने भी अमेरीका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि अब भारत का समय आ गया है। वास्तव में आज अमेरीका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। कहना न होगा कि वैश्विक मंच पर योग का विषय हो, या अहिंसा का या फिर आतंकवाद से निपटने का, जलवायु परिवर्तन का मसला हो या फिर जी-20 देशों की अध्यक्षता की बात, भारत, दुनिया को नई दिशा दे रहा है, नई उम्मीदें जगा रहा है। एक नई ताकत एवं सशक्त अर्थ-व्यवस्था के साथ एक नया ध्रुव बनकर उभर रहा भारत समूची दुनिया की नजरों का ताज बना हुआ है। भारत अब बिना किसी दबाव के किसी भी अन्य ताकतवर देश की नाराजगी मोल लेने का हौसला रखता है। शीतयुद्ध के दौर में दो धुरवीय विश्व व्यवस्था के बाद एक धुवीय व्यवस्था का अनुभव दुनिया को मिल चुका है। अब बहुधुरवीय विश्व व्यवस्था में ही संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बन भारत वैश्विक भूमिका को खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है। वैसे भी भारत एक बड़े देश के पाले में कभी नहीं रहा। अनेक संकटों से घिरा होकर भी भारत अपनी बात बुलन्दी के साथ दुनिया के सामने रखता रहा है, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के तीनों कार्यकाल में भारत ने अपने शक्तिशाली होने का भान कराया है। भारत की रूस से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमरीका, ऑस्ट्रिया या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है। इजरायल से नई दोस्ती के बावजूद फिलिस्तीन पर हमारी रणनीति नहीं बदली है। उसी तरह रूस से अच्छे संबंध का यह मतलब नहीं कि यूक्रेन के मामले में उसे क्लीन चिट दे दें। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। भारत की इस भूमिका के बीच अब अमरीका भी यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल शांति के पक्षधर अन्य देश भारत के साथ मिलकर रास्ता खोजने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौता वार्ता का मंच बनने की इच्छा जाहिर करना यही बताता है। भारत अहिंसा एवं शांति का हिमायती का देश है और मानता है कि युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध केवल बर्बादी और तबाही लेकर ही आता है। रूस व यूक्रेन के बीच जो सीमा विवाद है वह इन देशों के बीच का मामला है और भारत शुरू से ही कहता रहा है कि इस समस्या का हल केवल बातचीत से ही होना चाहिए। श्री मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान भी भारत का यही रुख सामने रखा और स्पष्ट किया कि किसी भी झगड़े को निपटाने का रास्ता केवल वार्तालाप ही हो सकता है। श्री मोदी ने रूस से आस्ट्रिया पहुंच कर भी इस रुख को और खोला और कहा कि भोले-भाले लोगों की हत्या कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध के सन्दर्भ में इस तथ्य को अमेरिका को ही सबसे पहले समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से क्या चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा? क्योंकि रूस एवं चीन के बीच बढ़ती मित्रता एवं प्रगाढ़ता समूची दुनिया के लिये एक चिन्ता का सबब है। भले ही अमरीका की ताकत को देखते हुए रूस ने चीन से निकटता बनाई हो, लेकिन भारत से उसकी दोस्ती इन सबसे ऊपर है। फिर भी चीन एवं पाकिस्तान भारत के दुश्मन ही रहे हैं। इन हालातों के बीच मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के भाग्य के लिए नये सूर्य का उदय कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी महत्वपूर्ण यात्रा रूस की रही, उतनी ही महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया की यात्रा भी रही। मोदी ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी निशाने पर लेते हुए पुतिन से कहा कि चीन जहां पाकिस्तान के आतंकवाद को सहयोग-समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अब मोदी की इन बातों का पुतिन पर क्या असर होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। जहां तक रूस से मित्रता का सवाल है तो यह भारत का परखा हुआ सच्चा मित्र है और भारत यह दोस्ती कभी नहीं छोड़ सकता। पिछले दो दशकों में हमारे सम्बन्ध अमेरिका से भी मधुर हुए हैं परन्तु हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतन्त्र है और दुनिया का कोई भी देश इसे प्रभावित नहीं कर सकता। भारत के द्विपक्षीय सम्बन्ध किस देश के साथ कैसे हैं यह केवल भारत ही तय करेगा। अमेरिका हमें रूस-यूक्रेन के बारे में क्या समझायेगा? भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक महाबड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और भारत शांति एवं अयुद्ध का हिमायती है। हम तो पहले ही यह कह चुके हैं कि भारत बुद्ध-महावीर-गांधी का देश है और इसकी विदेश नीति भी इनसे प्रेरणा लेकर ही तय होती रही है। बदलते वैश्विक सन्दर्भों के बावजूद भारत आपसी शान्ति, अहिंसा, युद्धमुक्त विश्व-संरचना व सह अस्तित्व पर ही विश्वास रखता है। दुनिया की महाशक्तियों द्वारा भारत को तवज्जो देने के पीछे जिन वजहों को देखा जा रहा है, उनमें व्यापारिक प्रगति के साथ शांति एवं अमन-चैन की दुनिया बनाना भी मुख्य है। निश्चित ही मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के लिये 'सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना' एवं 'परिवर्तनकारी क्षण' साबित होगा।

विश्व में कहीं बढ़ती आबादी की परेशानी है तो कहीं घटती आबादी बनी है अभिशाप

अशोक भाटिया , मुंबई

हमने जब से होश संभाला हमें यही बताया गया कि बढ़ती आबादी किसी भी देश के लिए खराब होती है, जब हाल ही में हिंदुस्तान ने चीन को आबादी के मामले में पछाड़ा तो कई मीम्स वायरल हुए और हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी का मजाक बनाया गया लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कई प्रसिद्ध लोग ज्यादा आबादी को किसी देश के लिए बेहतर मानने लगे हैं। हाल ही में 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और भारत में जगह – जगह बढ़ती आबादी के विस्फोटक होने का रोना रोया गया। इस मौके पर यह यह भी जानना जरुरी है कि कैसे सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत कई मायनों में कई देशों से बेहतर स्थिति में है। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने एक बयान से सबका ध्यान आकर्षित किया। दरअसल मस्क ने कहा कि यूरोप में बेहद कम बर्थ रेट की वजह से जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है साथ ही यहां बाहर से आने वालों की संख्या में भी कमी आई है जिस वजह से यूरोप के कई देशों में जनसंख्या के अकाल जैसी नौबत आ गई है। अगर ये नहीं बदला तो आने वाले समय में कम जन्म दर की वजह से दुनिया के कई देश लोगों से लगभग खाली हो जाएंगे जिसके फलस्वरूप ये देश बर्बाद हो सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि कई 'डेड सिविलाइज़ेशन' की खोज हुई है, यानी ऐसी सभ्यताएं जिनका अस्तित्व सदियों पहले खत्म हो चुका है। आखिर इस बयान से मस्क क्या कहना चाहते हैं कि क्यों किसी देश के लिए उसके लोग और जनसंख्या जरूरी है। दरअसल किसी देश को उसके लोग ही जिंदा रखते हैं। बढ़ती जनसंख्या को अभिशाप मानते हुए पहले कई देशों ने जनसंख्या नियंत्रण का पालन किया अब वही देश अपने लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण चीन, जापान, साउथ कोरिया, रूस, ईरान, इटली, स्पेन, फिनलैंड, हंगरी जैसे विकसित और विकासशील देश हैं जो इस समय कम जनसंख्या होने के चलते अपनी गिरती जीडीपी से परेशान हैं और अपने देश के लोगों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में वर्षों पहले एक बच्चे की नीति अपनाई गई। असके बाद चीन की आबादी लगातार कम होती रही है। चीन की घटती आबादी का असर वहां की घरेलू अर्थव्यवस्था पर तो दिख ही रही है, बल्कि वैश्विक स्तर भी पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। यही कारण है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री इससे चिंतित हैं।चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में जंनसंख्या घटने को लेकर चिंता साफ झलक रही है। आपको बता दें कि वर्षों तक चीन में बड़े पैमाने पर कामकाजी उम्र की आबादी रही है। इसी के बल पर ड्रैगन ने दुनिया में तेजी से विकास किया। सस्ते लेबर के दम पर दुनिया भर में निर्यात किए जाने वाले सामानों का उत्पादन किया। अब जब यहां की जनसंख्या घट रही है तो चीन के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है। इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका भी चीनी आयात वाले सामान पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन से कारोबार समेटने की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। एप्पल और नाइके जासी कंपनी अपना कोराबर चीन में समेटने की शुरुआत कर चुकी है। चीनी की घटती जनंसख्या दुनिया के बाजार के लिए बुरी खबर है। इस बीच चीन जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील देने के लिए तैयार नहीं है। चीन के लिए ये बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होता जा रहा है। जन्म दर घटने से युवाओं की संख्या कम हो रही है। चीन में कई दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू रही। माना जा रहा है कि उन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के चलते ही देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। चीन में मरने वालों का आंकड़ा, पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा है। सरकार इससे निपटने के लिए एक के बाद एक पॉलिसी लेकर आ रही है, लेकिन इसके सकारात्मक नतीजे नहीं निकल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर चीन में लोग शादी करना और बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहते हैं? चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, यहां की जनसंख्या में साल 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस देश में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 के अंत में देश की जनसंख्या 1141175 अरब थी। जो साल 2021 के 1141260 अरब के मुकाबले कम है। बता दें कि चीन कभी दुनिया में सबसे आबादी वाला देश था। अब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए चीनी सरकार ने 2016 में वन-चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसके बाद 2020 में तीन बच्चे पैदा करने की नीति बनाई गई है। इसके लिए बीजिंग, सिचुआन और जियांगशी प्रांत में माता-पिता को ज्यादा छुट्टी देना, मैटरनिटी लीव, शादी के लिए छुट्टी और पैटरनिटी लीव बढ़ाने जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। हालांकि, इसके बाद भी जन्म दर घट ही रही है। जेएनयू के प्रोफेसर और इतिहासकार हरिश वानखेड़े उस समय के बारे में बताते हैं कि जब हिंदुस्तान में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से ऐसे तरीके अपनाए जा रहे थे जो किसी के सामाजिक अधिकारों का हनन थे, साथ ही इतने बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के ये उपाय किसी भी रूप में ठीक नहीं थे। इसके लिए पर्याप्त शिक्षा की जरूरत है जिसकी कमी हमेशा से ही भारत में रही है, जिसकी वजह से हम सही तरीके नहीं अपना पाते। इमरजेंसी के समय नसबंदी जैसे तरीके अपनाए गए लेकिन आज के समय में लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना जरूरी है। हरीश आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन समेत एशियाई देशों में जनसंख्या हमेशा से ही यूरोपियन देशों से ज्यादा रही है और ऐसे में हमें समझना जरूरी है कि जनसंख्या किसी देश की ताकत है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश तरक्की कर सकता है। जिस तरह से चीन ने अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल किया है वो एक बेहतरीन उदाहरण है और इस मामले में हमें चीन से सीखना चाहिए। जनसंख्या का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सही तरीके से हो तो आपकी इकोनॉमी आसमान छू सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में उस तरह की पॉलिसी लाना बाकी है क्योंकि अभी भी एक बड़ी आबादी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और काफी युवा आबादी बेरोजगार है। इसके लिए हमारे देश में ऐसी पॉलिसी और रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या का इस्तेमाल सही तरीके से हो। समाजशास्त्री और प्रोफेसर दीपक केम का कहना है कि ये बात सही है कि ज्यादा जनसंख्या का असर देश में सीमित रिसोर्सेज पर देखा जाता है जिससे देश में गरीबी बढ़ती है लेकिन साथ ही जनसंख्या कंट्रोल करने के अपने कुछ नुकसान भी हैं। ज्यादा जनसंख्या को लेकर एक बार यूएस के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने भारत पर तंज कसते हुए कहा था कि इस देश की आबादी अमेरिका से काफी ज्यादा है और यहां मिडल क्लास जनसंख्या का आधिपत्य है। ऐसे में जब ऐसे देश से डिमांड बढ़ती है तो महंगाई अपने आप बढ़ती है। हालांकि बुश के इस बयान की काफी आलोचना की गई लेकिन भारत को हमेशा से ज्यादा आबादी पर लोगों की तल्खियां झेलनी पड़ी हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी देश की जनसंख्या उसकी इकोनॉमी के लिए वरदान होती है क्योंकि इकोनॉमी क्या है, लोग खरीदारी करते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है जिससे इकोनॉमी में पैसा आता है और डेवलपमेंट होता है। जब किसी देश की पर्चेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी बड़ी होती है। दूसरा किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए, ये तभी होगा जब किसी देश के पास यंग मैन पॉवर हो। यही वजह है कि चीन ने भी एक या दो बच्चे का कानून खत्म कर दिया है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है मगर अब यहां भी ज्यादा आबादी बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन अभी भी हमारी स्थिति दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर है। इसलिए हिंदुस्तान को जनसंख्या कंट्रोल करने की नहीं जनसंख्या को सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हमारे देश में हमारी युवा आबादी के पास रोजगार होगा तो हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी होगी। हमारी आबादी का फायदा सीधा हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। आज ज्यादातर देशों की इकोनॉमी के पिछड़ने की वजह यही है कि वहां युवा आबादी या कहें कि कुल आबादी ही बेहद कम है। वहां मार्केट तो है लेकिन खरीदार नहीं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पिछड़ रही है यही वजह है कि वो अपने देश के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगा रहे हैं साथ ही ऐसे देश खत्म होने के डर से दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में आकर रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनके देश में जनसंख्या बढ़ने से देश की इकोनॉमी में कुछ सुधार आए। उधर हिंदुस्तान जो आज विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है वो इस अवसर को भुनाने में नाकाम हो रहा है क्योंकि वो अपनी आबादी को पर्याप्त रोजगार देने में फेल हो रहा है। अगर हिंदुस्तान अपनी आबादी का सही से इस्तेमाल करे तो हमारी इकोनॉमी को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता।

मेष राशि–आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े-बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी।

वृष राशि–आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज किसी बड़ी कंपनी से आपके लिए जॉब का ऑफर आ सकता है। आज आप कोइ नया हुनर सीखेंगे। परिवार में किसी सदस्य से आपको अच्छी सलाह मिलेगी। आज आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज कारोबार में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज जीवनसाथी की मदद से आपका काम आसान हो जायेगा।

मिथुन राशि–आज आप दिन की शुरुआत अच्छे मूड से करेंगे। आज अपने किसी रुके काम को पूरा करने का सही समय है। सिविल इंजीनीयर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य समस्या से परेशान लोग आज खुद को बेहतर महसूस करेंगे। जॉब की तलाश कर लोगों को अच्छी जॉब मिलने के योग हैं। आज आप दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं।

कर्क राशि–आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे तो काम समय से पूरा हो जायेगा। आज आपको दूसरों का मूड समझने में बहुत हद तक सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय धैर्य और समझदारी रखें। आज परिवार के कामों में आप व्यस्त रहेंगे। आज पारिवारिक मामले में कोई भी फैसला शांति से लेंगे तो आपका काम बन जायेगा।

सिंह राशि–आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। परिवार का माहौल आज अच्छा रहेगा। आज धार्मिक गतिविधि में भी शामिल होने के योग बन रहे हैं। दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से आपको फायदा होगा। आज जरूरी काम और रिश्तों के बारे में विचार करेंगे। परिवार से जुड़ी कोई परेशानी खत्म होने के योग हैं । रुके हुये कार्यों को नए सिरे से फिर कोशिश करें, आप सफल अवश्य होंगे।

कन्या राशि–आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज ऑफिस के कार्य मेहनत, धैर्य और समझदारी से निपटा लेंगे। आज आपके पास बहुत-सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं । आज परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय बीत सकता है। रोजगार में स्थितियां पहले से ठीक होने की संभावना है।

तुला राशि–आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है लम्बे समय से सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा । माता के साथ घर के कामों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। शाम का समय परिवार वालों के साथ अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी ताल- मेल बना रहेगा। आज आपको अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

वृश्चिक राशि–आज का दिन आपके अच्छा रहने वाला है। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है आप अपना समय मन-पसंद काम करने में बिता सकती हैं। इस राशि के मंत्रियों की विदेशी यात्रायें हो सकती है। किसी बात को लेकर भाई-बहन से विचार विमर्श करेंगे। आज किसी से भी बेवजह मजाक करने से आपको बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पढ़ाई व काम के बीच संतुलन बनाकर रहेंगे तो जल्द ही सफलता मिलेगी।

धनु राशि–आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लाया है। आप परिवारवालों के साथ समय बितायेंगे घर में खुशी का महौल बना रहेगा। इस राशि के एग्रोकेमिकल व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। कहीं रूका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य आज पहले से काफी अच्छा रहेगा।

मकर राशि–आज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगो के लिए दिन अच्छा है समाज हित में किये गये कामों की तारीफ़ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। महिलाए अपने जीवनसाथी को आज कुछ मीठा बना कर खिला सकती है दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी स्वास्थ्य फिट रखने के लिए योग की रूटीन अपनाएं, फायदा मिलेगा।

कुंभ राशि–आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस के कलीग्स के साथ बाहर जा सकते हैं। लवमेट के रिश्ते की बात घर पर होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स पर काम करते हैं, उनकी जान-पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा।

मीन राशि–आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। इस राशि के टैक्सटाइल व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनायेंगे। ऑफिस के कार्यों को आज समय से पूरा कर लेना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए डेली रूटीन में मैडिटेशन व योगा अपनाएं।

शब्द सामर्थ्य -116

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. चौड़ी और सपाट जमीन, रणभूमि 3. स्वरग्राम, संगीत के सात स्वरों का समूह 6. धूल का कण, किसी वस्तु का सूक्ष्मकण, धूल 7. हिम्मत, सामर्थ्य 8. अभ्यर्थना, रिसेप्शन, यथा अवसर पर पूछे जाने वाला मंगल कुशल 9. आपस का करार, निबटारा 10. वरदान, दुल्हा 12. भोग, ऐश्वर्य 13. कीमत, मूल्य 14. एक वाद्ययंत्र जिसे सपेरे बजाते हैं 16. समता, बराबरी 18. अश्लील, बेहूदा, अभद्र, घटिया 19. युक्ति, उपाय, ढंग 20. रिक्त, अपूर्ण।

ऊपर से नीचे

1. दोस्ती, मित्रता 2. अच्छी शिक्षा, नेक सलाह 4. बचाव, हिफाजत 5. मीठापन, मधुर होने का भाव 7. समुद्र 8. आत्मनिर्भर, जो दूसरे पर आश्रित न हो 9. रसवाला, रसदार 11. मां का बच्चों के प्रति प्रेम 13. खैरात, देने की क्रिया 15. दृष्टि, निगाह 16. वरिष्ठ, बुजुर्ग, चतुर 17. पराजय, हार।

1	2			3	4		5	
							6	
	7							
8				9				
10								11
		12					13	
14	15				16	17		
			18					
19							20	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 115का हल

ला	लू	प्र	सा	द	या	द	व	
प		ति			र	क्ष	क	
र	ह	मा	न					आ
वा			मि	थु	न		दा	स
ह	वा	ला	त		सी	ता		पा
	न				ब	क	वा	स
औ	र	त		म		त		
ला		बे	च	ना		व	च	न
द	ह	ला		ना	ग	र		दी

सूडोकू नवताल- 7125

★★★ मध्यम

4	6		3		8	9		7
	1		9		6		5	4
						8		
	4		5				8	
2		5		4		6		1
	3				1		7	
		3						
5	9		7		2		6	
7		6	4		3		9	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकू नवताल -7124 का हल

5	7	2	3	8	4	1	9	6
8	6	1	9	2	5	7	3	4
3	9	4	1	6	7	5	8	2
2	5	7	4	1	3	8	6	9
4	8	6	5	9	2	3	7	1
1	3	9	6	7	8	4	2	5
6	2	3	7	4	1	9	5	8
9	4	5	8	3	6	2	1	7
7	1	8	2	5	9	6	4	3

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नाटो सम्मेलन

यूक्रेन का समर्थन

नाटो सम्मेलन, 2024 में यूक्रेन को समर्थन देने तथा रक्षा तैयारियां मजबूत करने की प्रतिज्ञा की गई है। 75 साल पहले वाशिंगटन में एकत्र 12 देशों ने 'उत्तर एटलांटिक संधि' पर हस्ताक्षर किए जो नाटो के नाम से लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य तत्कालीन सोवियत संघ के नेतृत्व में उभर रहे साम्यवाद तथा उसके अनेक देशों में विस्तार से सामूहिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना था। इस वर्ष 32 नाटो सहयोगियों ने एक बार फिर वाशिंगटन में बैठक की जिसमें सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। इन 75 वर्षों में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। सोवियत संघ का विघटन हो गया है तथा सोवियत-समर्थक देशों के बीच सैनिक गठबंधन 'वारसा संधि' समाप्त हो गई है। लेकिन नाटो जीवित है और उभरती विश्व व्यवस्था में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सदस्य देशों के बीच रणनीतिक विमर्श तथा उच्च स्तरीय चर्चाओं के तीन दिन बाद नाटो सम्मेलन, 2024 की समाप्ति हुई। मूलत: शीतयुद्ध के उत्पाद नाटो सैन्य सहयोग संगठन ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है, सामूहिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग के नए आयाम खोजे हैं। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण विषय नाटो का सामूहिक सुरक्षा दृष्टिकोण मजबूत करना है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव और टकरावों को देखते हुए नाटो नेताओं ने अपने संगठन की सैनिक क्षमता और तैयारियां बढ़ाने पर सहमति प्रकट की। इसमें सदस्य देशों द्वारा रक्षा खर्च में बढ़ोत्तरी, पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त बलों की तैनाती तथा साइबर रक्षा व्यवस्थाओं की प्रगति शामिल हैं। नाटो

सदस्यों ने अपनी परंपरागत भौगोलिक सीमाओं से आगे भी साझेदारियों के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की।
सम्मेलन ने गैर-सदस्य देशों से संपर्क बढ़ाने तथा वैश्विक सुरक्षा सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उसके प्रमुख सहयोगियों में जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड शामिल हैं। उन्होंने साझा सुरक्षा सरोकारों तथा सहयोगी पहलों पर चर्चा में भाग लिया। नई विश्व व्यवस्था में चीन और रूस वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी पक्ष के रूप में उभरे हैं। यूक्रेन में जारी टकराव पर सम्मेलन में चर्चा हुई। नाटो ने यूक्रेन की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अडिग समर्थन पुन: व्यक्त किया। नाटो मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है और उसने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया है, लेकिन वह रूस से सीधे टकराव तथा युद्ध को व्यापक बनाने से बचता रहा है। भारत ने अब तक नाटो से 'सुरक्षित दूरी' बनाए रखी है। उसने अपना गुटनिरपेक्ष मार्ग निर्धारित किया है और नाटो तथा अब समाप्त हो चुके वारसा संधि से समान दूरी बनाए रखी है। हालांकि, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, पर उसने सम्मेलन की घटनाओं पर गहरी नजर रखी है। वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण पक्ष होने के कारण नाटो सम्मेलन के परिणामों के भारत के रणनीतिक हितों तथा विदेश नीति पर अनेक प्रभाव होंगे। भारत लगातार नाटो सदस्यों से रक्षा व सुरक्षा सहयोग समेत विभिन्न मोर्चों पर संपर्क करता रहा है। नाटो सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा तथा साझेदारियों पर जोर दिया गया है। इससे नाटो देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत होने की संभावनायें खुली हैं। इस दृष्टिकोण से नाटो देशों के साथ भारत के संयुक्त सैनिक अभ्यासों, खुफिया सूचनाओं का साझा तथा रक्षा तकनीकी सहयोग को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ावा मिल सकता है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में सुधार होगा।

लोकतंत्र में सभ्यता व निष्ठा जरूरी

हालिया लोकसभा चुनाव के बाद नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवैधानिक सिद्धान्तों तथा संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित उच्च मानकों का पालन अवश्य करना चाहिए।

जे.एस. राजपूत
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

संविधान और संविधान निर्माताओं का सम्मान किसी कारगर लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। हालांकि, चुनाव के समय प्रतियोगी उम्मीदवारों तथा उनकी पार्टियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ जाती है, पर इसे उत्सव की तरह देखना चाहिए। यह न केवल देश, बल्कि मतदाताओं तथा भावी मतदाताओं के लिए भी जरूरी है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब प्रत्येक उम्मीदवार अन्य सभी का सम्मान करे तथा अपने शब्दों व उनके प्रयोग के बारे में हमेशा सचेतन रहे, फिर चाहे वह संवाद, साक्षात्कार या प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के दृष्टिकोण की समीक्षा ही क्यों न हो। चुनाव में उतरने वाले सभी लोगों को यह याद रखना जरूरी है कि नौजवान पीढ़ी उनके कृत्यों पर गंभीरता से गौर कर रही है। इसलिए सार्वजनिक और निजी तौर पर उनको अपने व्यवहार व आचरण के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

हालांकि, बढ़ते बच्चों को स्वरूप देने में परिवार तथा स्कूल की प्रमुख जिम्मेदारी है, पर समाज व खासकर ऐसे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जो समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। केवल 'आचार्य' व उसका व्यवहार ही अनुकरणीय नहीं होता है, बल्कि बच्चे अपने विकास के वर्षों में अनेक स्रोतों से सीखते हैं और कोई भी उनके गहन प्रेक्षण से बाहर नहीं होता है। हालिया चुनावों को देखने, उनका विश्लेषण करने और उनमें सहभागिता करने वाला कोई भी व्यक्ति इन 'उम्मीदों' को केवल 'काल्पनिक' कह सकता है, बल्कि उसे ऐसा भी लग सकता है कि ये कभी पूरी नहीं होंगी। चुनाव परिणामों के बाद संसद की बैठक हुई और कुछ मिनट की निकटता के बाद फिर अविश्वास की वही पुरानी प्रवृत्ति तथा निराशा की भावना हावी हो गई। इन बाधाओं को देखते हुए राष्ट्र को एक बार फिर सदन के दोनों सदनों में दोनों पक्षों की ओर से शोर-शराबे तथा बहिर्गमन के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

यह आश्चर्यजनक तथा दु:खद रूप से चिन्ताजनक है कि महान भारतीय लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि एकसाथ बैठ कर ऐसे तरीके नहीं खोज सकते हैं कि वे एकसाथ बैठें, अपनी भावनायें अभिव्यक्त करें तथा मतदाताओं के कल्याण के लिए उपयुक्त नतीजे निकालें। वे यह कैसे अनदेखा कर सकते हैं कि वे गांधी, अंबेडकर, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी तथा संविधान बनाने वाले अन्य उल्लेखनीय महानुभावों के वारिस हैं जिन्होंने उनको निर्वाचित होने तथा वे सारी वेतन व भत्तों की सुविधायें लेने में सक्षम बनाया है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी ने मुझे बताया कि जिस प्रकार लोग अपने तथाकथित अनशन, राजनीतिक नौटंकियों या ऐसी ही अन्य चीजें करने के लिए राजघाट जाते हैं, उन घृणित कृत्यों से वे शर्मिन्दा होते हैं। मैं उनकी इस पीड़ा का साझा करता हूं तथा अनेक अन्य लोगों का भी यही सोचना है। ऐसे घृणित कृत्य करने वालों को डा. अंबेडकर के वे शब्द याद रखने चाहिए जो उन्होंने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के समापन भाषण में कहे थे।

उन्होंने कहा था, 'यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र न केवल स्वरूप, बल्कि तथ्यात्मक रूप से बना रहे तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज हमारे सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का पालन है। इसका अर्थ है कि हमें खूनी क्रांति के तरीके छोड़ने होंगे और हमें नागरिक नाफरमानी, असहयोग तथा सत्याग्रह के रास्ते छोड़ने होंगे।' उन्होंने कहा कि संविधान स्थापित हो जाने के बाद इस राष्ट्र, उसके लोगों तथा खासकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि 'संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह निश्चित रूप से खराब हो जाएगा क्योंकि इसके लिए काम करने वाले लोग खराब होंगे। संविधान चाहे जितना खराब हो, यदि उसके लिए काम करने वाले लोग अच्छे हों तो वह अच्छा हो जाएगा। संविधान केवल राज्य के अंगों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का प्राविधान करता है। राज्य के इन अंगों का कामकाज उन लोगों और राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करता है जो इन उपकरणों का प्रयोग कर अपनी इच्छाओं व राजनीति को अभिव्यक्ति देंगे।'

न केवल अंबेडकर, बल्कि अन्य महानुभावों ने समान रूप से भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति चिन्ता व्यक्त की थी। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने अपनी अंतिम टिप्पणियों में जो कुछ कहा था वह प्रत्येक संसद सदस्य के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होना चाहिए, भले ही वह किसी भी पार्टी से हो। उन्होंने कहा था, 'संविधान में चाहे हो या नहीं, देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका प्रशासन कैसे किया जाता है। यह उसे संचालित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा। यह कहना उचित होगा कि किसी देश को ऐसी सरकार मिलती है जिसके वह योग्य हो। यदि निर्वाचित लोग सक्षम, चरित्रवान तथा निष्ठावान होंगे तो वे खराब संविधान से भी सर्वोत्तम निकाल लेंगे। लेकिन यदि उनमें इसकी कमी हो तो संविधान देश की मदद नहीं कर पाएगा। आखिरकार संविधान एक निर्जीव मशीन की तरह होता है। यह उसे नियंत्रित करने और चलाने वालों से जीवन प्राप्त करता है। भारत को आज ऐसे ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो देश के हित को अपने हितों से ऊपर रखें।' इतिहास के इस मोड़ पर भारतीय नागरिकों के अनुभवों, बेचैनी और पीड़ा की इससे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। भारत को आज भारतीय समाज के हर हिस्से में जागरूकता की आवश्यकता है। यदि नव-निर्वाचित सांसद अपना उल्लेखनीय राजनीतिक कॅरियर बनाना चाहते हैं तो उनको तीन उल्लेखनीय भारतीय महापुरुषों-गांधी, राजेन्द्र प्रसाद और अंबेडकर के विचारों को अपने भीतर समाहित करना होगा।

यह इन तीनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इससे वे भारत तथा उसकी जनता की सेवा के प्रति स्वयं को तैयार कर सकेंगे। विद्वानों और संस्थानों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कुछ आयामों का गंभीर विश्लेषण कर यह पता लगाना चाहिए कि वास्तविक व्यवहार तथा मतदाताओं के बीच इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए उनको अकादमिक विश्वसनीयता के साथ जनता को बताना चाहिए कि गांधीवादी मूल्यों का क्षरण क्यों हुआ है, जबकि भारतीय संविधान बनने के बाद इनको संविधान निर्माताओं के सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक आयामों में शामिल होना चाहिए था। ये सभी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी थे तथा अपने बलिदानों, संग्रह न करने की प्रवृत्ति तथा उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर को उनके महान योगदानों के लिए न केवल भारत, बल्कि सारी दुनिया में माना जाता है। बहुत से लोगों को यह देख कर आश्चर्य होता है कि उनका नाम लेने वाले अनेक लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनका प्रयोग करते हैं, पर उनके मूल सिद्धान्तों को भुला देते हैं। एससी-एसटी समुदायों के आरक्षण पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि यह न केवल संसद सदस्यों, बल्कि राज्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी है कि वे लक्षित समूहों को लाभ देने वाले आरक्षणों की सीमा का तथ्यात्मक विश्लेषण करें। आखिर दुष्ट राजनेताओं को जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र और भाषा के खेल खेलने की अनुमति कहां तक दी जाएगी? यदि यह सब जारी रहने दिया गया तो सामाजिक एकजुटता तथा धार्मिक सद्भाव वाला भारत बनाना असंभव हो जाएगा।

इस परिदृश्य में एक बार पिछली शताब्दी के साठ के दशक पर विचार करें। उस समय महात्मा गांधी हमसे विदा ले चुके थे, पर जनता में उनकी सोच गायब नहीं हुई थी। उस समय नौजवानों का मानना था कि अगले दो से तीन दशकों में 'जाति व्यवस्था' को समाप्त कर दिया जाएगा। यह उस समय भारतीय संविधान की भावना थी और यह बाबा साहेब के सपनों का भारत था।

उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर ने भी 'एनीहिलेशन आफ कास्ट्स' यानी जाति व्यवस्था समाप्त करने की अवधारणा बनाने के साथ उसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी।

प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक रूस यात्रा

> प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ने भारत की विदेश नीति में रूस के महत्व को रेखांकित किया।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

इस सप्ताह दुनिया भर के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई हाई-प्रोफाइल बैठकें हुईं, जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न संघर्षों और संभावित परिणामों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान अपनी पहली राजकीय यात्रा में रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा किया।

यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह पहली राजकीय यात्रा थी और यह भारत के मामलों में रूस की प्रधानता को रेखांकित करती है। इस बीच, वैश्विक भू-राजनीति पर चर्चा करने के लिए सभी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नेता वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए। सभी चर्चाओं में यूक्रेन और मध्य पूर्व प्रमुख रूप से शामिल थे, भले ही उनके विचार काफी अलग थे।

राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकों के बाद भारत-रूस संयुक्त बयान में कहा गया, दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति सहित यूक्रेन के आसपास के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से मध्यस्थता और अच्छे कार्यालयों के प्रासंगिक प्रस्तावों की सराहना की। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नेताओं के एक टेलीविज़न भाषण के दौरान अपने रूसी समकक्ष से कहा था कि शांति सबसे महत्वपूर्ण है और यूक्रेन का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं पाया जा सकता।

उन्होंने कीव में बच्चों के अस्पताल पर बमबारी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा जब मासूम बच्चों की हत्या की जाती है, तो हम उन्हें मरते हुए देखते हैं, दिल दुखता है और यह दर्द असहनीय होता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत में कई बार टेलीफोन पर बात की है, ने भारत की रूस की राजकीय यात्रा को शांति प्रयासों के लिए झटका कहा। नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारी में नाटो महासचिव, श्री स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि मित्र देश यूक्रेन के लिए एक वित्तीय प्रतिज्ञा पर सहमत होंगे, और उन्हें यूक्रेन को और अधिक तत्काल सैन्य सहायता की भी उम्मीद है। यूक्रेन नाटो के करीब जा रहा है । नाटो के साथ घनिष्ठ संबंध रूस के यूक्रेन में आने के कारणों में से एक था। रूस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले दशक में अपेक्षाकृत नए रणनीतिक संबंध विकसित किए हैं, जिनमें से भारत-अमेरिका साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यह ध्यान देने योग्य है कि यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर भारत ने अभी तक रूस की आक्रामकता के लिए मौखिक रूप से आलोचना नहीं की है और मॉस्को के खिलाफ बहुपक्षीय प्रस्तावों से भी दूर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले कुछ महीनों में, कई अमेरिकी शीर्ष नेताओं ने युद्ध के संबंध में भारत के रुख की आलोचना की थी और यहां तक ??कि प्रतिबंधों की धमकी पर भी चर्चा की गई थी। हालांकि, दोनों दीर्घकालिक साझेदारों द्वारा किए गए कुशल कूटनीतिक प्रयासों के कारण, उच्च-स्तरीय आलोचना बंद कमरे की बैठकों तक ही सीमित रही। पीएम मोदी की रूस की राजकीय यात्रा ने वाशिंगटन में यूक्रेन को लेकर पिछले कुछ समय से चली आ रही नाराज़गी को फिर से जगा दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका ने रूस के साथ अपने संबंधों के बारे में भारत के समक्ष चिंता जताई है।

उन्होंने कहा, हम भारत से आग्रह करेंगे, जैसा कि हम किसी भी देश से करते हैं जब वह रूस के साथ बातचीत करता है, कि वह स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष का कोई भी समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने वाला होना चाहिए, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो। यह ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में अमेरिका को भारत के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक माना जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने दोबारा चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा में से एक में बीजिंग का दौरा किया और पिछले हफ्ते कज़ाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय यात्रा की। चीन और रूस ने बिना किसी सीमा के मित्र बनने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है, और उन्हें व्यापक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है।

भारत और चीन भारत की सीमाओं पर सैन्य आक्रमण के कारण बेहद मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। भारत ने अभी तक मुश्किल हालात से निपटने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन किसी समय उसे विश्व संघर्षों पर अधिक कार्रवाई योग्य बयानों के साथ संतुलन बनाना होगा।

आप की बात

आतंकी हमले

जम्मू के कठुआ में सेना पर किया गया हालिया आतंकी हमला और पहले भी जम्मू में आतंकियों द्वारा 5-6 घटनाओं को अंजाम दिया जाना चिन्ता का विषय है। इनमें तीर्थयात्रियों पर किया हमला भी शामिल है। श्रीनगर में आतंक नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद उन्होंने जम्मू में अपने अड्डे बनाने के प्रयास लिए हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर कुछ भारत-विरोधी तत्व उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को आतंकियों के बीच अपने मुखबिरों को प्लांट करने के प्रयास तेज करने चाहिए। इसके साथ ही उसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त करना चाहिए ताकि आतंकियों व उसके समर्थकों के बारे में समुचित जानकारी सही समय पर मिल सके। बॉर्डर पर स्पष्ट रूप से सामने आने वाले दुश्मन से युद्ध लड़ना आसान है। मगर देश की जनता में छुपे देशद्रोहियों का सफाया तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। इसके लिए उन्हीं के तौर तरीकों से उनका सफाया किया जाना चाहिए। आतंकी घटनायें बढ़ने पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक की जरूरत पैदा हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन व पुलिस में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी जासूसों या आतंकी-हमदर्दों को तलाश कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी समय की आवश्यकता है।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

मोदी के वैश्विक प्रयास

महीनों से चल रहे रूस-यूक्रेन के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में सबसे पहले रूस पहुंचे और राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाक़ात कर यूक्रेन समस्या के युद्ध के बजाय शान्ति वार्ता से समाधान की बात कही। वे पहले भी पुतिन से ऐसी ही गुजारिश कर चुके हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया में भी उन्होंने शान्ति की बात कहते हुए याद दिलाया कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। दोनों ही देशों में उन्होंने युद्ध नहीं, शान्ति की बात करते हुए दुनिया में शांति स्थापना के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से दुनिया में -इन्फ्लूएंस के बजाय कान्फ्लूएंस बढ़ाने, यानी देशों द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र व वर्चस्व बढ़ाने के बजाय दूसरे देशों के विचारों को सुनने और उनको एक व्यापक दृष्टिकोण में समाहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहले दो कार्यकालों में भारत को मिले वैश्विक सम्मान तथा स्वीकार्यता पर आगे बढ़ते हुए देश का कद और बढ़ाना चाहते हैं। मोदी के ये वैश्विक प्रयास दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके व तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इनसे भारत विश्व गुरु भी बनेगा।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

बंगाल में अराजकता

सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में अमन चैन कायम नहीं हो पा रहा है। यहां से आए दिन हिंसा व उपद्रव की खबरें आ रही हैं। हत्याएं होना आम बात हो गई है। आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी आग में घी का कारण है। पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु और अधिक सख्ती से कदम उठाने होंग। चाहे अपना हो या पराया किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीमावर्ती राज्य होने से कारण वहां पर कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक रहना पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के कड़े उपाय करने होंगे। ये भी किसी खतरे से कम नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश के एक महत्वपूर्ण नेता की हत्या में बांग्लादेशियों का हाथ होने से स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश के अराजक तथा बांग्लादेश सरकार-विरोधी तत्वों को पश्चिम बंगाल में पैर जमाने का स्थान मिल रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल की स्थितियां भारत-बांग्लादेश मैत्री में भी बाधक बन सकती हैं। विडंबना है कि ममता बनर्जी जहां अपने प्रदेश में होने वाले जघन्य कांडों की सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाती हैं, वहीं वे मोदी व शेख हसीना के बीच हुए समझौते का विरोध करती हैं।

-हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

एआई का वर्चस्व

कला जगत ही नहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में एआई का वर्चस्व बढ़ रहा है। उद्योग धंधों, इलाज, मनोरंजन, संगीत, फिल्में, शिक्ष, युद्ध व राजनीति से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक में अब एआई की मौजूदगी से कोई क्षेत्र अछूता रहने वाला नहीं है। हर नई तकनीक अपने साथ कई फायदे तो कुछ बुराइयां भी लेकर आती है। कला जगत में डरने के बजाय इसे चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। एआई के प्रयोग से कला जगत नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। अपने सृजन को एआई के सहयोग से और अधिक निखार कर पेश किया जा सकता है। एआई से कुछ क्षेत्रों के रोजगार कम होंगे तो कई नए रोजगार शुरू भी होंगे। ऐसा लगता है कि पहले आई तकनीकों की तुलना मे एआई का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आम जनता, खासकर गरीब व हाशियाकृत समुदायों पर इसके प्रभावों का आंकलन करना भी जरूरी होगा। यदि एआई से कुछ विशिष्ट व अति-प्रतिभाशाली लोगों को रोजगार मिलें तथा बड़ी संख्या में अर्धकुशल या अकुशल लोगों के रोजगार छिन जाएं तो यह चिन्ता का विषय होगा। ऐसे में कौशल संवर्धन को भी सर्वाधिक महत्व देना होगा।

-विभूति बुपक्या, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 13 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

नाटो, युद्ध और शांति

यह महज संयोग है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मास्को में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वैश्विक शांति के लिए बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करते हुए अपनी बात को दोहरा रहे थे कि यह युद्ध का समय नहीं है, लगभग उसी समय वाशिंगटन में अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के सदस्य देश रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में घी डालने का काम कर रहे थे। उनका विश्वास है कि रूस युद्ध का समर्थक है और उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इतना ही नहीं, रूस यूरोप सहित पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। इसलिए नाटो देशों ने घोषणा की है कि अगले एक वर्ष के दौरान यूक्रेन को 40 अरब यूरो डॉलर की सैन्य सहायता दी जाएगी। फरवरी, 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। यह सब जानते हुए भी अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को अभी तक 50 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता दे चुका है। हाल में उसने घोषणा की है कि वह 2026 में जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। इसका उद्देश्य रूस की चुनौतियों का सामना करना है। इसका स्पष्ट मतलब है कि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि शांति वार्ता की मेज पर एक साथ बैठ कर विमर्श करें। राष्ट्रपति पुतिन इस संकेत से अनजान नहीं हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पिछले महीने स्विटजरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में शामिल होने से इंकार कर दिया। पश्चिमी देश पुतिन को आक्रमणकारी और रक्त पिपासू ठहराते हैं लेकिन यह सच नहीं है। वस्तुतः यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की घोषणा के कारण पुतिन को अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सही मायने में नाटो का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। चीन का भी ऐसा ही मानना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 19वीं सदी की उस ऐतिहासिक वियना कांग्रेस की याद दिलाई जिसने यूरोप में शांति और स्थिरता कायम करने में महती भूमिका निभाई थी। चांसलर नेहमर को विश्वास है कि भारत रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस शांति प्रक्रिया में नाटो को आगे आना होगा वरना पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है।

सुनवाई जरूरी

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल अलग-अलग किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बार दिल्ली कूच करने की बजाय देशव्यापी विरोध की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा को वे प्रमुखता देंगे। इन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। फसल बीमा, किसानों को पेंशन बिजली के निजीकरण को बंद करने के साथ सिंधु और टिकरी सीमा पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग भी कर रहे हैं। समर्थन मूल्य को लेकर यह आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था। यूं तो इसे बड़े किसानों का आंदोलन कहा जा रहा है लेकिन किसानों का एक वर्ग मोदी सरकार की कृषि नीतियों से संतुष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से मिले आश्वासन और आम चुनाव के दौरान आंदोलन कुछ वक्त के लिए ठहर सा गया था। देश में छोटे किसानों की तादाद बहुत है। दूसरे वे लोग हैं, जो कृषि कार्यों के जरिए जीवन यापन करते हैं। उन सबको इन आंदोलनों या मांगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हर देशवासी को है। वह सरकार के समक्ष अपनी कोई भी मांग रखने को आजाद है। मगर पिछले आंदोलन के दरम्यान प्रदर्शनकारियों के कारण कई स्थानों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। आगजनी और पथराव हुआ था। सुरक्षाबलों पर हथियार भी प्रयोग हुए। इसी दरम्यान पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के शंभू बार्डर पर धरनारत किसानों को हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को भी बैरिकेड हटाने और चड़ीगढ़-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का आदेश दिया है। पांच महीनों से अवरुद्ध इस मार्ग के खोलने से कारोबारियों और नियमित यात्रियों को होने वाली असुविधा से निजात मिल सकेगी। हम कृषि प्रधान देश हैं इसलिए उनकी जरूरतों और मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। मगर उन्हें भी उग्र विरोध से बचना चाहिए। अड़ियल रुख दिखाने की बजाय सरकार को भी छोटे किसानों के हितों की रक्षा में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

कटाक्ष/ कबीरदास

राम नाम पर लूट है...!

कौन जानता था कि ये राम विरोधी इतने गिर जाएंगे। बताइए, पहले मोदी जी का विरोध करते-करते, राम का विरोध करने लगे। पर अब तो ये राम तो राम, रामकृपा का भी विरोध करने तक चले गए हैं। कहते हैं कि राम मंदिर बनने से पहले, राम की नगरी में जमीनों की खरीद-बिक्री में जो करोड़ों-अरबों रुपया बनाया गया है, वह तो राम के नाम पर ठगी है। राम के नाम पर ठगी यानी राम के साथ ठगी। यह तो राम के घर में लूट है।

हम पूछते हैं कि राम भक्तों के लिए लूट और ठगी जैसे अपराध विज्ञान के शब्दों के प्रयोग की इजाजत कैसे दी जा रही है? डेमोक्रेसी का ये मतलब थोड़े ही है कि जो बाकी सब के लिए जो लूट और ठगी है, उसी को राम भक्तों के लिए भी लूट और ठगी मान लिया जाएगा। हर्गिज नहीं। वर्ना इस महान देश के बच्चे क्या अब तक बाबरी मस्जिद के गिरने को, बाबरी मस्जिद का गिरना ही मान और बता नहीं रहे होते। पर मोदी जी ने ऐसा होने दिया क्या? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तो कभी थी ही नहीं। जब मस्जिद थी ही नहीं तो मस्जिद के गिरने-गिराने की बात ही कहां से आई? बस जमीन थी और तीन गुंबद थे। और राम जी के भव्य मंदिर के लिए जमीन की जरूरत थी।

भव्य मंदिर के लिए जमीन तरह-तरह से आई-जीत कर आई, खरीद कर आई, धक्के से आई। गरीबों के मंदिरों से आई, गरीबों के घरों से आई, गरीबों की दूकानों से आई, गरीब गुंबदों से आई। जमीन कैसे भी आई, राम जी के काम के लिए आई। और राम जी का काम तो राम जी का काम है, उसमें गलत तरीका क्या और सही तरीका क्या? सही-गलत के चक्कर में पड़े रहते, तो राम जी कबीर के अंदाज में आज भी बाजार में खड़े होते-लिए लुकाठी हाथ, कि मैं घर जारों तास का, जो चले हमारे साथ! खैर!

अगर राम जी के काज में भक्तों ने चार पैसे कमा भी लिए तो क्या हुआ? राम जी के काज में उनके भक्त पैसे नहीं कमाएंगे, तो क्या उनके विरोधी पैसे कमाएंगे। अयोध्या में नहीं कमाएंगे तो क्या काबुल में कमाएंगे? इसे लूट नहीं राम जी की कृपा कहिए। फिर बेशक, कृपा की लूट कहिए-राम नाम पर लूट!

सावधानी ही बड़ा बचाव

साइबर क्राइम

सतीश सिंह

भारत में साइबर अपराधों में काफी विविधता आई है। 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' की तर्ज पर अपराधी अब नये-नये तरीकों से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। नई मोडस ऑपरेंडी है 'डिजिटल हाउसअरेस्ट'। इस तकनीक की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में काफी तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर,11 मई को एक बुजुर्ग डॉक्टर को डिजिटली हाउसअरेस्ट करके 45 लाख रुपये ठगे गए। 15 अप्रैल को इंदौर के एक दंपति को 53 घंटों तक हाउसअरेस्ट करके रखा गया और लाखों रुपये ठगे गए। 6 जुलाई को वाराणसी में 3 दिनों तक डिजिटल हाउसअरेस्ट के जरिए सोनारपुरा के निहार पुरोहित से 28.75 लाख रुपये ठगे गए।

आजकल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी ठगी की जा रही है। कूरियर, रिश्तेदार, दोस्त की गिरफ्तारी आदि की धमकी, अश्लील वीडियो आदि नये-नये तरीकों की मदद से ठगी करने की वारदात में तेजी आई है। स्नैप चैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अब ठगी के साधन बन गए हैं। मित्र या रिश्तेदार की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई और पिछले दशक में भारतीय बैंकों में 65017 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े निश्चित रूप से डराने वाले हैं।

हाल के वर्षों में कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए साइबर अपराध करने की घटनाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा देती हैं, जिसके तहत कॉल एवं एसएमएस को फॉरवर्ड किया जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल उपभोक्ता तब करते हैं, जब मीटिंग या किसी जरूरी काम में व्यस्त होते हैं, ताकि कोई जरूरी कॉल मिस न हो। इसके जरिए स्कैमर कॉल करके उपभोक्ताओं को यह कहता है कि हम आपकी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी से बोल रहे हैं। हमने नोटिस किया है कि आपके नंबर पर नेटवर्क की समस्या है। समस्या को दूर करने के लिए आपको 'स्टार 401 हैशटैग' नंबर डायल करना होगा। यह नंबर डायल करने के बाद उपभोक्ता को अंजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही, उपभोक्ता कॉल करता है, उसके सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल ही में 'विश्व साइबर अपराध सूचकांक' तैयार किया है, जिसके अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक

में 100 देशों को शामिल किया गया है। इसके मुताबिक साइबर अपराध के मामले में रूस शीर्ष पर है, जबकि यूक्रेन दूसरे, चीन तीसरे, अमेरिका चौथे, नाइजीरिया पांचवें, रोमानिया छठे और उत्तर कोरिया सातवें स्थान पर है। बीते कुछ वर्षों से गूगल सर्च इंजन पर लोग अपने हर प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे मनोविज्ञान को दृष्टिगत कर ठग नामचीन भुगतान एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर सहेज रहे हैं जिसके कारण खुद से लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं।

अब तो ब्राउजरएक्सटेंशनके डाउनलोडिंग के जरिए भी साइबर अपराध किए जा रहे हैं। यह काम वायरस के जरिए किया जाता है। सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल एवं लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं। क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिए किए गए ऑनलाइन लेन-देन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अज्ञानतावश लोग ऐसा नहीं करते हैं, और इसका फायदा साइबर ठगों को मिल जाता है। फिशिंग के तहत किसी बड़ी या नामचीन कंपनी या फिर यूजर की कंपनी का फर्जी बेवसाइट बनाकर, जिसका स्वरूप असली बेवसाइट जैसा होता है से लुभावने मेल किए जाते हैं, जिसमें मुफ्त में महंगी चीजें देने की बात कही गई होती है। मोबाइल का चलन बढ़ने के बाद हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं, जिनमें मैलवेयर युक्त हाइपर लिंक दिया हुआ होता है। मैलवेयर, कंप्यूटर या मोबाइल या टैब में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ यूजर की वित्तीय जानकारी जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण, उनके पासवर्ड, ओटीपी, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता नंबर, जन्मतिथि आदि चुरा लेता है। यह यूजर की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से दूसरे को फर्जी ईमेल भी भेज सकता है और इसके जरिए ठगी करने के साथ-साथ संवेदनशील जानकारी अवांछित लोगों को बेची भी जा सकतीं है। साथ ही साथ, इसकी मदद से किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा सकता है।

आजकल साइबर अपराधी फोन कॉल्स या एसएमएस द्वारा लोगों को बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बता कर उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग छोटी राशि मसलन 2000 से 5000 रुपये के लिए ज्यादा की जा रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पुलिस में शिकायत नहीं करें। लोन रिकवरी एजेंट यह धमकी देते हैं, आपने हमसे कर्ज लिया है और अगर दो-तीन दिनों में पैसे वापिस नहीं करेंगे तो आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी या आपके सगे-संबंधियों या सहकर्मियों के साथ साझा कर दी जाएंगी और सबूत के तौर पर वे मोर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो भेजते हैं। मोबाइल एप से लोन लेना सूदखोर या महाजन या साहूकार से भी ज्यादा खतरनाक है।

कई बार लोन रिकवरी एजेंट लोगों से सिर्फ पैसे ही नहीं ठगते हैं, बल्कि समाज में उन्हें बदनाम भी कर देते हैं। अगर लोग ब्राउजिंग सेशन के दौरान संदेहास्पद पॉपअप से सतर्क रहें, और सुनिश्चित करें कि वेबसाइट्स या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करेंगे, अंजान नंबर या ईमेल आईडी से आए अटैचमेंट को तुरंत डिलीट कर देंगे और ऑनलाइन लॉटरी, कैसिनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की उपेक्षा करेंगे तो फिशिंग मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड होने वाले संदेहास्पद हाइपर लिंक के जाल से बचा जा सकता है। मामले में सावधानी ही बचाव है। लालच नहीं करें। यह सभी समस्याओं की जड़ है। मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आएं। धमकी मिलने पर पुलिस की मदद लेने से हिचकें नहीं। तभी साइबर अपराध का शिकार बनने से बचा जा सकता है।

> अब तो ब्राउजरएक्सटेंशनके डाउनलोडिंग के जरिए भी साइबर अपराध किए जा रहे हैं। यह काम वायरस के जरिए किया जाता है। सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल एवं लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं। क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिए किए गए ऑनलाइन लेन-देन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अज्ञानतावश लोग ऐसा नहीं करते हैं

देश के श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की चिंता

- साल 2022-23 में देश के कुल श्रमबल में महिलाओं का राष्ट्रीय अनुपात 37 फीसद दर्ज किया गया। साल 2021-22 में यह आंकड़ा 32.8 फीसद था
- बेशक, यह छलांग कम नहीं कही जा सकती लेकिन यह बढ़ा हुआ अनुपात भी 50 फीसद से ऊपर के ग्लोबल ऐवरेज के सामने फीका पड़ जाता है
- कुल श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़त नाकाफी है, और सरकार की बड़ी चिंता है कि देश के श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

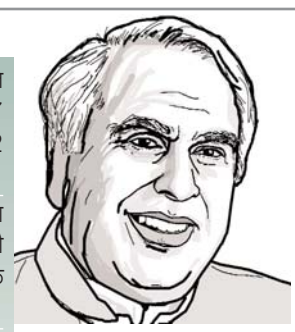

राजनीतिज्ञों के लिए अयोध्याः धर्म और चांदी काटने का मसला–मंदिर का उद्घाटन करके राजनीतिक फसल काटने की कोशिश-अयोध्या में और उसके आसपास के इलाकों में जमीन खरीद कर धन कमाना-एक दूसरे से जुड़े हुए उपक्रम ही तो हैं, और आम जन मूकदर्शक भर है।

कपिल सिब्बल, राजनेता
@KapilSibal

बच्चों पर जानलेवा कहर

मौसम परिवर्तन **भगवती प्र. डोभाल**

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में हर घंटे औसतन 345 नवजातों का समय से पहले जन्म हो रहा है यानी मां के गर्भ में शिशु का नौ महीने तक विकास होता है, तब जन्म लेता है, पर अब ऐसी स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिससे 'प्री टर्म बर्थ' बढ़ रहे हैं। देखें तो विश्व में हर दो सेकंड में एक नवजात का समय से पहले जन्म हो रहा है। और हर 40 सेकंड में इनमें से एक की मौत हो रही है। इस गंभीर समस्या को फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता सामने लाए हैं। शोध के निष्कर्ष 'साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट' में प्रकाशित हुए हैं। नवजात शिशुओं का समय से पहले मां के गर्भ से बाहर आना जलवायु परिवर्तन के कारण माना जा रहा है।

जलवायु में आ रहे ऐसे बदलाव का सीधे तौर पर संबंध बच्चों की सेहत से जुड़ा है। तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होने से न केवल प्री टर्म बर्थ हो रहे हैं, बल्कि शिशुओं की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसी ही शोध जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के शोधकर्ताओं ने 29 निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर किए। एक शोध के अनुसार, चार प्रतिशत से अधिक नवजातों की मृत्यु जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले अधिकतम और न्यूनतम तापमान से जुड़ी है। ये निष्कर्ष 'नेचर कम्युनिकेशन' पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पिछले 18 वर्षों में एक लाख 75 हजार नवजातों की मौत उन 29 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में चार फीसद में से औसतन 1.5 फीसद सालाना नवजात मौतें अत्यधिक तापमान से जुड़ी थीं। वहीं करीब तीन फीसद अत्यधिक ठंड से हुई थीं। इसके अलावा, 18 वर्ष की इस अवधि में नवजात शिशुओं में गर्मी से जुड़ी 32 फीसद मौतों के लिए जलवायु परिवर्तन जवाबदेह है। इसका मतलब है कि इस दौरान नवजात शिशुओं की गर्मी से जुड़ी कुल मौतों में से 1 लाख 75 हजार से अधिक मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण मानी जा रही हैं। शोध के आंकड़ों के अनुसार, पहले नवजात शिशुओं का जलवायु परिवर्तन की वजह से 2001 से 2019 के दौरान औसत सालाना तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा नवजात शिशुओं की

शरीर तापमान नियंत्रण की क्षमता अधूरी होती है। उनका शरीर गर्मी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं होता। उच्च चयापचय और पसीने की दर कम होने से उन्हें शरीर से अतिरिक्त गर्मी को निकालना कठिन हो जाता है। तीसरी स्थिति में शोधकर्ताओं का मानना है कि उप-सहारा अफ्रीकी देशों में अत्यधिक तापमान की वजह से नवजात शिशुओं की मौतों पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक असर देखा गया है। चौथी स्थिति में पाकिस्तान, माली, सिएरा लियोन और नाइजीरिया में तापमान से जुड़ी नवजात शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थीं। इनमें एक लाख जीवित जन्मों में से 160 से अधिक मौत बढ़े हुए तापमान से हुईं। 2019 में विश्व भर में 24 लाख नवजात शिशु मौतें हुईं। इनमें से 90 फीसद से अधिक नवजात मृत्यु निम्न और मध्यम आय वाले देशों विशेषकर उपसहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हुईं। मौसम परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, पर उस परिवर्तन में हम तेजी से बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। मनुष्य की इच्छाएं तेजी से बढ़ रही हैं और परिवर्तित भी हो रही हैं। इस परिवर्तन में तेजी लाने का कारण हमारी तकनीकी सहायक हो रही हैं। तकनीकी का विकास मानव मस्तिष्क की खोजी प्रवृति है। इस खोज में हम भूल रहे हैं कि प्रकृति का दोहन एकदम नहीं, बल्कि धीरे-धीरे करना होगा।

वैज्ञानिक उपलब्धियों से तो हम दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में प्रकृति के साथ संतुलन भी करना होगा। हम इस अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर वनस्पतियों और वृक्षों का संतुलित अनुपात में होना आवश्यक है। वन धरती की प्यास बुझाते हैं, लेकिन वनों की हमने कटाई इस तरह से कर दी है कि कार्बन डाइआक्साइड और आक्सीजन का संतुलन ही हम मिटाने पर तुले हैं। मानसून पर ही यदि हम एक दृष्टि डालें, तो पता चलेगा जिन पर्वतों पर वृक्ष और वन होते थे, वे समाप्ति की ओर हैं। पहाड़ों के बड़े वृक्ष भूमि का कटाव नहीं होने देते थे। उनकी जड़ें मजबूती से पहाड़ों की मिट्टी में धंसकर वर्षा के जल को एकदम मैदानों की तरफ नहीं आने देती थीं, जिसकी वजह से नदियों में जलस्तर एक ही बरसात से खतरे से ऊपर नहीं होता था। वह स्थिति आज नहीं रही है। वनों से ऐसे पेड़, जो मैदानी भागों की सुरक्षा कवच का काम करते थे, कट चुके हैं। संतुलित वातावरण कहीं पर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण जिन नवजात पर मृत्यु का कहर ढह रहा है, उसको रोक पाने में हम अक्षम हैं। सरकार कोई भी आए और जाए, जब तक नियोजित विकास का रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक प्राकृतिक आपदाएं मुंह बाये खड़ी रहेंगी।

प्रभु का चिंतन **संत राजिन्दर**

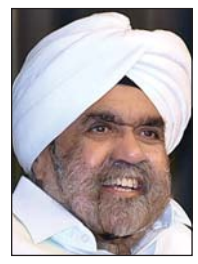

दुनियाभर में सभी लोग किसी न किसी रूप में पिता-परमेश्वर की पूजा करते हैं। हर धर्म की अपनी-अपनी उपासना पद्धति होती है, हालांकि सभी का मूल उद्देश्य केवल प्रभु का ध्यान करना है। अधिकांश लोग यह दिखाते हैं कि वे पूजा के स्थान पर सेवाओं में भाग लेकर पिता-परमेश्वर को याद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। विभिन्न धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रभु को पाने का मार्ग सिर्फ इंसान के अंदर जाकर ही मिलता है, जिसके लिए हमें अपने शरीर और मन को शांत करना पड़ता है। प्रभु का अनुभव हम ध्यान-अभ्यास के जरिए कर सकते हैं। ध्यान-अभ्यास करते समय हमें बाहर से ध्यान हटाने की जरूरत है। पिता-परमेश्वर आनंद, चेतनता और प्रेम के महासागर हैं। प्रेम, आनंद और चेतनता के इस महासागर के साथ हमारा मिलन तब होता है, जब हम ध्यान-अभ्यास में बैठते हैं और अपने अंतर में प्रभु के साथ बात करते हैं। ध्यान-अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह ढूंढकर हम आराम से बैठते हैं, जिसमें हम ज्यादा देर तक स्थिर रह सकें। हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान दो भौहों के बीच 'शिवनेत्र' पर एकाग्र करते हैं, जिसे तीसरी आंख या दिव्य-चक्षु भी कहा जाता है। मन को स्थिर रखने के लिए हम प्रभु के नामों का जाप करते हैं। ध्यान-अभ्यास की इस कला को हम वक्त के किसी पूर्ण गुरु से सीख सकते हैं, जो हमें हमारे भीतर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराते हैं। तभी हम अपने अंतर आध्यात्मिक यात्रा करके प्रभु के अंतरीय मंडलों का पता लगा सकते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हम शिक्षक के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें आध्यात्मिक विद्या में निपुण होना है तो हमें किसी पूर्ण गुरु के चरण-कमलों में जाना ही होगा। प्रभु के प्रति सच्चा प्यार और चिंतन ध्यान-अभ्यास द्वारा प्रभु को पाना है। प्रति दिन ध्यान-अभ्यास में समय देने से हमें अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा के बारे में जानने में मदद मिलती है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर प्रभु का प्रकाश ही प्रकाश है। उसके बाद ही हमें यह अनुभव होता है कि प्रभु का जो प्रकाश हमारे अंदर है, वही दूसरों में भी है तो हमें दूसरे कोई और नहीं, अपने ही लगते हैं।

रीडर्स मेल

कुपोषण गंभीर चिंता

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा भारत सहित पूरे विश्व में भूख, कुपोषण एवं बाल स्वास्थ्य पर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई है। कुपोषण और भुखमरी से जुड़ी वैश्विक रिपोर्टें न केवल चौंकाने, बल्कि सरकारों की नाकामी को उजागर करने वाली ही होती हैं। इस विवशता को कब तक ढोते रहेंगे और कब तक दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा, यह गंभीर स्थिति है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़ा हुआ ही निकलता है। आहार की गुणवत्ता को किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन के सभी स्रोतों के संदर्भ में देखना जरूरी है। चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया गया भोजन हो, मिड-डे मील या आइसीडीएस या देश के बाजारों में उपलब्ध खाद्य पदार्थ हो, वर्तमान चुनौती उच्च अनाज और कम प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की है।

ललित गर्ग, दिल्ली

असम में अच्छा फैसला

हाल में असम सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को माता-पिता या सास ससुर के साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रत्येक नवम्बर महीने में 2 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की। भारत की जिला अदालतें तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभिन्न माता पिता द्वारा अपने बच्चों के खिलाफ विभिन्न तरह की रीत या शिकायत दाखिल की जा रही है। ऐसे में असम सरकार द्वारा उठ गया यह कदम सराहनीय है। इस प्रकार से सरकारी तंत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी महिला-पुरुष सभी के लिए माता-पिता तथा सास-ससुर के लिए 2 दिन का स्पेशल अवकाश देने की घोषणा की है, उससे माता-पिता तथा सास-ससुर आपस में मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे और उसके साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस तरह की नीति का पालन भी होगा। असम सरकार से अन्य और भी राज्य इस बात के लिए प्रेरित होंगे।

मीना धानिया, ई मेल से

मुस्लिम महिलाओं के हित में

मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है। तलाक के बाद बनी विषम परिस्थितियां उस समय और भी जटिल बन जाती हैं, जब महिला कम पढ़ी-लिखी और आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर नहीं होती। एक विशेष समुदाय वर्ग में विवाह के उपरांत केवल अपनी नापसंद और अन्य छोटे-मोटे कारणों के आधार पर किसी महिला को तलाक तो दे दिया जाता है परंतु तलाकशुदा महिला के हालात पर हमारे समाज द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे कुछ मामलों में तलाक के बाद महिलाओं का जीवन नरक समान बन जाता है। शीर्ष अदालत के ताजा फैसले से उम्मीद की किरण जरूर जगी है। फैसले से महिला सशक्तिकरण को तो बल मिलेगा ही साथ ही साथ हर जाति, धर्म-संप्रदाय की महिलाओं को बराबरी से जीने का हक भी मिलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विवाह के पश्चात महिलाओं को मामूली वजह से तलाक देने के मामलों में भी गिरावट आएगी।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 329

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी

भारत में बेरोजगारी को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसका आधार यह है कि संगठित क्षेत्र में नौकरियों की कमी हो रही है। संगठित क्षेत्र के आंकड़े आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं परन्तु असंगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े इकट्ठे करना सरल काम नहीं होता क्योंकि भारत की लगभग 90 प्रतिशत अर्थव्यवस्था यही क्षेत्र थामे हुए है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दारोमदार इसी क्षेत्र पर है। भारत सरकार के सांख्यिकी व कार्यक्रम नियोजन मन्त्रालय ने 2015-16 के बाद पहली बार जो आंकड़े जारी किये हैं उनके अनुसार पिछले सात वर्षों में गैर संगठित क्षेत्र में 16 लाख 45 हजार नौकरियों का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा कोई बहुत आंकड़ा नहीं है मगर इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था की जमीनी हालत क्या है। इससे यह भी अंदाजा लग सकता है कि देश के औसत आदमी की क्रय क्षमता या औसत आय की स्थिति क्या होगी क्योंकि जब नौकरियां ही घट रही हैं तो आम आदमी की औसत आय कैसे बढ़ सकती है। 16.45 लाख नौकरियां क्यों समाप्त हुई। इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि 2016 में हुई नोटबन्दी का असंगठित क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा। इस क्षेत्र में अधिकतम कारोबार नकद रोकड़ा में ही होता था।

नकद रोकड़ा की कमी से छोटे उद्योग-धंधों पर बहुत असर पड़ा। उसके बाद 2017 में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू कर दिया गया। इसका भी छोटे उद्योग-धंधों पर बुरा असर पड़ा। तदोपरान्त कोरोना का कहर 2020 में आ गया जिसकी वजह से रही-सही कसर पूरी हो गई क्योंकि कोरोनाकाल में तो लॉक डाऊन की वजह से उद्योग-धंधे बन्द ही कर दिये गये थे। इन आंकड़ों में बताया गया है कि 2015-16 में जहां असंगठित उत्पादन इकाइयों की संख्या 6.33 करोड़ थी वहीं 2022-23 में बढ़कर यह 6.50 करोड़ हो गई। अर्थात इनकी संख्या में 15 लाख 56 हजार का इजाफा हुआ मगर नौकरियां भी लगभग इतनी ही घट गईं। इसका मतलब यही निकलता है कि उद्योग इकाइयों की संख्या बढ़ जाने से जहां रोजगार में इजाफा होना चाहिए वहीं इसमें उल्टे कमी आ गई। यह सब नोटबन्दी, जीएसटी व कोरोना की वजह से हुआ। जिन राज्यों में नौकरियां घटी उनमें उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व बिहार शामिल हैं। इन पांच राज्यों में 2015-16 में कुल छोटी इकाइयां छह करोड़ 34 लाख थीं जिनमें 11 करोड़ 33 लाख लोग रोजगार पाते थे। परन्तु 2022-23 में इन इकाइयों की संख्या बढ़कर छह करोड़ पचास लाख हो गई मगर रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या घटकर दस करोड़ 96 लाख ही रह गई।

> **भारत के कुल दस राज्य ऐसे हैं जिनमें कुल इकाइयों की तीन चौथाई छोटी इकाइयां लगी हुई हैं। इन पांच राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा हैं। वैसे इन राज्यों का औसत ठीक रहा। मूल प्रश्न यह है कि नकद रोकड़ा की कमी हो जाने के असर से छोटे उद्योगों पर विपरीत असर पड़ा और जीएसटी लागू होने का प्रभाव भी इन्हीं इकाइयों पर पड़ा जबकि कोरोना ने तो इनकी कमर ही तोड़ डाली। परन्तु छोटी इकाइयों की संख्या में वृद्धि बताती है कि स्वरोजगार स्थापित करने में ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह रहा है मगर नकद रोकड़ा की कमी होने व जीएसटी का फन्दा लटके होने से इनके कारोबार मन्दे होते चले गये।**

भारत के कुल दस राज्य ऐसे हैं जिनमें कुल इकाइयों की तीन चौथाई छोटी इकाइयां लगी हुई हैं। इन पांच राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा हैं। वैसे इन राज्यों का औसत ठीक रहा। मूल प्रश्न यह है कि नकद रोकड़ा की कमी हो जाने के असर से छोटे उद्योगों पर विपरीत असर पड़ा और जीएसटी लागू होने का प्रभाव भी इन्हीं इकाइयों पर पड़ा जबकि कोरोना ने तो इनकी कमर ही तोड़ डाली। परन्तु छोटी इकाइयों की संख्या में वृद्धि बताती है कि स्वरोजगार स्थापित करने में ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह रहा है मगर नकद रोकड़ा की कमी होने व जीएसटी का फन्दा लटके होने से इनके कारोबार मन्दे होते चले गये। कोरोना में यह और भी मन्दा पड़ गया। कोरोनाकाल में केन्द्र सरकार ने छोटी इकाइयों को भी वित्तीय मदद देने की स्कीम जारी की मगर वह ऋण रूप में ही थी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए बैंकों से इन इकाइयों को ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई मगर इसके प्रति इनके मालिकों में उत्साह नहीं देखा गया। कोरोनाकाल में छोटी इकाइयों को अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लाले पड़ते सुने गये। कोरोना के बाद ऐसी छोटी इकाइयों की कमर इस हद तक टूट चुकी थी कि इनके पास बैंक से लिए गये कर्जों की किश्तें चुकाने तक के पैसे नहीं थे। कोरोना के बाद जो कर्मचारी बहाल किये गये उनके वेतन में कटौती करनी पड़ी। परन्तु इसके बाद भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बीते वित्त वर्ष 2023-24 में ठहराव आया लगता है क्योंकि इस दौरान सकल विकास वृद्धि दर सन्तोषजनक स्तर पर रही है। मगर यह तथ्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नोटबन्दी व जीएसटी का सबसे बुरा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थात असंगठित क्षेत्र पर ही पड़ा जबकि सर्वाधिक रोजगार यही क्षेत्र प्रदान करता है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

और नेताओं की खोखली...

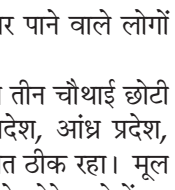

गीता पाढा

भरुच के उस दृश्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया,
बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे से अवगत करा दिया,
उन पढ़ें-लिखे लाखों बेरोजगार युवक-युवतियों की मजबूरियों ने रुला दिया,
और नेताओं की खोखली बयानबाजियों से पर्दा उठा दिया...!!

चुनावी बॉण्ड योजना : अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा न्यायालय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने को लेकर सहमति जताई, जिसमें चुनावी बॉण्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है।

- पीठ ने दोनों एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की इन दलीलों का संज्ञान लिया

गैर सरकारी संगठनों 'कॉमन कॉज' और 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका में राजनीतिक दलों, कंपनियों और जांच एजेंसियों के बीच स्पष्ट लेन-देन का आरोप लगाया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोनों एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि पिछले कुछ महीनों में वह उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, इसके बावजूद याचिकाएं अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''कृपया एक ईमेल भेजें।'' इस पर भूषण ने कहा कि उन्होंने ईमेल भी भेजे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा-आज फिर भेजें। इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। चुनावी बॉण्ड योजना को एक घोटाला करार देते हुए याचिका में मुखौटा और घाटे में चल रही उन कंपनियों के वित्तपोषण के स्रोत की जांच का अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

संसद सत्र क्यों छोटा होता जा रहा है ?

राकेश कपूर

संसद से सड़क तक

kapurakesh@gmail.com

1953 में जब स्वतन्त्र भारत की पहली लोकसभा में इसके तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष की मंशा साफ थी कि अध्यक्ष महोदय पक्षपात कर रहे हैं परन्तु यह भी स्पष्ट था कि श्री मावलंकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के बावजूद विपक्ष को लोकसभा के भीतर अपनी बात कहने का पूरा मौका दे रहे थे और यह मानते थे कि संसद पर पहला अधिकार विपक्ष का ही होता है। परन्तु वह दौर स्वतन्त्रता सेनानियों का दौर था।

लोकसभा में अधिसंख्य सदस्य वही थे जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए निजी स्वार्थ की कुर्बानियां दी थीं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा भेद नहीं था। केवल कुछ सांसद ही ऐसे थे जिन्होंने इस महायज्ञ में आहुति नहीं डाली थी। ऐसी पृष्ठभूमि में ही स्व. मावलंकर ने यह स्वयं स्वीकार किया था कि भारत में ऐसा समय भी आ सकता है जब अध्यक्ष पद पर बाहर से किसी निष्पक्ष व्यक्ति को बैठाने की मांग की जाये। लाख विसंगतियों के चलते अभी भारत में ऐसी मांग किसी भी तरफ से नहीं हुई है। मगर इसके विपरीत जिस तरह संसद के चलने की अवधि लगातार छोटी होती जा रही है उससे दुनिया के सबसे बड़े संसदीय लोकतन्त्र कहे जाने वाले भारत में संसद की भूमिका को लेकर चिन्ता अवश्य हो सकती है।

1952 में गठित पहली संसद में लोकसभा साल में कुल 135 दिन चली थी। राज्यसभा भी 90 दिन से ऊपर ही चली थी। दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी यही परंपरा निभाई गई। मगर धीरे-धीरे इसमें कमी आती गई और 1971 के बाद से संसद का सत्र लगातार छोटा होता चला गया तथा 90 के दशक में 70 दिनों तक पहुंच गया। यह परंपरा भी 2014 तक चलती रही परन्तु वर्तमान में यह 55 दिनों तक सिमट गया। दुनिया के सभी खुले लोकतान्त्रिक देशों की संसद के सत्रों की तुलना में यह समयावधि बहुत कम आंकी जाती है। इसका क्या कारण है? क्या विपक्ष का हो-हल्ला इसका कारण हो सकता है? यदि ऐसा है तो क्या विपक्ष संसद में केवल सत्तापक्ष की हां में हां मिलाने के लिए बैठा हुआ होता है? जाहिर है कि ऐसा नहीं है क्योंकि लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका बहुत संजीदा होती है।

विपक्ष का नेता छाया प्रधानमन्त्री होता है और वह अपने विमर्श में वैकल्पिक नीतियों की वकालत करता है। जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना सत्तारूढ़ दल का विशेषाधिकार होता है। विपक्ष की इसलिए आलोचना नहीं की जा सकती कि वह संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालता है बल्कि इसलिए आलोचना की जा सकती है कि उसके पास कोई वैकल्पिक विचार नहीं है। लोकतन्त्र में विपक्ष का धर्म सत्ता पक्ष का विरोध (अंध विरोध नहीं) करना होता है और सरकारी नीतियों की खामियों को उजागर करना होता है और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे सत्ता से बेदखल करने का भी होता है। मुझे याद आता है कि जब 1977 में केन्द्र में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके विपक्ष की पंचमेल जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी तो विपक्ष के नेता लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से केरल के नेता श्री सी.एम. स्टीफन बनाये गये। श्री सी.एम. स्टीफन ने विपक्ष के नेता के तौर पर जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के हर मोर्चे पर छक्के छुड़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

यहां तक कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के मुद्दे पर जनता पार्टी में विलीन हुई जनसंघ के हिन्दुत्व को भी भारतीयता के रंग में जिस तरह परिभाषित किया उससे तत्कालीन सरकार के विदेश मन्त्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बाद में 1980 के लोकसभा चुनावों में इन दोनों दिग्गजों की दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर टक्कर भी हुई जिसमें श्री वाजपेयी बामुश्किल साढ़े तीन हजार वोटों से ही जीत पाये। श्री स्टीफन बेशक

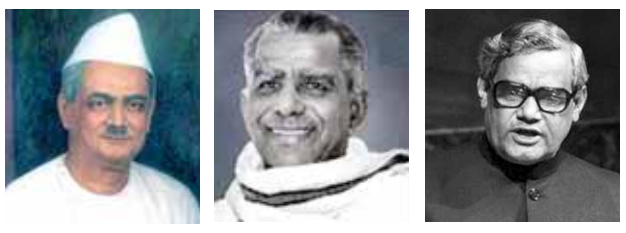

> **1977 में केन्द्र में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके विपक्ष की पंचमेल जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी तो विपक्ष के नेता लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से केरल के नेता श्री सी.एम. स्टीफन बनाये गये। श्री सी.एम. स्टीफन ने विपक्ष के नेता के तौर पर जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के हर मोर्चे पर छक्के छुड़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।**

पराजित हो गये थे मगर एक दक्षिण भारतीय इसाई होने के बावजूद उन्होंने उत्तर भारत के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कड़ी मुश्किल में डाल दिया था। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के नेता का रुतबा किसी भी दृष्टि से कम करके आंकना स्वयं सत्ताधारी दल के लिए ही हानिकारक होता है। इस चुनौती का सामना संसद चलने की समयावधि घटा कर नहीं किया जा सकता है।

संसद ही चुने हुए प्रतिनिधियों की योग्यता की पहचान कराती है और बताती है कि जनता ने अपने जो नुमाइन्दें लोकसभा में भेजे हैं उनमें से प्रत्येक की योग्यता देश को चलाने की होनी चाहिए। भारत में प्रधानमन्त्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है बल्कि संसद में पहुंचे हुए प्रतिनिधि करते हैं। लोकसभा में बहुमत में पहुंचे दल के प्रतिनिधि जिस सांसद को अपना नेता चुनते हैं वही प्रधानमन्त्री बनता है। मगर हम देख रहे हैं कि संसद की अवधि 55 दिनों की रह जाने के बावजूद सरकारी विधेयकों की संख्या में कोई कमी दर्ज नहीं हो रही है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि संसद में अधिसंख्य विधेयक बिना समुचित चर्चा के ही पारित हो रहे हैं।

संसदीय प्रणाली की यह सबसे बड़ी विसंगति है। स्व. प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में विधेयकों पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति के गठन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि विधेयक पर समिति में सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सके। समिति में संसद में मौजूद सभी प्रमुख राजनैतिक दलों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। इसमें विधेयक पर सर्वसम्मति बना कर ही संसद को भेजा जाता है। समिति में मतदान कराने की प्रथा नहीं होती। असहमति रखने वाला सांसद अपनी पृथक टिप्पणी दर्ज करा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का संविधान स्वयं है।

संविधान सभा में विभिन्न दलों के नेता शामिल थे। इसमें जनसंघ के डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और समाजवादी शइब्बन लाल सक्सेना भी थे। साथ ही कई रियासतों के राजे-रजवाड़े भी थे। संविधान सभा ने नियम बनाया कि वह किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं करायेगी बल्कि सर्वसम्मति से ही सभी पक्षों के विचारों को लेकर अंतिम फैसले पर पहुंचेगी। हम जो आज भारत का संविधान देख रहे हैं वह सर्वसम्मति से बना हुआ दस्तावेज ही है। मगर हमारी संसद में विशिष्ट विषयों पर मत विभाजन के प्रावधान हैं। मगर हमें ध्यान रखना होगा कि 80 के दशक में दल-बदल कानून के बन जाने के बाद हर दल के सांसदों के सामने अपनी पार्टी का व्हिप (निर्देश) मानने की मजबूरी भी है।

इसके चलते सांसद अपनी अन्तर्आत्मा के अनुसार मतदान नहीं कर सकते हैं। पार्टी अनुशासन मानना उनकी मजबूरी होती है। इस बारे में अलग से बहस हो सकती है कि दल बदल कानून लोकतंत्रीय आजादी के मार्ग में कितना बड़ा अवरोध है। इसके बावजूद यदि संसद की अवधि घटती रहती है तो इसका अर्थ यही निकलता है कि हम अपने लोकतान्त्रिक दायित्व से भाग रहे हैं और विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जबकि लोकतन्त्र में विपक्ष का दावा सत्ता के हर क्षेत्र में बराबर का होता है क्योंकि विपक्षी सांसदों का चुनाव भी लोकतन्त्र की असली मालिक जनता ही करती है। विचार विनिमय लोकतन्त्र की असली मुद्रा होती है। यदि संसद में इसकी गुंजाइश ही खत्म कर दी जायेगी तो संसदीय लोकतन्त्र की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लगने लगेंगे और जनता सोचने पर मजबूर होगी कि वे जिन प्रतिनिधियों को चुन कर संसद में भेजते हैं उनकी उपयोगिता आखिरकार क्या है?

उपचुनाव लड़कर मायावती दे रही नये संकेत

ताक-झांक

आर.आर. जैरथ

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मायावती उत्तर प्रदेश में आगामी दस विधानसभा उपचुनावों में बसपा के लड़ने की संभावना पर गंभीरता से

विचार कर रही हैं। बसपा नीतिगत तौर पर कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है। इसलिए अगर वह चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो यह पिछली परंपरा से एक बड़ा बदलाव होगा। दस विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के लोकसभा में चुने जाने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

ऐसा लगता है कि उपचुनावों को लेकर मायावती का मन परिवर्तन हाल के आम चुनावों में लगभग खत्म हो जाने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उनकी घबराहट से उपजा है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक स्थिति का जायजा लें और देखें कि आज बीएसपी कहां खड़ी है। पार्टी ने एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती और यूपी में उसका वोट शेयर 9% से थोड़ा कम रह गया। उनके भतीजे आकाश आनंद को चुनाव का प्रभारी बनाया जा सकता है। उन्हें हाल ही में बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की आलोचना करने के कारण अचानक उन्हें पद से हटा देने से यूपी के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया था।

आकाश आनंद अपने उग्र बीजेपी विरोधी भाषणों के लिए प्रचार अभियान के दौरान चर्चा में रहे थे, जिसमें दलितों ने कहा था कि वे उन्हें छोटी मायावती की याद दिलाते हैं। बीएसपी प्रमुख को उम्मीद है कि उनका भतीजा पार्टी की किस्मत को फिर से चमका सकता है। सत्ताधारी बीजेपी भी यही चाहती है क्योंकि बीएसपी वोट काटने में मददगार रही है। अतीत में, मायावती की पार्टी ने मुस्लिम वोटों को सफलतापूर्वक विभाजित किया है और बीजेपी को उन सीटों पर जीत दिलाने में मदद की है जहां अल्पसंख्यक आबादी के पास नतीजों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संख्या है।

ब्रिटेन के लोकतंत्र से सबक ले भारत

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

शपथ ग्रहण के नियमों में संशोधन किया है, ताकि सांसदों को स्वीकृत प्रारूप में कुछ जोड़ने से रोका जा सके। उन्होंने ऐसा तब किया, जब राहुल गांधी और शशि थरूर सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने अपनी शपथ में जय संविधान और एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन जोड़ा।

इसके ठीक विपरीत, ब्रिटेन में, जहां से हमने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली उधार ली है, वहां की नई संसद में कई सांसदों ने पद की शपथ लेते समय स्क्रिप्ट से पूरी तरह अलग हटकर शपथ ली। वास्तव में, उन्होंने शपथ का उपयोग राजनीतिक विरोध दर्ज करने और अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए किया। उदाहरण के लिए, सोशल एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉलिन ईस्टवुड ने कहा कि वह विरोध के तहत निष्ठा की शपथ ले रहे हैं, क्योंकि उनकी सच्ची निष्ठा आयरलैंड (ब्रिटेन नहीं) के लोगों के प्रति है। उनकी साथी पार्टी सदस्य क्लेयर हैना ने भी नियमों के अनुसार अंग्रेजी के बजाय आयरिश में शपथ लेकर स्क्रिप्ट से अलग हटकर शपथ ली और फिर आयरलैंड के बेलफास्ट के लोगों के प्रति निष्ठा की शपथ ली। भारत के विपरीत, किसी ने भी विरोध के इन इशारों पर आपत्ति नहीं जताई, न तो स्पीकर ने और न ही पार्टी नेताओं ने। कुछ बयानों को क्राउन और ईश्वर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की परंपरा

को चुनौती या गैर-धार्मिक प्रतिज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र कितना परिपक्व और उदार है। विडंबना यह है कि हमारे सांसदों ने विरोध का कोई इशारा भी नहीं किया। वे शपथ लेते समय केवल संविधान को सलाम कर रहे थे।

अंतरिक्ष की मानव उड़ान का नया युग

फोर्ट कॉलिंस, (द कन्वरसेशन): ऐसे लोगों की संख्या लगभग 600 है, जिन्होंने कभी अंतरिक्ष की यात्रा की है। पिछले छह दशकों में अधिकांश अंतरिक्ष यात्री मध्यम आयु वर्ग के पुरुष रहे हैं जो 20 दिनों से कम अवधि के मिशन पर गए थे। आज, निजी, वाणिज्यिक और बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान प्रदाताओं और यात्रियों के बाजार में प्रवेश के साथ, हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का एक नया युग देख रहे हैं। मिशन मिनटों, घंटों और दिनों से लेकर महीनों तक के होते हैं।

जैसा कि मानवता आने वाले दशक में चंद्रमा पर फिर जाने की उम्मीद कर रही है, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन बहुत लंबे होंगे, जिसमें कई अधिक अंतरिक्ष यात्री और यहां तक कि अंतरिक्ष पर्यटक भी होंगे। इसका मतलब यह भी है कि व्यापक विविधता वाले लोग अंतरिक्ष के चरम वातावरण का अनुभव करेंगे- अधिक महिलाएं और विभिन्न जातीयता, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के लोग। चूंकि लोग अंतरिक्ष के अनूठे तनावों और जोखिमों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए मेरे जैसे अंतरिक्ष स्वास्थ्य के शोधकर्ता, अंतरिक्ष उड़ान के मानव स्वास्थ्य प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी से, हम यह पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने के दौरान और पृथ्वी पर लौटने के बाद स्वस्थ रहने में कैसे मदद की जाए।

ऐतिहासिक नासा ट्विन्स अध्ययन के एक भाग के रूप में, 2019 में, मेरे सहयोगियों और मैंने इस पर अभूतपूर्व शोध प्रकाशित किया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक वर्ष बिताने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के पर्यावरण और रेडियोलॉजिकल स्वास्थ्य विज्ञान विभाग में एक विकिरण कैंसर जीवविज्ञानी हूं। मैंने नेचर पत्रिकाओं के पोर्टफोलियो में हाल ही में प्रकाशित पत्रों की एक श्रृंखला में उस पहले के शोध को जारी रखने में कुछ साल बिताए हैं।

ये पेपर पांडुलिपियों, डेटा, प्रोटोकॉल और रिपॉजिटरी के स्पेस ओमिक्स और मेडिकल एटलस पैकेज का हिस्सा हैं जो एयरोस्पेस मेडिसिन और स्पेस बायोलॉजी के लिए अब तक इकट्ठे किए गए सबसे बड़े संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25 देशों के 100 से अधिक संस्थानों ने अंतरिक्ष उड़ान डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला के समन्वित रिलीज में योगदान दिया।

नासा ने अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली को एजेंसी के पहले एक साल के मिशन के लिए चुना, जिसके दौरान उन्होंने 2015 से 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक साल बिताया। उसी समय अवधि में, उनके समान जुड़वां भाई, मार्क केली, एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान एरिजोना का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी सीनेटर पृथ्वी पर ही रहे।

मेरी टीम और मैंने अंतरिक्ष में जुड़वां बच्चे से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की जांच की और अंतरिक्ष उड़ान से पहले, उसके दौरान और बाद में पृथ्वी पर उसके आनुवंशिक रूप से मेल खाने वाले जुड़वां की जांच की। हमने पाया कि स्कॉट के टेलोमेरेस-गुणसूत्रों के सिरों पर सुरक्षात्मक टोपी, प्लास्टिक की नोक की तरह जो जूते के फीते को फटने से बचाती है - अंतरिक्ष में उसके रहने के दौरान, काफी अप्रत्याशित रूप से लंबे हो गए। हालांकि, जब स्कॉट पृथ्वी पर लौटे, तो उनके टेलोमेरेस जल्दी ही छोटे हो गए। अगले महीनों में, उनके टेलोमेरेस ठीक हो गए, लेकिन अंतरिक्ष में जाने से पहले की तुलना में उनकी यात्रा के बाद भी वे छोटे थे। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तनाव सहित कई कारकों के कारण आपके टेलोमेरेस छोटे हो जाते हैं। आपके टेलोमेरेस की लंबाई उम्र से संबंधित स्थितियों जैसे मनोभ्रंश,

हृदय रोग और कैंसर के विकास के लिए आपके जोखिम के जैविक संकेतक के रूप में काम कर सकती है।

एक अलग अध्ययन में, मेरी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर छह महीने के मिशन पर 10 अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह का अध्ययन किया। हमारे पास आयु और लिंग-मिलान प्रतिभागियों का एक नियंत्रण समूह भी था जो जमीन पर रुके रहे। हमने अंतरिक्ष उड़ान से पहले, उसके दौरान और बाद में टेलोमेरेस की लंबाई मापी और फिर पाया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान टेलोमेरेस लंबे थे और फिर पृथ्वी पर लौटने पर छोटे हो गए। कुल मिलाकर, अंतरिक्ष उड़ान के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के टेलोमेर पहले की तुलना में अधिक छोटे थे। अन्य जुड़वां अध्ययन जांचकर्ताओं में से एक, क्रिस्टोफर मेसन, और मैंने टेलोमेरेस से जुड़ा एक और अध्ययन किया। इस बार जुड़वां टेलोमेर छोटे हो गए। उनके जुड़वाँ जो कम ऊंचाई पर रहे, उन्हें टेलोमेर की लंबाई में समान बदलाव का अनुभव नहीं हुआ। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि यह अंतरिक्ष स्टेशन की माइक्रोग्रैविटी नहीं है जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों में टेलोमेर की लंबाई में बदलाव देखा गया -अन्य कारक, जैसे कि विकिरण जोखिम में वृद्धि के इसके लिए जिम्मेदार होने की अधिक संभावना है।

उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहियों के साथ पृथ्वी पर कुछ हद तक समान चरम वातावरण।

हमने पाया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों के टेलोमेर लंबे थे, और नीचे उतरने के बाद उनके

हमारे नवीनतम अध्ययन में, हमने स्पेसएक्स के 2021 इंस्पिरेशन 4 मिशन पर चालक दल के टेलोमेरेस का अध्ययन किया। इस मिशन में पहला सर्व-नागरिक दल था, जिनकी आयु चार दशकों तक फैली हुई थी। मिशन के दौरान चालक दल के सभी सदस्यों के टेलोमेर लंबे हो गए, और पृथ्वी पर वापस आने के बाद चार अंतरिक्ष यात्रियों में से तीन के टेलोमेर छोटे हो गए। निष्कर्षों के बारे में विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि इंस्पिरेशन4 मिशन केवल तीन दिनों तक चला। इसलिए, वैज्ञानिकों के पास अब न केवल अंतरिक्ष उड़ान के प्रति टेलोमेर की प्रतिक्रिया पर सुसंगत और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य डेटा है, बल्कि हम यह भी जानते हैं कि यह जल्दी से होता है। इन परिणामों से पता चलता है कि अंतरिक्ष में सप्ताहांत की छुट्टी जैसी छोटी यात्राएं भी टेलोमेर की लंबाई में बदलाव से जुड़ी होंगी।

वैज्ञानिक अभी भी टेलोमेर की लंबाई में इस तरह के बदलावों के स्वास्थ्य प्रभावों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हमें यह पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी कि लंबे और छोटे दोनों टेलोमेर किसी अंतरिक्ष यात्री के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 127

नाटो की परीक्षा

वॉशिंगटन में आयोजित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शिखर सम्मेलन में तीन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। परंतु वहां चीन का मुद्दा ही केंद्र में रहा। यह बात शिखर बैठक के बाद की गई घोषणा में भी नजर आई जहां चीन का अभूतपूर्व जिक्र देखने को मिला। नाटो के सभी 32 सदस्यों द्वारा स्वीकृत सामग्री में चीन को यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का 'निर्णायक ढंग से समर्थन देने वाला' बताया गया और चीन से यह मांग की गई कि वह रूस की सेना को हर प्रकार का भौतिक और राजनीतिक समर्थन देना बंद कर दे। इसमें चीन के परमाणु हथियारों और अंतरिक्ष में उसकी हमलावर क्षमता को लेकर भी चिंता जताई गई। 2019 के ऐसे ही वक्तव्य में चीन का जिक्र इतनी स्पष्ट भाषा में नहीं था। इससे एक तथ्य यह सामने आता है कि नाटो ने यूक्रेन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को और गहन करने का संकेत दे दिया है। शिखर बैठक आरंभ होने के साथ ही अमेरिका में बने एफ-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन को भेज दी गई और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इससे यूक्रेन को रूस के उन हवाई हमलों से बचाव करने में मदद मिलेगी जो हाल के समय में काफी सफल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 'यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए स्पष्ट और मजबूत सेतु' की बात की। परंतु यह नतीजा पहले शत्रुता के समाप्त होने पर निर्भर है।

वहां हो रहे भव्य रात्रि भोजों से इतर नाटो के सदस्य इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि गठबंधन और यूक्रेन का भविष्य काफी हद तक नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। गत माह पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में लड़खड़ाहट भरी शुरुआत के बाद ही बाइडन के स्वास्थ्य का मुद्दा एक तात्कालिक चिंता में परिवर्तित हो गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि शिखर बैठक में बिना टेलीप्रॉम्पटर के अपने भाषण को कामयाबी के साथ पढ़ लेने की बात ने नाटो के उनके सहयोगियों को आश्वस्त किया होगा या नहीं। हालांकि लगता है कि वह अपनी ही पार्टी के लोगों की चिंताओं को दूर नहीं कर पाए हैं। अगर बाइडन अपने अभियान को जारी रखते हैं तो वह अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डॉनल्ड ट्रंप की संभावनाओं को ही मजबूत करेंगे। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने नाटो गठबंधन में शामिल देशों की व्यय साझा करने की अनिच्छा की आलोचना की थी जो कि उचित ही थी। हालांकि तब से अब तक इसमें बदलाव आया है और अधिकांश सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद का दो फीसदी नॉटो पर खर्च करने के अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की पुतिन के साथ करीबी नॉटो-यूक्रेन संबंधों में एक अप्रत्याशित तत्त्व जोड़ सकती है। नाटो की घोषणा को लेकर चीन ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें उसने इसे स्पष्ट झूठ करार दिया है और जोर देकर कहा है कि रूस और चीन के बीच व्यापार किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता। परंतु घोषणा की स्पष्ट भाषा ने रूस-यूक्रेन युद्ध को नाटो-चीन के बीच के छद्म युद्ध में बदल दिया है। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब नाटो के सदस्य हंगरी और तुर्किए के रूस के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं। अब तक रूस को चीन की मदद में गहराई है लेकिन वह हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहा है। परंतु चीन की सेना अब नाटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमाओं पर रूस के साझेदार बेलारूस के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। ऐसे संयुक्त अभ्यास पहले भी हुए हैं लेकिन फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह पहली ऐसी कवायद है। नेतृत्व में बदलाव के इस अहम दौर में नाटो हालात से कैसे निपटता है यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी।

विनय सिन्हा

राजस्व बढ़ाने पर देना होगा ध्यान

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि वित्त वर्ष 25 के बजट में सरकार के समक्ष व्यय के मोर्चे पर सीमित विकल्प हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल में बजट का प्रदर्शन कैसा रहा? इस सवाल का एक जवाब यह होगा कि उनकी तुलना पिछली सरकारों के बजट से की जाए। परंतु एक अन्य तरीका यह भी होगा कि मोदी सरकार के बजट की आपस में ही तुलना की जाए। मौजूदा संदर्भ में ऐसा करना अधिक उपयोगी हो सकता है। चूंकि मोदी सरकार में आम चुनाव के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया है और यहां तक कि वित्त मंत्रालय में बजट बनाने वाली टीम भी कमोबेश पहले वाली है। ऐसे में यह जानना जानकारीपरक होगा कि पिछले 10 साल के बजट में बुनियादी राजकोषीय संचालन में क्या बदलाव आया है और कैसे ये 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के लिए संकेतक का काम कर सकते हैं।

शुरुआत करते हैं सरकार के आकार से। वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार का कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 13.34 फीसदी था। अगले चार साल में यानी 2018-19 तक इसे कम करके जीडीपी के 12.25 फीसदी तक लाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि यह कमी राजस्व व्यय में कमी करके की गई जबकि इन पांच साल में पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.5 से 1.8 फीसदी के बीच अपरिवर्तित रहा।

वर्ष 2019-20 में यानी कोविड के पूर्व वाले वर्ष और 2020-21 में यानी कोविड वाले वर्ष में सरकारी व्यय क्रमशः जीडीपी के क्रमशः 13.4 फीसदी और 17.7 फीसदी रहा और इस इजाफे को समझा जा सकता है। इसमें राजस्व व्यय में इजाफे और पूंजीगत व्यय में मामूली बढ़ोतरी का अहम योगदान था। परंतु जिस बात ने उम्मीद बंधाई वह यह थी कि सरकार ने अगले तीन साल के दौरान अपने कुल व्यय को जीडीपी के 15 फीसदी तक कम कर लिया। इस गिरावट में दो आश्वस्त करने वाली बातें थीं। सरकार का पूंजीगत व्यय तेजी से बढ़ा और वह 2020-21 में जीडीपी के 2.1 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में जीडीपी के 3.2 फीसदी तक हो गया। इससे ऐसे समय में वृद्धि को गति देने में मदद मिली जब निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाने की स्थिति में नहीं था। इसके साथ ही समान अवधि में राजस्व व्यय 15.5 फीसदी से कम होकर 11.8 फीसदी रह गया। यह एक सराहनीय उपलब्धि थी। न केवल सरकार का कुल व्यय कम हुआ बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। सीतारमण को 2024-25 का बजट बनाते समय जिस अहम सवाल से जूझना होगा वह यह है कि क्या सरकारी व्यय में और कमी की जा सकती है? आदर्श स्थिति में उन्हें राजस्व व्यय में तीव्र कटौती करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूंजीगत व्यय बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2024-25 के उनके अंतरिम बजट में जीडीपी के 3.4 फीसदी के बराबर पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव रखा गया था जबकि राजस्व व्यय के जीडीपी के 11.1 फीसदी रहने की बात कही गई थी। अगर पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.5 फीसदी तक बढ़ाना पड़े तो राजस्व व्यय को और अधिक झटका लगेगा जो शयद जीडीपी के 11 फीसदी तक कम हो जाएगा।

परंतु इसके बावजूद कई अहम चुनौतियां होंगी। इसके लिए सरकार की कई कल्याण योजनाओं में कटौती करनी होगी। इसमें सब्सिडी योजनाएं भी शामिल हैं। गत वर्ष सीतारमण ने कुल सब्सिडी बिल को कम करके जीडीपी के 1.5 फीसदी तक ला दिया था जबकि 2022-23 में यह जीडीपी के 2.4 फीसदी के बराबर थी। ऐसे में 2024-25 में सब्सिडी में और कटौती की संभावना कम है। वित्त मंत्री के समक्ष पहले ही पीएम किसान और मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाने की मांग है। गठबंधन की राजनीति की कीमत उन दो राज्यों में आवंटन बढ़ाने के रूप में चुकानी पड़ सकती है जहां के सत्ताधारी दल केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। रिजर्व बैंक के जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर के अतिरिक्त अधिशेष स्थानांतरण को ध्यान में रखने के बाद भी व्यय वृद्धि को रोकना बड़ी चुनौती होगी। ध्यान देने वाली बात यह हे कि 2023-24 का सरकार का राजकोषीय घाटा पहले ही जीडीपी के 5.6 फीसदी के बराबर है। अगर सीतारमण 2024-25 के लिए अंतरिम बजट के 5.1 फीसदी के लक्ष्य पर टिकी रहती हैं तो जीडीपी के आधे फीसदी के बराबर का राजकोषीय समेकन गत वर्ष हासिल लक्ष्य की तुलना में कम ही होगा। इसका अर्थ यह भी होगा कि उन्हें घाटे में कहीं अधिक कटौती करनी होगी ताकि वह 2025-26 के 4.5 फीसदी के लक्ष्य तक पहुंच सकें। इस वर्ष उन्हें रिजर्व बैंक के अधिशेष स्थानांतरण का लाभ मिलेगा जो शायद अगले वर्ष उपलब्ध न हो। ऐसे में समझदारी यही होगी कि इस वर्ष राजकोषीय घाटे को और कटौती के साथ जीडीपी के पांच फीसदी या 4.9 फीसदी किया जाए। तभी अगले वर्ष वित्त मंत्री की राह थोड़ी आसान हो जाए।

परंतु कल्याण योजनाओं के लिए उच्च व्यय मांग के साथ वित्त मंत्री के पास रास्ता भी क्या है? उनके पास बेहतर राजस्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केंद्र का शुद्ध कर राजस्व कोविड के असर के बाद धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह 2020-21 के जीडीपी के 7.2 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 7.88 फीसदी हो गया। इसके अलावा 2021-22 से ही कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो चुकी है। चिंताजनक संकेत यह है कि गैर कर राजस्व बीते चार साल से लगातार जीडीपी के 1.5 फीसदी से कम बना हुआ है और विनिवेश प्राप्तियों में न केवल बीते दो वर्षों से गिरावट आ रही है बल्कि इस बात को लेकर भी सवाल हैं कि इस वर्ष या अगले वर्ष विनिवेश को लेकर गंभीर प्रयास होंगे भी या नहीं?

इसके बावजूद लगता है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सीतारमण का पहला बजट राजस्व जुटाने पर अधिक निर्भर होगा। अगर कल्याण योजनाओं में आवंटन बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा तो राजस्व व्यय में और कटौती करना मुश्किल होगा। अगर राजकोषीय समेकन की गति मजबूत होती है और पूंजीगत व्यय में जरूरी इजाफे से समझौता नहीं किया जाता है तो वित्त मंत्री को ऐसे कदमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो गैर कर राजस्व जुटाने से संबंधित हों। इसके अलावा विनिवेश की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाने को लेकर भी काम करना होगा। ये सभी लक्ष्य किस प्रकार हासिल होंगे, यह बात दो सप्ताह बाद ही पता चल सकेगी।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बदलते आयाम

भारतीय बैंक अब तक के सबसे मजबूत दौर में हैं। बैंकिंग उद्योग की संपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में यह उद्योग के लिए सबसे अच्छा वक्त है। कुल फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) वित्त वर्ष 2024 में 12 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच कर 2.8 प्रतिशत हो गईं। फंसे कर्ज के लिए अलग से पूंजी प्रावधान के बाद शुद्ध एनपीए 0.6 फीसदी के ऐतिहासिक स्तर पर है।

पिछले दशक के अंतिम कुछ वर्षों में कुछ बैंकों की हालत बेहद नाजुक थी। इस क्षेत्र का इलाज डॉक्टर रघुराम राजन ने किया था और इनकी नियमित स्वास्थ्य जांच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में हो रही थी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए पुनर्पूंजीकरण कोष के रूप में सही खुराक दी और आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ऊर्जित पटेल ने बैंकों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजों और परहेज करने वाली चीजों के बारे में बताया।

अब हम इस पर विचार करते हैं कि मौजूदा दशक के पिछले चार वर्षों में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद स्थिति कैसे बदली है। मार्च 2020 में बैंकिंग तंत्र का सकल एनपीए 8.5 प्रतिशत (सितंबर 2019 में 9.3 प्रतिशत) और शुद्ध एनपीए 3 प्रतिशत था। वर्ष 2018 के मार्च महीने में सकल एनपीए 11.6 प्रतिशत था जबकि शुद्ध एनपीए 6.1 प्रतिशत था जो मौजूदा चरण में शीर्ष पर था।

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उद्योग, कृषि, सेवा और खुदरा क्षेत्र के लिए बैंकों के जोखिम का स्वरूप कैसे बदला है? मार्च 2020 में उद्योग को दिए गए ऋण में बैंकों का सकल एनपीए 14.2 प्रतिशत (सितंबर 2018 में 20.5 प्रतिशत से कम), कृषि ऋण 10.1 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र 7.2 प्रतिशत और खुदरा 2 प्रतिशत था।

अगर हम कुल संकटग्रस्त ऋण पर नजर डालें तो आंकड़े थोड़े अधिक थे। उद्योग के लिए यह 14.8 प्रतिशत, कृषि के लिए 10.3 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र के लिए 7.6 प्रतिशत और खुदरा के लिए 2.1 प्रतिशत था। संकटग्रस्त ऋण में वे ऋण शामिल होते हैं जिन्हें पहले से ही फंसी संपत्ति या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसमें अन्य ऋण भी शामिल होते हैं जिनकी फंसे कर्ज में तब्दील होने की अधिक संभावना होती है।

इस साल मार्च महीने में क्या स्थिति थी? कृषि क्षेत्र में फंसा कर्ज सबसे उच्च स्तर पर यानी 6.2 प्रतिशत के स्तर पर था और उद्योग दूसरे पायदान (3.5 प्रतिशत) पर था। इसके बाद सेवा क्षेत्र (2.7 प्रतिशत) और निजी ऋण (1.2 प्रतिशत) का स्थान है। संकटग्रस्त अग्रिम के लिहाज से देखें तो ये आंकड़े कृषि क्षेत्र के लिए 6.5 प्रतिशत, उद्योग के लिए 4.8 प्रतिशत, सेवाओं के लिए 3.8 प्रतिशत और निजी ऋण के लिए 2.1 प्रतिशत थे।

इसके साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि उद्योग के उप क्षेत्रों का प्रदर्शन कैसा रहा है? मार्च 2020 में रत्न एवं आभूषणों में सकल एनपीए सबसे ज्यादा करीब 24.8 प्रतिशत था और इसके बाद निर्माण क्षेत्र (24.3 प्रतिशत), इंजीनियरिंग (20 प्रतिशत), खनन एवं उत्खनन (19.8 प्रतिशत), बुनियादी धातु (16.2 प्रतिशत), खाद्य प्रसंस्करण (14.5 प्रतिशत), कागज और कागज से बने उत्पाद (13.6 प्रतिशत), बिजली (13.5 प्रतिशत) और बुनियादी ढांचा एवं कपड़े (प्रत्येक 13.1 प्रतिशत) का स्थान था।

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

जहां तक इन क्षेत्रों में बैंकों के निवेश की बात है तब हमने यह पाया कि बुनियादी ढांचा इस सूची में शीर्ष पर था जो उद्योग को दिए गए कुल ऋण (36.2 प्रतिशत) में से एक-तिहाई से अधिक था। इसके बाद बिजली (17.5 प्रतिशत) और बुनियादी धातु (11.3 प्रतिशत) का स्थान था। बाकी अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी एक अंक में थी।

इस साल मार्च में रत्न एवं आभूषणों में सकल एनपीए अधिकतम रहा लेकिन आंकड़ा नाटकीय रूप से 24.8 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गया। निर्माण क्षेत्र 6.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर, खाद्य प्रसंस्करण तीसरे (5.5 प्रतिशत), कपड़ा चौथे (5.2 प्रतिशत) और इंजीनियरिंग पांचवें (5 प्रतिशत) स्थान पर रहा। उद्योग के किसी भी उप-क्षेत्र में सकल एनपीए 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। दो अन्य क्षेत्र में सकल एनपीए 4 प्रतिशत से अधिक है और ये हैं बुनियादी ढांचा (बिजली को छोड़कर) और कागज एवं कागज उत्पाद। मार्च 2020 में बैंकिंग क्षेत्र के कुल ऋण में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी 51.23 प्रतिशत थी लेकिन सकल एनपीए में उनकी हिस्सेदारी 78.3 प्रतिशत थी। मार्च 2018 से दोनों में कमी देखी जा रही है। मार्च 2024 तक ऋण में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी घटकर 44.4 प्रतिशत और फंसे कर्ज की हिस्सेदारी कम होकर 47.6 प्रतिशत हो गई। ये आंकड़े संभवतः भारतीय बैंकिंग के पूरे स्वरूप में बदलाव का सार पेश करते हैं।

कृषि और उद्योग, कुल ऋण का 58 प्रतिशत समान रूप से साझा करते हैं और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 27.3 प्रतिशत है जबकि 13.9 निजी ऋण से जुड़ा है। बढ़े हुए फंसे ऋण के कारण असुरक्षित निजी ऋण में बैंकों का निवेश आरबीआई के जांच के दायरे में आ गया है। पिछले साल नवंबर महीने में बैंकिंग क्षेत्र के नियामक ने इस तरह के ऋण में जोखिम स्तर को 0.75 फीसदी से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया था और इसके चलते ऐसे ऋण के वितरण के लिए पूंजी की लागत महंगी हो गई। अब ऐसे में बैंकों को उन्हें समर्थन देने के लिए अधिक पूंजी आवंटन की जरूरत होगी। इसका उद्देश्य बैंकों को आक्रमक तरीके से निजी ऋण देने से हतोत्साहित करना है।

इस क्षेत्र में शिक्षा ऋण में सबसे अधिक सकल एनपीए (3.6 प्रतिशत) है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां (1.8 प्रतिशत), वाहन ऋण (1.3 प्रतिशत), आवास ऋण (1.1 प्रतिशत) का स्थान है।

निजी ऋण में आवासीय ऋण की अधिकतम हिस्सेदारी (48.6 प्रतिशत) है और इसके बाद वाहन ऋण (11.1 प्रतिशत) का स्थान है। दोनों ही सुरक्षित ऋण हैं और इसे कुछ चीजें गिरवी रखे जाने से इन क्षेत्रों को समर्थन मिलता है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का फंसा ऋण अधिक है। वहीं, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों का सकल एनपीए 11.3 प्रतिशत है, शिक्षा ऋण 3.9 प्रतिशत और आवास ऋण 1.2 प्रतिशत है।

कुल मिलाकर ये आंकड़े भारतीय बैंकिंग उद्योग की बदलती तस्वीर को दर्शाते हैं। पिछले दशक में आरबीआई द्वारा की गई अनूठी परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद बैंकों के बैलेंसशीट में सुधार करने के बाद इसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश में दोबारा संतुलन बनाने की कोशिश की। नए मामले में कमी आने और फंसे कर्ज को लगातार बट्टे खाते में डाले जाने से भी फंसे कर्ज में कमी आई है। इसके अलावा अच्छे वक्त में जब क्रेडिट बुक में वृद्धि होती है तब फंसे कर्ज के प्रतिशत में गिरावट आती है। यह सरल अंकगणित है।

आंकड़े निजी ऋण क्षेत्र में कुछ खराब संकेत नहीं पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद आरबीआई इतनी सतर्कता क्यों बरत रहा है? निजी ऋण में एनपीए के आंकड़े भी उतने अधिक नहीं लगते हैं क्योंकि आक्रामक रूप से इन्हें बट्टे खाते में डाला गया है। कोई खाता एनपीए में तब बदल जाता है जब उधारकर्ता लगातार तीन महीने तक ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है। ज्यादातर निजी बैंक निजी ऋण को बट्टे खाते में डालने को तरजीह देते हैं जिनमें 90 दिनों तक चूक दर्ज की जाती है। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि इस तरह के ऋण से होने वाली आमदनी अधिकांश अन्य ऋण की तुलना में कहीं अधिक है। एक बार जब ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है तब यह बैंक की बैलेंसशीट से निकल जाता है और शाखाओं में जमा हो जाता है। बाद के चरण में अगर कोई वसूली होती है तब इससे बैंक का मुनाफा बढ़ता है।

कई वर्षों से बैंकों की बैलेंसशीट में एक चीज बिल्कुल नहीं बदली है और वह है कृषि क्षेत्र में ज्यादा फंसा ऋण। मई महीने में आरबीआई ने परियोजना ऋण के मसौदे के लिए दिशानिर्देश जारी किए। साथ ही इसने बैंक प्रोविजन को परियोजना के निर्माण चरण के दौरान बैंक के बकाया और ताजा जोखिम को 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा। क्या बैंकिंग नियामक, कृषि ऋण के लिए प्रोविजन बढ़ाने की संभावनाएं तलाश सकता है। अगर ऐसा होता है तब बैंक इसमें चूक के जोखिम का मूल्यांकन करते हुए इस ऋण की लागत तय करेंगे। हालांकि यह भविष्य में संभव होना चाहिए लेकिन यह आसान नहीं है।

आपका पक्ष

बारिश के मौसम में जलमग्न होते गांव-शहर

दिल्ली हो या मुंबई या अन्य कोई शहर सभी में अनवरत वर्षा से जलप्रलय की स्थिति बनना आम बात हो गई है। इसकी वजह अनियोजित शहरीकरण एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध न होना है। जब भी शहर में कॉलोनी या सोसाइटी बसती हैं तो उसके साथ ही जल निकासी की समुचित योजना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत यह देखा जाना चाहिए है कि कौन से निचले स्तर के इलाके हैं और उनके लिए बारिश का पानी निकलने के रास्ते क्या होंगे। अगर कुछ किलोमीटर के फासले पर तालाब जैसे जलाशय बनाकर उस पानी को सहेजा जाए तो यह जलजमाव रोकेगा तथा जलसंकट से निपटने में भी सहायक होगा। प्रत्येक मकान के साथ संचयन की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। कई शहरों की जल निकासी की व्यवस्था दशकों पुरानी है। अतः उनका नवीकरण भी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शुक्रवार को सड़क पर कमर तक भरे पानी के बीच अपनी बाइक लेकर निकलता एक व्यक्ति

वर्षाकाल में बाढ़ एक प्रमुख समस्या है जिस क्षेत्र में बड़ी नदियां होती हैं वे क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाते हैं। इससे जानमाल का काफी नुकसान होता है। नदियों को आपस में जोड़ने से इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने एक योजना भी बनाई थी लेकिन इस दिशा में उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए।

विमलेश पगारिया, धार

भारत और ब्रिटेन संबंधों के नए आयाम

लेख 'भारत-ब्रिटेन संबंध नए शिखर की ओर' और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की चुनावों में भारी विजय के पश्चात प्रधानमंत्री कियर स्टॉर्मर के नेतृत्व में सरकार के गठन के समाचारों ने दोनों देशों के संबंधों में नए आयामों के प्रति आशान्वित किया है। ब्रिटेन की नई वित्त मंत्री रचेल रीव्स भी आर्थिक नीतियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वर्तमान में ब्रिटेन के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौते के इतर भी दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा, तकनीक, खेल, अंतरिक्ष, शिक्षा एवं ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए बड़े पटल पर पारस्परिक संबंधों के विस्तार की आवश्यकता है। इन चुनावों में लेबर पार्टी की भारी विजय ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि इस सरकार की आर्थिक नीतियां ब्रिटेन को समृद्ध करने पर ही केंद्रित रहेंगी। इसलिए आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति की उन्नति एवं अवनति उसी देश के भीतर के कारणों से जनित होती है।

इसलिए ब्रिटेन को भी उन्हीं कारणों की पहचान करनी होगी और इस दिशा में भारत का सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है। ब्रिटेन को भी भारत जैसा एक विशाल और सुदृढ़ साझेदार चाहिए। पिछले वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार और निवेश बढ़ा है और दोनों देशों में नई सरकारें गठित हुई हैं। इसलिए भारत और ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों और सहयोग की बहुत संभावनाएं और अवसर हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नेहयान के साथ भारतीय मूल के डॉ. जॉर्ज मैथ्यू। यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम 84 वर्षीय डॉ. जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। डॉ. मैथ्यू 1967 में 26 वर्ष की आयु में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के प्रति आभार का प्रतीक है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जमानत और जेल

जब किसी को अदालत से जमानत मिलती है, तो कहा जाता है कि वह जमानत पर बाहर आ गए। मगर शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है, उसे लेकर यह नहीं कहा जा सकता। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब-नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है, लेकिन सिर्फ इतने से ही उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। कुछ सप्ताह पहले भी उन्हें इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, हालांकि हाईकोर्ट ने तब इस पर रोक लगा दी। प्रवर्तन निदेशालय, यानी 'ईडी' के सामने यह तभी स्पष्ट हो गया था कि इस मामले में केजरीवाल को बहुत समय तक जेल में रखा जाना शायद संभव न हो। ठीक उसी समय एक दूसरी जांच एजेंसी 'सीबीआई' आगे आई और उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर एक मामला दर्ज किया और उन्हें औपचारिक रूप से अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक मामले में जमानत हासिल करने में कामयाब भी रहे, तो दूसरा मामला उन्हें जेल से बाहर जाने से रोक देगा। शुक्रवार को यही हुआ और जमानत की खबर उनके लिए कोई राहत नहीं ला पाई। यह जरूर है कि इन मामलों पर जो राजनीति चल रही है, उनमें आम आदमी पार्टी को अपनी आक्रामकता दिखाने का एक और मौका मिल गया।

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े जितने भी मामले हैं, वे काफी समय से चल रहे हैं और गिरफ्तारियों व आरोपों के अलावा चीजें बहुत आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी सर्वोच्च अदालत में दाखिल की थी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उसे एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस याचिका में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उसे गैर-कानूनी बताया था। जब इस याचिका पर बड़ी पीठ विचार करेगी, इस दरमियान केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के सवाल पर अदालत ने कहा कि हमें संदेह है कि अदालत एक निर्वाचित नेता को पद छोड़ने का निर्देश दे सकती है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह फैसला हम पूरी तरह अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। इसके पहले आम चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, जो दिल्ली में मतदान खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। तब केजरीवाल रिहा होकर बाहर आए थे और उन्होंने पूरे देश में प्रचार भी किया था, इस बार जमानत के बाद भी वह जेल में ही रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट काफी पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि नियमतः हर किसी को जमानत मिलनी चाहिए, केवल अपवाद मामलों में ही किसी को जेल में रखा जाना चाहिए। कौन सा मामला अपवाद है और कौन सा नहीं, यह हमेशा ही विवादास्पद रहता है। जिन मामलों में कोई राजनीतिज्ञ शामिल हो, वहां ऐसे विवाद काफी बढ़ जाते हैं। यह भी सच है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े जितने भी मामले हैं, वे काफी समय से चल रहे हैं और गिरफ्तारियों व आरोपों के अलावा चीजें बहुत आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं। इसमें कितना इस वजह से है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में चीजें बहुत ज्यादा खिंचती ही हैं और कितना इस वजह से कि इन मामलों में राजनीतिक खींचतान काम कर रही है। यह ऐसी समस्या है, जिसका समाधान पारदर्शिता लाकर ही किया जा सकता है।

तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को गुजारा-भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरर्थक करने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा मई 1986 में मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। उस पर हुई बहस में कही गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं।

तलाकशुदा औरतों के साथ यह नाइंसाफी

यहां स्कैन करें

प्रो मधु दंडवते | वरिष्ठ सांसद

- यह विधेयक संविधान के भाग तीन में नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों को उनसे छीनता है।
- वक्फ बोर्ड तो खुद अपने सामान्य कार्यों के लिए सरकार से मदद मांगते रहते हैं, वे क्या उनकी मदद करेंगे?

महोदय, मैं उन लोगों में हूं, जो समाजवाद, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों से स्पष्टतः प्रतिबद्ध हैं और अपनी दृढ़ धारणा तथा विवेक के आधार पर मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं।... मैंने इस सम्मानित सभा में शपथ लेते समय देश के संविधान तथा संरक्षण के लिए शपथ ली थी। प्रजातंत्र में मेरे लिए वही सबसे पवित्र पुस्तक है। इस संविधान... के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 और उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 (2) में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, जो संविधान के भाग-तीन द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को या तो छीनता है अथवा उनसे वंचित करता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक की न्यायिक जांच की जाए, तो आप पाएंगे कि इस विधेयक को एक बहुत छोटे से कारण से पहले ही झटके में वापस भेज दिया जाता कि इस विधेयक पर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13(2)के उपबंध लागू होते हैं, जो किसी भी ऐसे विधेयक अथवा कानून को, जो वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है अथवा वंचित करता है, अनुमति नहीं देता है। इसलिए मैंने इस विधेयक की विधायी सक्षमता को पहले ही चुनौती दी।

महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो यह सोचते हैं कि जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद का प्रश्न है, तो धार्मिक समुदाय का लिहाज किए बिना इसमें देश की महिलाओं को कतिपय सुरक्षा प्रदान की गई है और धार्मिक संप्रदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना मैं यह कह सकता हूं कि इस्लाम के नियमों के अनुसार शरीयत की भावना यह है कि महिलाओं को समानता का अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाए। इसका निष्कर्ष यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किसी अनुच्छेद में यदि महिलाओं को अतिरिक्त राहत या सहायता प्रदान की जाती है, तो किसी को भी महिलाओं के रास्ते में नहीं आना चाहिए, चाहे महिलाएं मुसलमान या हिंदू या ईसाई हों। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद-125 की परिधि से बाहर करना है और उन्हें रिश्तेदारों तथा दिवालिया हुए वक्फ बोर्डों की दया पर छोड़ना है। वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इस विधेयक को तैयार करने वालों ने जान-बूझकर उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद-125 की परिधि से बाहर किया है, ताकि इद्दत की एक विशेष सीमा के बाद वह (तलाकशुदा महिला) अपने पति से कोई अनुरक्षण की धनराशि की मांग न कर सके। इस मामले में अनुरक्षण और सहायता के लिए उसे अपने रिश्तेदारों के पास जाना होगा और यदि रिश्तेदार उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वह वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। परंतु वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति क्या है? अपने सामान्य कार्यों के लिए भी ये वक्फ बोर्ड सरकार के पास आकर कहते हैं कि 'हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। बोर्ड के नियमों के अंतर्गत निर्धारित सामान्य कार्य भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अतः हमें वित्तीय सहायता दीजिए।' उनकी स्थिति यह है।

मैं एक कहानी बता सकता हूं, जो करुणा से भरी हुई है। आप प्रधानमंत्री से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं अश्रुपूरित नेत्रों से प्रधानमंत्री के पास गईं। एक मुस्लिम लड़की ने कहा : प्रधानमंत्री जी, मुझे तीसरी बार तलाक दिया गया है और यदि आप 21वीं शताब्दी में जाने की बात कहते हैं, तो हम जैसी महिलाओं को वापस छठी शताब्दी में क्यों फेंकते हैं? हमें इन लोगों की दया पर मत छोड़िए।' ... जब वह यह बात कह रही थी, तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। इसका उल्लेख समाचारपत्रों में हो चुका है, क्योंकि एक प्रेस संवाददाता वहां उपस्थित था। उसने सारी तस्वीरें प्रस्तुत की हैं।

यह बिडंबना है। हम नहीं चाहते कि यह त्रासदी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में लाई जाए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

आमने-सामने

हमें गैर-मर्द के टुकड़ों पर जीना गवारा नहीं

यहां स्कैन करें

आबिदा अहमद | वरिष्ठ सांसद

- सेक्शन-125 में अगर साबिक शौहर भाग जाए या मर जाए, तो वह औरत बेसहारा हो जाएगी।
- सेक्शन-125 के तहत जो रकम मिलती है, उसकी एक हद है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई हद नहीं।

जनाब चेयरमैन साहब, मुझे आज यह शरफ (सम्मान) हासिल हुआ है कि मैं इस बिल पर अपने ख्यालात का इजहार करूं, जो मुस्लिम खवातीन (महिलाओं) के मुत्तालिक सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में पेश हुआ है, वह शरीयत पर मुबनी (निर्भर) है। जब से यह बिल पेश हुआ है, तब से आज तक इस दौरान हिन्दुस्तान में जगह-ब-जगह इस बिल की ताईद (समर्थन) में जलसे किए गए, 10 अप्रैल को वोट क्लब में मुस्लिम खवातीन की रैली हुई, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान औरतों ने हिस्सा लिया और एक आवाज होकर उन्होंने इस बिल की ताईद की, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी और कहा कि इस बिल को इसी 'सेशन' में पास कर दिया जाए।

...मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हमारी चंद बहनें, चंद भाई इस बिल के खिलाफ हैं? दफा-125 को इस बिल पर तरजीह नहीं दी जा सकती। शरीयत में इद्दत (प्रतीक्षा अवधि) की मुद्दत के दौरान औरत की देखभाल उसका साबिक (पूर्व) शौहर करता है। उसके बाद वह एतबार से भी अजनबी हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन वह औरत बेसहारा नहीं होती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसके मां-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी और दूसरे अजीज रिश्तेदारों की हो जाती है। दरअसल, जिनकी जायदाद में वह वारिस हो सकती है और उसकी जायदाद में जो लोग वारिस हो सकते हैं, वे उसकी देखभाल करते हैं। 125 में अगर साबिक शौहर भाग जाए या मर जाए, तो वह औरत बेसहारा हो जाएगी। उसके बाद वह 'सेक्शन' खामोश है। उसकी देखमाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन शरीयत में वह बेसहारा नहीं होती, क्योंकि उसको देखने वाले पहले तो उसके मां-बाप हैं, फिर बेटा-बेटी हैं, बहन-भाई हैं और अगर कोई भी न हो इनमें से, तो फिर 'कम्यूनिटी' है।

...अभी किसी बरखुरदार ने यह कहा था कि तलाकशुदा का अगर कोई बच्चा शीरख्वार (दूधमुंहा) है, तो दो साल तक साबिक शौहर से मेंटनेंस मिलेगा और दो साल के बाद वह बच्चा क्या करेगा, उसको कौन मेंटेन करेगा?... मैं यह कहना चाहूंगी कि शरीयत के ऊपर बोलने से पहले यह जरूरी है कि शरीयत को पढ़ लिया जाए कि उसमें पोजीशन क्या है?... वह बच्चा दो साल के बाद बेसहारा नहीं हो जाता... बच्चे की देखभाल करना उसके बाप का फर्ज है। वह हमेशा रहेगा उसका और हिस्सा भी उसकी जायदाद में जितना भी होगा, वह वैसा ही रहेगा, जैसा और बच्चों का होता है। यह कहा गया था कि वह बच्चा कहां जाएगा इसके बाद? कौन देखभाल करेगा? तो मैंने सोचा कि इस पहलू को जरा साफ कह दूं।

मां-बाप की नजर में उनकी बेटी लख्ते-जिगर, उनकी नूरे-नजर है। आखिर वह लड़की या औरत तलाक के बाद उस आदमी के सामने हाथ क्यों फैलाए, जो उसके लिए अब अजनबी है, एक गैर-मर्द है?... क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है, कोई गैरत नहीं है? सेक्शन-125 के तहत शाह बानो के केस में जो फैसला किया गया, उससे औरत को बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया।... कौन गैरतदार औरत ऐसी है, जो शरीयत के दिए हुए ऊंचे दर्जे को छोड़कर एक भिखारिन बन जाए, यानी एक गैर-मर्द के टुकड़ों पर पलती रहे?

...एक बात मैं और कहना चाहूंगी। सेक्शन-125 के तहत जो रकम मिलती है, उसकी हद 500 रुपये है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई हद नहीं है। यह बिल जो शरीयत पर बेस्ड है, तो क्या मुखालफत इस बात पर है कि औरतों को मेहर मिले, उनकी जो जायदाद है, उनको मिले, उसकी जो जाती मिल्कियत है, वह उसे मिले? क्या यह हमदर्दी है, जो आप इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं! ऐसी हमदर्दी की औरतों को जरूरत नहीं है। मैं इस बिल की ताईद करती हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा में छिपी खुशहाली

यहां स्कैन करें

शबाना आजमी | अभिनेत्री

पिछली सदी के आखिरी दशक में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मुझे दक्षिण एशिया के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था। अपनी नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैंने मुंबई की झुग्गियों में काम करने वाली महिलाओं से बात करने का फैसला किया। मैं गांवों में जाकर सैकड़ों महिलाओं से मिली और यह महसूस किया कि वे अपनी मर्जी से कई बच्चे पैदा नहीं करतीं। इससे उनके शरीर और बच्चों को होने वाले नुकसान से भी वे भली-भांति वाकिफ थीं। इनमें से कई महिलाएं कुपोषित थीं, तो कई एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित। मुझे याद है, मैंने एक महिला से कहा था कि उसके लिए मैं नियमित रूप से गर्भनिरोधक गोलियां भेजने की व्यवस्था करूंगी, जिसे वह अपनी सास और पति को बताए बिना चुपचाप ले सकती है। उसका जवाब था, दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी झोपड़ी में एक भी ऐसी जगह है, जहां मैं परिवार की नजरों से बचाकर कोई चीज रख सकती हूं? उन दिनों कई समुदायों में परिवार नियोजन पर चर्चा करना गलत माना जाता था।

पितृ-सत्तात्मक सोच और सामाजिक मानदंड ही नहीं, कई अन्य कारकों ने भी महिलाओं को परिवार नियोजन, यौन संबंध और प्रजनन से जुड़े मसलों पर फैसले लेने से रोका है। लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स से जुड़े सार्वजनिक विमर्शों में इस तथ्य को सामने लाने की जरूरत थी। मुझे इस संदर्भ में तमाम लोगों से बात करने का मौका मिला- सरकारी अधिकारियों से लेकर समुदायों के मुखियों तक। तब से लेकर अब तक हमने परिवार नियोजन के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति देखी है। हालांकि, भारत के परिवार नियोजन-2030 विजन को हासिल करने के लिए अब भी काफी प्रयास करने की दरकार है।

निस्संदेह, पिछले कुछ वर्षों में गर्भनिरोधक विकल्पों का काफी विस्तार हुआ है। अब ऐसे-ऐसे सुरक्षित और सरल तरीके हैं, जो स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य और करियर को लेकर सजग फैसला लेने में सक्षम बना सकते हैं। इससे वे अधिक संतुष्ट जीवन जी सकती हैं। हालांकि, महिलाओं व पुरुषों, दोनों के लिए आधुनिक गर्भनिरोधकों तक पहुंच बनाना अब भी एक चुनौती है। आधुनिक

पिछले कुछ वर्षों में, गर्भनिरोधक विकल्पों का काफी विस्तार हुआ है। अब ऐसे-ऐसे सुरक्षित व सरल तरीके हैं, जो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और करियर को लेकर सजग फैसला लेने में सक्षम बना सकते हैं।

गर्भनिरोधकों की उपलब्धता के बावजूद विवाहित स्त्रियों (15-49 आयु-वर्ग की) के बीच पारंपरिक तरीकों का उपयोग करीब-करीब दोगुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पारंपरिक तरीके से गर्भनिरोध करने वाली महिलाओं का आंकड़ा 2015-16 में 5.7 प्रतिशत था, जो 2019-21 में बढ़कर 10.2 फीसदी हो गया। सवाल है कि क्या हम उन बुनियादी कारणों को दूर करने में सफल रहे हैं, जो आधुनिक गर्भनिरोधकों को व्यापक तौर पर अपनाने से रोक रहे हैं?

भारत में विशाल युवा आबादी को देखते हुए यहां अस्थायी और अंतराल वाले तरीकों की पहुंच जरूरी है। गर्भनिरोधक, जैसे इंजेक्शन, प्रत्यारोपण व अंतरगर्भाशयी उपकरण (आईयूडी) अनचाहे गर्भ को रोकने के विश्वसनीय तरीके हैं। इसके अलावा, खुद से प्रबंधन करने वाले तरीके भी हैं। ये महिलाओं को अपने गर्भधारण के बीच अंतराल रखने में सक्षम बनाकर मां व बच्चे, दोनों की सेहत को सुधारने में मददगार साबित होते हैं।

एनएफएचएस-5 के मुताबिक, उन महिलाओं की संख्या घटी है, जो गर्भधारण को रोकना या टालना तो चाहती हैं, पर किसी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2015-16 में ऐसी महिलाओं की संख्या 12.9 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 9.4 फीसदी हो गई। यह संकेत है कि महिलाएं अब गर्भधारण में अंतराल लाने वाली विधियों के फायदे समझने लगी हैं। महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने व उनके प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमें गर्भनिरोधक उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रभावी और सुगम तरीके खोजने होंगे। इसके अलावा, गर्भनिरोधकों से जुड़ी गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए समाज को शिक्षित भी करना होगा। इसके लिए नामचीन हस्तियों और समाज के बौद्धिकों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का सम्मान करने वाली नीतियों की वकालत करें। ऐसे प्रयासों से हम स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज व बराबरी वाली दुनिया बना सकेंगे।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 13 जुलाई, 1949

दिल्ली का शासन

दिल्ली प्रान्त केन्द्रीय सरकार की देखरेख में चीफ कमिश्नर द्वारा शासित हो रहा है। अंग्रेजी राज के समय में भी यही व्यवस्था थी और देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी उस स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। पहले चीफ कमिश्नर एक निरंकुश शासक की भांति काम करते थे। केन्द्रीय सरकार उनके कामों में क्वचित ही हस्तक्षेप करती थी। दिल्ली के नागरिकों के लिए चीफ कमिश्नर के निरंकुश शासन को चुपचाप बर्दाश्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब इतना परिवर्तन जरूर हो गया है कि दिल्ली निवासियों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार के नेताओं तक पहुंच सकते हैं और अपनी शिकायतें उनके सामने पेश कर सकते हैं। उनकी शिकायतें ध्यान से सुन ली जाती हैं और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दे दिया जाता है। स्वयं चीफ कमिश्नर भी जनता की आकांक्षाओं के प्रति उतना उपेक्षा भाव नहीं रखते, जितना पहले रखा करते थे। केन्द्रीय सरकार ने कृपा करके एक सलाहकार कौंसिल नियुक्त कर दी है, जिसमें तीन नामजद और तीन निर्वाचित सदस्य हैं। उनके अलावा केन्द्रीय धारासभा में दिल्ली के प्रतिनिधि भी उसके सदस्य मान लिये गये हैं। दिल्ली के निवासियों को अपने शासन की मौजूदा स्थिति से सन्तोष नहीं है। सन्तोष हो भी नहीं सकता; क्योंकि देश के अन्य भागों को स्वशासन के जिन अधिकारों का उपभोग करते वे देखते हैं, उनसे वे अपने को वंचित पाते हैं। सलाहकार कौंसिल का काम तो केवल सलाह देना मात्र है और उस सलाह को मानना, न मानना चीफ कमिश्नर साहब की मीठी मर्जी पर निर्भर करता है। ऐसी दशा में यदि दिल्ली के नागरिक प्रान्त के शासन की मौजूदा अवस्था से असन्तुष्ट हों तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

दिल्ली की शासन व्यवस्था का स्वरूप बदलने और उसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए दिल्ली के नेता और सार्वजनिक संस्थायें एक लम्बे अर्से से सचेष्ट रही हैं। किसी न किसी कारणवश अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। दिल्ली प्रान्त का मौजूदा क्षेत्रफल ५७४ वर्गमील और आमदनी डेढ़ करोड़ से कुछ अधिक है। कुछ भाग पूर्वी पंजाब का और कुछ भाग युक्त प्रान्त का लेकर दिल्ली प्रान्त का विस्तार किया जा सकता है।

मनसा वाचा कर्मणा

ईश्वर का साकार रूप

ईश्वर परमात्मा है; उनका निराकार स्वरूप अदृश्य है। परन्तु उन्होंने भौतिक संसार की रचना की तो वे परमेश्वर जगतपिता कहलाए। सृष्टिकर्ता की भूमिका निभाने के लिए वे साकार हो गए। वे दृष्टिगोचर हो गए। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का शरीर है।

तारे उनकी आंखें हैं, घास और पेड़ उनके बाल और नदियां उनका रक्त प्रवाह। समुद्र का गर्जन, लवा पक्षी का गीत, नवजात शिशु का रुदन और सृष्टि की सभी ध्वनियां उनकी वाणी हैं। यह ईश्वर का साकार रूप है। सबके हृदयों की धड़कन उस प्रभु की धड़कती हुई ब्रह्माण्डीय शक्ति है। वे समस्त मानव जाति के असंख्य चरणों द्वारा चलते हैं। वे सबके हाथों के माध्यम से काम करते हैं। यह एकमात्र दिव्य-चेतना है, जो सब मस्तिष्कों द्वारा व्यक्त हो रही है। ईश्वर के आकर्षण व प्रतिकर्षण के नियम के कारण मनुष्य-शरीर के कोशाणु एक-दूसरे के साथ एक लय में उसी प्रकार संबद्ध हैं, जैसे सितारे अपनी-अपनी कक्षा में संतुलन रखे हुए हैं। सर्वव्यापक भगवान नित्य क्रियाशील हैं। कहीं कोई भी ऐसा स्थान नहीं, जहां किसी न किसी प्रकार का जीवन न हो। अपनी असीम उदारता से ईश्वर सदा ही अनेक रूपों के आकार- अपनी विश्व-शक्ति के अनंत स्वरूपों- को प्रक्षिप्त करते हैं।

जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रची, तो उनके मन में एक विशेष विचार या रूपरेखा थी। पहले उन्होंने संपूर्ण विश्व को बाह्य रूप दिया, तत्पश्चात मानव की सृष्टि की। ईश्वर ने तीन स्वरूप प्रदर्शित किए : विश्व-चैतन्य, विश्व-शक्ति और विश्व-द्रव्य या पदार्थ। ये तीनों क्रमानुसार मनुष्य का कारण शरीर, सूक्ष्य या शक्तिमय शरीर और स्थूल शरीर दर्शाते हैं। इन सबकी आत्मा या जीवन परमात्मा हैं।

श्री श्री परमहंस योगानंद

केर स्टार्मर | ब्रिटिश प्रधानमंत्री

मासूम बच्चों पर हमला इस धरती का सबसे निकृष्टतम कृत्य है। हम रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। युद्ध खत्म होने तक कीव को हमारा समर्थन कम नहीं होगा।

भारत का सदाबहार दोस्त रहा है रूस

रूस हमारा सदाबहार मित्र है। वह हमेशा भारत के सुख-दुख का साथी रहा है। भले ही उसके सिर पर लाल टोपी रही, लेकिन दिल से वह सदैव तिरंगे की मदद ही करता रहा है। यही वजह थी कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति पुतिन की दिल से प्रशंसा की, साथ ही कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत का विकास सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। भारत हर वक्त शांति, संवाद और कूटनीति पर ही जोर देता है। वह किसी भी देश को सही बात सुनाने में सक्षम है। इसी कारण, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को यह बताया कि युद्ध का समाधान शांति और आपसी वार्ता ही है, गोला-बारूद नहीं। रूस में भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया को शांति का संदेश देने में पीछे नहीं रहे। बहरहाल, इस दौरे ने रूस को भारत के और करीब ला दिया है। यह मित्रता किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि दोतरफा विकास के लिए है। इसीलिए, किसी अन्य देश को इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

पुरानी मित्रता

भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती पूरी दुनिया में जगजाहिर है। इस दोस्ती को और धार एवं मजबूती प्रदान करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी में विदेश यात्रा की शुरुआत रूस से की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा से चीन और पश्चिम के देशों को बता दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती में कोई तीसरा नहीं आ सकता। इस यात्रा से भारत को एक बड़ी उपलब्धि यह मिली है कि रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों के वतन लौटने का रास्ता साफ हो गया है। इस यात्रा ने भारत और रूस के संबंधों को एक नई ऊर्जा दी है, लिहाजा यह अपेक्षा भी है कि उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मसलों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हुआ है। रूस में भारतीयों के हितों की बात हो, आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य या फिर कई अन्य समझौतों पर मुहर, इन सबसे भारत और रूस की आपसी दोस्ती कहीं ज्यादा गहरी हुई है। सात दशक पुराना भारत-रूस संबंध इस दौरे के बाद कहीं ज्यादा मजबूत नजर आने लगा है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

भारत-रूस दोस्ती

मॉस्को और बीजिंग अब ज्यादा करीब

रूस संभवतः भारत से ज्यादा अब चीन के करीब है, कम से कम पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों से यही संदेश निकल रहा है। इसी मई में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने नए कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के तहत चीन पहुंचे थे, तब उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए। उनकी दोस्ती बेशक ज्यादा पुरानी न हो, लेकिन हाल-फिलहाल इसमें इसलिए घनिष्ठता आ गई है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, तो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसने चीन के साथ कराबोरी रिश्ते बढ़ाए। चीन ने भी उसका पूरा साथ दिया, भले ही उसने इस अवसर का लाभ भी उठाया। चीन इसलिए भी रूस के करीब आ गया है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी से हर कोई वाकिफ है और रूस तो अमेरिका के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है।

साफ है, रूस और चीन के हित आपस में जुड़े हुए हैं। रूस को जहां अपनी अर्थव्यवस्था बचाने और यूक्रेन संकट से पार पाने के लिए चीन की जरूरत है, तो वहीं बीजिंग भी मॉस्को से सस्ते दामों में गैस व तेल मंगाना चाहता है, जिस कारण वह दोस्ती बढ़ाने में जुटा है। यहां यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि हर देश अपने-अपने हितों का ही पोषण करते हैं। रूस भी यही कर रहा है। वह पश्चिमी देशों से टकराने के लिए तमाम देशों से नजदीकी बढ़ा रहा है। आज के समय में चूंकि आर्थिक ताकत सबसे अहम होती है और चीन इस मामले में भारत पर बीस साबित होता है, इसलिए रूस को चीन के साथ जाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही।

भारत के साथ मुश्किल यह है कि वह अमेरिका के साथ टकराने की मुद्रा में कभी नहीं रहा। ऐसा शायद ही कभी हो सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष नीति के तहत हम किसी खेमे में जाना पसंद नहीं करते। हमारी यह नीति भी रूस और चीन को करीब लाती है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि भारत अपनी नीतियों के कारण अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, जबकि चीन लगातार अमेरिका से टकराता रहा है। फिर, सस्ते उत्पादों के कारण भी चीन का वैश्विक व्यवस्था में खासा दबदबा है, जिसका लाभ रूस को मिल सकता है। इन्हीं सबको देखकर यह लगता है कि हम बतौर राष्ट्र भले ही रूस के साथ दोस्ती के राग गाते रहें, लेकिन उसकी मित्रता अब चीन से कहीं अधिक पक्की जान पड़ती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह जानता है कि किसी मुश्किल वक्त में अब बीजिंग उसके ज्यादा काम आ सकता है।

शोभित कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AINewsPaperPdf

दैनिक जागरण

ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता का मार्ग है

संविधान हत्या दिवस

केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी कर यही स्पष्ट किया कि वह विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी कि भाजपा संविधान बदलने का इरादा रखती है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि मोदी सरकार ने 49 साल पहले 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल थोपे जाने के इंदिरा गांधी के मनमाने फैसले को संविधान को कुचलने वाले कदम के रूप में स्मरण करने का निर्णय केवल इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में देश भर में घूम-घूम कर यह दुष्प्रचार कर लोगों को बरगलाया कि यदि भाजपा का चार सौ पार का नारा सही सिद्ध हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। यह निर्णय संभवतः इसलिए भी लिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी कांग्रेस और उसके साथी दल यह खोखला दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने संविधान की रक्षा की। निःसंदेह 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन शायद मोदी सरकार के लिए ऐसा कोई फैसला लेना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि अभी हाल में जब आपातकाल की बरसी पर इंदिरा सरकार की ओर से की गईं ज्यादतियों का स्मरण किया जा रहा था तो कांग्रेस ने यही दिखाया कि उसे यह रास नहीं आ रहा है। हद तो तब हो गई, जब आपातकाल के विरोध में लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस के नकारात्मक रवैये को देखते हुए इसकी आवश्यकता स्वतः रेखांकित होने लगी थी कि उस काले दौर को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने तो आपातकाल के अलावा भी संविधान की अनदेखी करने वाले फैसले लिए हैं। क्या यह एक तथ्य नहीं कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के फैसले को पलटना संविधान का नग्न निरादर ही था? सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से देश को यह अच्छी तरह स्मरण भी हो आया। कांग्रेस संविधान को भाजपा और विशेष रूप से मोदी सरकार से खतरे का कितना ही हौवा खड़ा करे, सच यह है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन उसने ही किए हैं और वह भी विपक्ष की अनदेखी करके। इसके विपरीत मोदी सरकार ने बीते दस वर्षों में जो भी संविधान संशोधन किए, उनमें से हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया-वह चाहे जीएसटी संबंधी हो या फिर निर्धन सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का।

भूमि की बंदरबांट

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल ने जिस तरह 75 बीघा विवादित भूमि की बंदरबांट की, वह उदाहरण है कि तहसील स्तर पर किस तरह लेखपाल से लेकर एसडीएम तक जमीन कब्जाने के लिए आपराधिक गठजोड़ में लिप्त हैं। इस उदाहरण के आईने में ही कई अन्य समस्याओं की सच्चाई भी दिख जाएगी जो अंततः आम आदमी के लिए ही नासूर बनती है। यह भी दिख जाएगा कि मुख्यमंत्री के बार-बार कहने के बावजूद कि आम आदमी की समस्याएं जिला स्तर पर ही सुलझा ली जाएं, क्यों वह मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पीड़ित, याचक या शिकायतकर्ता के रूप में पहुंचने को विवश हो जाता है। यह भी कि क्यों चारागाहों, तालाबों, जलाशयों, पंचायतों, निकायों की भूमि सरकारी रिकार्ड से गायब होती जा रही है। तहसील स्तर पर जिन लोगों के पास अर्धन्यायिक शक्तियां निहित हैं, उनमें यही लेखपाल से लेकर एसडीएम तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होते हैं। जब न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर ही भ्रूण हत्या की शिकार हो जाए तो भविष्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में 75 बीघा भूमि के तीन दावेदार सामने आए थे। प्रकरण एसडीएम के पास तक पहुंचा और भूमि की बंदरबांट ऐसी हुई कि एसडीएम की सास, ससुर, साली, चचेरे भाई और इसी तरह अन्य अधीनस्थों के बीच बैनामे के शक्ल में बंट गई। जिलाधिकारी ने शिकायत पर जांच की तो मामला खुला, जिसमें शामिल लेखपाल से लेकर एसडीएम तक को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यही नहीं, अब इन अफसरों की संपत्तियों की विजिलेंस जांच भी होगी। इसमें संदेह नहीं कि शासन स्तर पर सख्त कार्रवाई हुई है। अब इसे शीघ्रता से इस रूप में परिणति तक पहुंचाना चाहिए कि अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए उदाहरण बने। न केवल भ्रष्टाचार से कमाई संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें जेल तक पहुंचाने एवं सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

मतांतरण की खतरनाक चुनौती

डा. ऋतु सारस्वत

किसी व्यक्ति के मतांतरण से न केवल मतांतरित हुआ वह व्यक्ति, अपितु पूरा समाज प्रभावित होता है

अवधेश राजपूत

बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मतांतरण पर कठोर टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा, 'यदि मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी।' न्यायालय ने यह भी कहा कि मत प्रचार-प्रसार की तो छूट है, लेकिन मतांतरण की अनुमति नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है कि मतांतरण के संबंध में न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पूर्व नवंबर 2022 में भी उच्चतम अदालत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जबरन मतांतरण के संबंध में कहा था 'यह अंततः राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों के अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है।' देश के विभिन्न न्यायालयों ने जबरन मतांतरण को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके पीछे तथ्यात्मक एवं ठोस कारण हैं।

यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके 'पथ' जिसे संवैधानिक एवं न्यायिक भाषा में 'धर्म' भी कहा जाता है, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। विश्व भर में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है, जो किसी न किसी पंथ के अनुयायी हैं और अपने मत विशेष में न केवल आस्था रखते हैं, बल्कि उसे 'जीवन निर्देशक' के रूप में स्वीकार करके अपनी जीवन प्रणाली को उसकी मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुरूप संचालित करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ही नहीं अधिकांश देशों में 'पंथ' मात्र आस्था का विषय नहीं, अपितु व्यक्ति की पहचान का द्योतक भी है और इस पहचान को परिवर्तित करने का निर्णय यदि एकाएक हो तो कई प्रश्नों का खड़ा होना स्वाभाविक है। मतांतरण पर कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, जो मुख्य रूप से इस तथ्य पर केंद्रित हैं कि कैसे एक व्यक्ति के मतांतरण से न केवल वह व्यक्ति, अपितु पूरा समाज प्रभावित होता है। 'द आक्सफोर्ड हैंडबुक आफ रिलीजियस कन्वर्जन' पुस्तक मतांतरण की गतिशीलता की व्यापक खोज प्रस्तुत करती है। इसमें चर्चा की गई है कि कैसे मतांतरण सदियों से संस्कृतियों और व्यक्तियों को प्रभावित करता आया है। पुस्तक के संपादक लुइस आर. रेंबो लिखते हैं कि मतांतरण का प्रभाव केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। रेंबो ने मतांतरण के संबंध में कहा है कि इसके तमाम कारणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कारक 'संकटावस्था' है। चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक या फिर मनोवैज्ञानिक।

मतांतरण शायद ही कभी केवल धार्मिक विश्वासों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में बदलने तक सीमित रहा हो। सत्य तो यह है कि मतांतरण प्रायः 'पंथ' विशेष द्वारा अपनी जनसांख्यिकी को बढ़ाकर 'प्रभुत्व' स्थापित करने की मंशा से कराया जाता है, ताकि राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर वह दबाव समूह के रूप में कार्य कर सके और अपने मनोनुकूल व्यवस्थाओं को प्रभावित करे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके शिकार मुख्यतः हाशिए पर खड़े वे लोग होते हैं, जो सामाजिक भेदभाव का दंश झेल चुके हैं अथवा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक प्रलोभन एवं सामाजिक उत्थान के मकड़जाल के रूप में मतांतरण की रणनीति स्वतंत्रता पूर्व से ही भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी, जिसने भारत की जनसांख्यिकी को बहुत हद तक प्रभावित भी किया।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 'शेयर आफ रिलीजियस माइनारिटी ए क्रास कंट्री एनालिसिस' बताती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14.95 प्रतिशत तथा ईसाई आबादी का 2.24 से बढ़कर 2.36 प्रतिशत हुआ है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। 'साम दाम दंड भेद' की रणनीति अपनाकर मतांतरण की मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए 1936 में रायगढ़ रियासत द्वारा 'रायगढ़ मतांतरण अधिनियम' पारित किया गया। ऐसे ही कानून उदयपुर, कोटा और जोधपुर आदि द्वारा भी बनाए गए। बड़े पैमाने पर मतांतरण की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश ने 1954 में एक समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट ने उजागर किया कि निर्धन लोगों को बरगलाकर मतांतरण कराया जा रहा है। परिणामस्वरूप, स्वतंत्र भारत में पहला मतांतरण विरोधी कानून मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित किया गया, जिसे 'मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967' के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा मतांतरण को दंडनीय अपराध माना गया था। इसके बाद ओडिशा ने 'उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968' पारित किया। इन दोनों अधिनियमों को उनके संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी गई थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 'रेव. स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य' (1974) मामले में अधिनियम की वैधता को कायम रखा। उच्च न्यायालय ने माना कि 'बड़े पैमाने पर मतांतरण में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता है...।' उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। शीर्ष न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विचारों से सहमति प्रकट की और कहा कि 'अनुच्छेद 25 (1) के तहत किसी के मत का प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति को अपने मजहब में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है।' मतांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक और ऐतिहासिक मामला 'हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधि., 2006' है। यह अधिनियम अपने पूर्ववर्तियों से एक कदम आगे गया। इसमें जोड़ी गई धारा-4 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले सूचना देनी होगी, जो मतांतरण की सत्यता की जांच करेगा।

न्यायालय की टिप्पणियों, उनके निर्णयों और कानूनी उठापटक से इतर हमें उन सामाजिक भूमिकाओं को भी जांचना होगा, जिनके चलते आज भी छल-कपट व लोभ-लालच से मतांतरण हो रहा है। उन खामियों पर भी खुले रूप से चर्चा की जाए, जो हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को मतांतरण की ओर धकेलती हैं। यह भी स्मरण रहे कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं के योजनाबद्ध मतांतरण पर स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि 'एक हिंदू का मतांतरण केवल एक हिंदू का कम होना नहीं, बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है।'

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

शाहबानो की याद दिलाने वाला फैसला

क्षमा शर्मा

यह अफसोस की बात है कि लगभग 39 साल बाद भी कट्टर लोगों के विचार वही हैं, जो पहले थे

महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय। फाइल

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का मामला फिर चर्चा में है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि हर मत-मजहब की महिलाओं को भरण-पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उपासना पद्धति इसमें कोई रुकावट नहीं बनती। जैसा कि होता आया है, इसका स्वागत के साथ विरोध भी होने लगा। विरोध करने वालों की ओर से कहा जाने लगा कि एक ही पंथ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अदालत ने पंथों से परे सभी महिलाओं की बात की है और यह भी कहा है कि गुजारा भत्ता दान नहीं, हर तलाकशुदा महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पतियों के लिए जरूरी है कि वे पत्नियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। पति-पत्नी के नाम से संयुक्त खाते खुलवाए जाएं और एटीएम के प्रयोग का अधिकार भी महिलाओं को हो, लेकिन विरोध करने वालों को यह कहां समझ में आने वाला है। वे तो अच्छे फैसले को भी मजहब पर खतरे के रूप में प्रचारित करने लगते हैं। कई बार तो उन्हें लोगों को बरगलाने में कामयाबी भी मिल जाती है। तीन तलाक के मामले में भी इसी तरह का विरोध देखा गया था।

अफसोस है कि महिला हितों के लिए काम करने वाले संगठनों और रात-दिन अल्पसंख्यकों और महिलाओं के समर्थन में गुहार लगाने वाले लेखक-लेखिकाओं की कोई मुखर आवाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में नहीं सुनाई दी। हां, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाली जकिया सोमन और अंबर जैदी, नाइश हसन आदि ने जरूर इस फैसले का समर्थन किया। कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इसे अच्छा फैसला बताया, लेकिन कुछ ने इसे 'दीन में दखल' करार दिया। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड शरिया का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है। कुछ और भी संगठन विरोध के स्वर उभार रहे हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग महिलाओं का श्रम तो चाहते हैं, मगर उन्हें कोई अधिकार नहीं देना चाहते? वे मजहब के कोड़े से अक्सर महिलाओं को पीटते हैं और उसे सही भी बताते हैं। अधिकांश मजहब बात तो मानवता की करते हैं, पर महिलाओं के मामले में उनकी मानवता पता नहीं कहां गुम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शाहबानो, उसके साथ हुए अन्याय और वोट बैंक की राजनीति के चलते कट्टरपंथियों के समक्ष समर्पण का स्मरण हो आया। शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने यही फैसला दिया था कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मुसलमानों की नाराजगी देखते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट दिया था।

उस समय अधिकांश महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि कट्टरपंथी उनसे नाराज हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लगभग 39 साल बाद कट्टर लोगों के विचार वही हैं, जो पहले थे। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1986 में पलट दिया गया था। इसके एक साल बाद 1987 में राजस्थान के दिवराला में रूपकंवर सती हो गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 23 दिन बाद इस मसले पर कुछ बोले थे। जब भी महिलाओं के हितों की बात आती है, कट्टरपंथी एक हो जाते हैं। कई राजनीतिक दलों को लगने लगता है कि कहीं उनके वोटों का नुकसान न हो जाए, इसलिए वे मौन धारण कर लेते हैं। नेता हमेशा कट्टरपंथियों को ही पूरी कौम का प्रतिनिधि मानते हैं। एक बार अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा था कि सरकार उदारवादी मुसलमानों के मुकाबले कट्टरपंथियों की बात सुनती है। यह कट्टरपंथियों का ही असर था कि कई वर्षों बाद शाहबानो से जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि कोर्ट ने उसके समर्थन में फैसला देकर गलत किया। बाद में उसने यह भी कहा कि अगर वह ऐसा न कहती तो देश में खून की नदियां बह जातीं। यह कितने दुख की बात है कि उच्चतम न्यायालय महिलाओं के हित में कोई फैसला दे और उस कारण से खून की नदियां बहने का डर उसे ही सताने लगे, जिसके पक्ष में फैसला दिया गया हो।

जब सच्चर कमेटी का उद्धरण देते हुए यह कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है तो क्या उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल नहीं हैं, लेकिन कट्टरपंथी कई बार अपने समर्थन में कुछ महिलाओं को भी खड़ा कर लेते हैं। तीन तलाक और हिजाब के मामले में उन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसी महिलाओं का तर्क होता है कि उन्हें मजहब की बात माननी है, न कि न्यायालय की। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दशकों पहले 'वायस आफ द वायसलेस' नामक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसे सैयदा हमीद ने तैयार किया था। इसमें मुसलमान महिलाओं की स्थिति का इतना दर्दनाक चित्रण था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। सैयदा हमीद ने देश भर की तमाम मुसलमान महिलाओं से बात की थी। ये अभागी महिलाएं बीमार, बदहाल और गरीबी से परेशान थीं। इनमें से बहुत सी कोई साधन न होते हुए भी कई-कई बच्चों को पालने के लिए मजबूर थीं, क्योंकि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। कट्टरपंथी संगठनों के नेता कह रहे हैं वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे। आज नहीं तो कल, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब महिलाएं ही ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मजहबी मान्यताओं ने महिलाओं का जैसा शोषण और नुकसान किया है, वह किसी से छिपा नहीं। कट्टरपंथी अक्सर संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन आखिर यह किस तरह से संविधान को मानना और उसकी रक्षा करना है कि यदि अदालत महिलाओं के पक्ष में कोई फैसला दे तो उसके विरोध में खड़े हो जाया जाए?

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म का मार्ग

धर्म की मर्यादा को भंग करना दैवीय आज्ञा की अवज्ञा है। धर्म के मार्ग से विचलन नियति की गति की अवहेलना एवं उपेक्षा है। माया-मोह ही प्रायः व्यक्ति को धर्म की राह से विलग करने का निमित्त बनते हैं। स्मरण रहे कि माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि यह बड़ी चतुराई से व्यक्ति के भीतर अभिमान और मोह उत्पन्न कर उसे पतन की राह पर मोड़ देती है। जैसे ही व्यक्ति को मान, धन, पद और बल प्राप्त होते हैं तब माया उसे घेर कर छलती है। व्यक्ति अपने समस्त ऐश्वर्य-वैभव को अपना मान लेने की भूल कर बैठता है। जबकि देखने-सुनने और अनुभव करने में जो भी संसार आकर्षित कर रहा है, वह सब नश्वर है।

अंतःकरण की चार वृत्तियां-मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार तथा दसों इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाना ही भगवद्भक्ति है। धर्म की मर्यादा को छोड़ देना ही प्रभु अवज्ञा है। समुद्र, चंद्र और सूर्य आदि सभी धर्म की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं करते हैं। जो स्वधर्म का परित्याग करके पूजा-अर्चना करते हैं, उनकी स्तुति को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान को धर्म और उसकी मर्यादा अतिशय प्रिय है। धर्म साधन और साध्य दोनों ही है। धर्म का मन, वचन और कर्म से प्रसन्नतापूर्वक पालन करना ही प्रभु की भक्ति है। जो भी दैवीय कृपा से हमें लोक में प्राप्त हुआ है, उसका निष्काम भाव से प्रसन्नतापूर्वक सदुपयोग ही भगवद्भक्ति है।

संप्रति, स्वेच्छाचार से ही आज मानव का वैचारिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक पतन हो रहा है। इस कारण चारों ओर अशांति और परस्पर विद्रोह हावी है। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हम पर प्रसन्न हों तो हमें धर्म और उसकी मर्यादा का सर्वथा और सर्वत्र पालन करना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है। यही भक्ति धर्म के मार्ग की ओर उन्मुख करती है। धर्म का मार्ग ही ईश्वर से एकाकार कराकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।

आचार्य नारायण दास

अदृश्य पदार्थ का रहस्य

प्रदीप

ब्रह्मांड का लगभग 95 प्रतिशत भाग पदार्थ एवं ऊर्जा के अदृश्य एवं विचित्र रूप से निर्मित है जिससे हम परिचित नहीं हैं

पदार्थ और ऊर्जा के रूप में व्याप्त हमारे ब्रह्मांड के दृश्य स्वरूप का दूरबीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन विज्ञानियों को इसके प्रमाण मिले हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 95 प्रतिशत भाग पदार्थ एवं ऊर्जा के ऐसे अदृश्य और विचित्र रूप से निर्मित है जिससे हम ढंग से परिचित नहीं हैं। यही वजह है कि ब्रह्मांड के इन स्वरूपों को अदृश्य पदार्थ (डार्क मैटर) और अदृश्य ऊर्जा (डार्क एनर्जी) की संज्ञा दी गई है। अदृश्य ऊर्जा और द्रव्यमान की यह पहेली ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। हाल ही में दो विज्ञानियों ने सुझाव दिया है कि अदृश्य पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से चलने वाले कण (पार्टिकल) 'टैक्योन' से निर्मित हो सकता है।

विस्कान्सिन-मैडिसन विवि के विज्ञानी सैमुअल एच. क्रेमर और सेंट लुइस विश्वविद्यालय के इयान एच. रेडमाउंट के अनुसार, टैक्योन नामक काल्पनिक कणों ने अदृश्य पदार्थ का निर्माण किया है। हालांकि यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत (थ्योरी आफ रिलेटिविटी) की उस मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध है, जिसके अनुसार प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सर्वोच्च गति सीमा है। मालूम हो कि सर्वप्रथम भारतीय भौतिक विज्ञानी ईसीजी सुदर्शन ने टैक्योन के क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन की इस मान्यता को चुनौती दी थी कि कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। हालिया शोधपत्र में दोनों विज्ञानियों ने दावा किया है कि टैक्योन ब्रह्मांडीय घटनाओं पर अकल्पनीय प्रभाव डाल सकते हैं और यदि हम यह मान लें कि ब्रह्मांड में इन कणों का वर्चस्व है, तब भी यह विचार आधुनिक भौतिकी के ढांचे के अनुरूप होगा। दोनों ने एक नया माडल प्रस्तावित किया है जिसके मुताबिक ब्रह्मांड पहले धीमा (मंदित) होता है, फिर तेज या त्वरित होता है।

उनके अनुसार ब्रह्मांड विज्ञान का 'स्टैंडर्ड लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर माडल', जिसके अनुसार त्वरण अदृश्य ऊर्जा के कारण होता है, उसका स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रह गया है। चूंकि टैक्योन प्रकाश से भी अधिक तेज होते हैं, इसलिए उनका संयोजन गतिज ऊर्जा का एक अनूठा रूप ग्रहण कर लेता है। नया माडल सुझाता है कि टैक्योन कणों के संयोजन से अदृश्य पदार्थ का निर्माण होता है।

यदि इस माडल को मान्यता मिल जाती है, तो यह ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह अदृश्य पदार्थ की प्रकृति और आकाशगंगाओं के निर्माण में इसकी भूमिका को उजागर कर सकता है। यह ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि और आकाशगंगाओं के वितरण में हुए विसंगतियों को भी स्पष्ट कर सकता है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

जवाबदेह बनें जनप्रतिनिधि

'चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है सरकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. एके वर्मा ने नए कार्यकाल में मोदी सरकार के समक्ष संभावित चुनौतियों एवं उनके समाधानों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो यह मानने में कोई संकोच नहीं कि इस बार उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में लेखक ने सिलसिलेवार चुनौतियों को पेश कर उनके संभावित परिदृश्य का भी बखूबी आकलन किया है। निःसंदेह प्रधानमंत्री मोदी को सहयोगी दलों से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने समीकरणों को दुरुस्त करना होगा, लेकिन उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने दल के जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह एवं जिम्मेदार बनाने की होगी। पिछले कुछ समय से यही देखने में आया है कि भाजपा नेता यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे ही उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी, लेकिन इस बार के चुनावों में यह धारणा कुछ ध्वस्त होती दिखी। यह तो प्रधानमंत्री की व्यापक लोकप्रियता थी कि दस साल की सरकार के बाद भी वह अपने नेतृत्व में इतनी सीटें ले आने में सफल रहे कि सहजता से उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बन गई। इसलिए नए कार्यकाल में प्रधानमंत्री को अपने सांसदों को भी सक्रिय रखना होगा कि वे जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की तत्परता दिखाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी को हावी होती जा रही नौकरशाही की भी कोई काट तलाशनी होगी, क्योंकि अक्सर नौकरशाहों की संवेदनहीनता का खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ता है।

आशुतोष मणि त्रिपाठी, आजमगढ़

मेलबाक्स

मुस्लिम महिलाओं को नायाब तोहफा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कह दिया है कि दूसरे पंथों की तरह ही एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इस तरह के नायाब फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी जो तलाक मिलने के बाद गरीबी की जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसा ही मौका उन्हें वर्ष 1986 में भी शाहबानो केस पर कोर्ट के आदेश के बाद मिला था। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनके पति को प्रतिमाह अपनी तलाकशुदा पत्नी शाहबानो को गुजारे भत्ते के रूप में धन देना होगा। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास अपार बहुमत था। पर वह मुस्लिमों के दबाव को झेल नहीं सके, क्योंकि कांग्रेस प्रारंभ से ही तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही है। लिहाजा उसने संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बेकार कर दिया। शाहबानो सुप्रीम कोर्ट से जीतकर भी ''ठनठन गोपाल'' रह गईं, पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए कमर कसे हुए है। इसी कारण वह कोर्ट के फैसले में कोई दखल नहीं देगी। पूर्व में मोदी उनको तीन तलाक के दंश से भी मुक्ति दिला चुके हैं। निर्बल वर्ग को जो भी मकान आबंटित किए गए हैं, सब महिलाओं के नाम से हैं, तलाक होने पर उन्हें घर से निकाला नहीं जाएगा। शीघ्र ही समान सिविल कोड लागू होगा, तब मुस्लिम महिलाओं को सौत का भय नहीं सताएगा, क्योंकि तब पुरुषों को चार शादी करने की मंजूरी नहीं होगी।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

भारत-रूस की दोस्ती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा सफल रही। इस यात्रा से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का सही रूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यह देश के लिए गर्व का विषय है। यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण समझौते हुए वे भविष्य में भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस यात्रा से रूस और भारत के बीच का अविश्वास समाप्त हो गया है। साथ ही चीन और पाकिस्तान को यह संदेश भी गया कि रूस अब भी भारत का मित्र है।

नवीनचंद्र तिवारी, रोहिणी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

बदलती चुनौतियां

देश की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो रही

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गुरुवार को भारत सरकार की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े कई लिहाज से उत्साहवर्धक कहे जाएंगे कि देश के 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) को रिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से नीचे लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। TFR का आशय किसी महिला द्वारा पूरे जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या से है और रिप्लेसमेंट लेवल वह स्तर है जिस पर किसी खास समाज या क्षेत्र की आबादी संतुलित रहती है। दूसरे शब्दों में वहां जनसंख्या वृद्धि को चुनौती के रूप में लेने और उस पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं रहती।

AI Image

डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल

अपनी राह पर | भारत के संदर्भ में, यह देखना दिलचस्प है कि जनसंख्या वृद्धि को एक चुनौती के रूप में लेते हुए कैसे हम धीरे-धीरे उस स्थिति में आ गए जहां हमारे लिए चुनौती जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की उतनी नहीं, जितनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की है। खास बात यह कि हम एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर अपने रास्ते चलते हुए यहां पहुंचे हैं। हमें चीन के उन बाध्यकारी तरीकों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ी जो एक समय काफी आकर्षक माने जाते थे, पर आखिरकार बड़े हानिकारक साबित हुए।

जनगणना की ज़रूरत | हर साल की तरह इस बार भी विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी बाकायदा आंकड़े जारी कर बताया गया है कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी का अन्य देशों के मुकाबले अनुपात क्या रहेगा। इन गणनाओं की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध इसलिए भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि भारत में जनगणना के वास्तविक आंकड़े करीब डेढ़ दशक पुराने हैं। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी तक नहीं हुई है।

आंकड़ों में निरंतरता | TFR के इन आंकड़ों की खासियत यह भी है कि इसमें कोई चौंकाने वाला ट्रेंड नहीं बल्कि एक तरह की निरंतरता दिखती है। 1950 में TFR का जो आंकड़ा 6.18 पर था, वह 1990 में 4.6 पर आया और 2021 में 1.91 पर आ गया। ये आंकड़े न केवल एक राष्ट्र के रूप में हमारी हाल के दशकों में हुई ग्रोथ की पुष्टि करते हैं बल्कि परिवार और समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति भी बयान करते हैं।

आगामी चुनौती | बहरहाल, TFR कम होने का मतलब यह नहीं कि देश की आबादी में बढ़ोतरी नहीं होगी। यह अगले कई दशकों तक बढ़ती रहेगी। इस लिहाज से सरकार की मुख्य चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने की है ताकि देश को अपनी आबादी के युवा स्वरूप का अधिकाधिक फायदा मिल सके।

दो दूनी चार

लेबर चौक पर भटके हम

रमेश तिवारी

क्या आप हाल में कभी लेबर चौक गए हैं? दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में ये चौक हैं। इन चौक पर आम लोग सीधे राजमिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, कारपेंटर आदि को काम देते हैं। इन जगहों पर कामगारों की संख्या भरपूर दिख सकती है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की हो सकती है जो काम की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं हैं। जिन्होंने कभी राजमिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, कारपेंटर के औजारों का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी उस भीड़ में मौजूद हो सकते हैं। कारण? देश में कुशल कामगारों की भारी कमी दिख रही है। जिस काम में शारीरिक श्रम की प्रधानता है, उसमें कमी तो है ही। जिन कामों में शारीरिक श्रम के साथ थोड़ा स्किल भी चाहिए, वहां समस्या और गंभीर है। हाल में देश की एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म ने स्किल वाले कामगारों की कमी पर चिंता जताई तो इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई। इस फर्म ने कहा कि वो 25 से 30 हजार कामगारों की कमी का सामना कर रही है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रॉजेक्ट लेट हो रहे हैं।

ये संकट नया नहीं है। एक तरफ बेरोजगारी हमारे देश में अरसे से मुद्दा रही है, दूसरी तरफ कंपनियां कुशल कामगारों की कमी का रोना रोती रही हैं। इन दोनों के बीच रोजगार के मामले में सरकारी आंकड़े लगातार तरक्की का भरोसा दिलाते हैं। मसलन, रिजर्व बैंक ने हाल ही में रोजगार की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 4.7 करोड़ नौकरियां जोड़ी हैं। इस तरह के और भी आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन खुशनुमा तस्वीर के पीछे एक पेच है। ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में तो इसका हिसाब किताब होता है कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो सेक्टर ऑर्गनाइज्ड नहीं हैं, वहां बिल्कुल सही-सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसी के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पाया गया कि जहां फॉर्मल रोजगार नहीं, वहां 2015-16 के मुकाबले 2022-23 में कामगारों की संख्या करीब 16 लाख कम हो गई है। राष्ट्रीय आय में इस सेक्टर का योगदान कम हो गया। इकॉनमी में जो तेजी दिख रही है, वो फॉर्मल सेक्टर में रोजगार बढ़ने से दिख रही है। बाकी के जो सेक्टर हैं, उन पर 2020 में कोविड की जो मार पड़ी, उससे उबरना बाकी है।

जो लोग सोचते हैं कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है, तो इससे रोजगार की समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी, वे एक बात भूल जाते हैं। बेरोजगारी पर पिछले 50 बरसों के दौरान कई सर्वे हुए। इनसे साफ हो गया कि भारत में रोजगार की स्थिति आर्थिक विकास की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। आगे भी यही हो सकता है। सिटी रिसर्च ने 4 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इकॉनमी की विकास दर भले ही सात पर्सेंट दर्ज हो जाए, लेकिन अगले एक दशक में जितनी नौकरियों की जरूरत होगी, उसके हिसाब से ये विकास नाकाफी होगा। सरकार ने सिटी रिसर्च की बात को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ सवाल तब भी बाकी रह जाते हैं। क्या रोजगार बढ़ने के साथ प्रॉडक्टिविटी बढ़ी है। क्या रोजगार की क्वॉलिटी में बेहतरी आई है। ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि अच्छी क्वॉलिटी वाली नौकरियों की कमी है। भारत की बढ़ती युवा आबादी को देखते हुए ये बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

ऑफ दि ट्रैक

हाइड्रोजन से हवाई सफर

दिलीप लाल

ग्लोबल वॉर्मिंग के सबसे बड़े कारणों में से हैं जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम और कोयला। मुश्किल है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी इन पर टिकी है और इन्हें एक झटके में रिप्लेस नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी खबर आई है, जो जुड़ी है हाइड्रोजन को विमानों में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने से। स्वीडन की Chalmers University of Technology ने अपने देश में हाइड्रोजन ईंधन पर हो रहे काम को लेकर स्टडी की है। इसके मुताबिक, 2045 तक स्वीडन में करीब 12 सौ किलोमीटर तक की सभी हवाई सेवाओं में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगेगा। जिस तरह से डिवेलपमेंट चल रहा है, अगर सब सही रहा तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइट 2028 में उड़ान भर सकती है। स्वीडन ने हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर रिसर्च और डिवेलपमेंट पर काफी निवेश किया हुआ है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2050 तक ग्लोबल एविएशन का 30 से 40% हिस्सा हाइड्रोजन फ्यूल पर चलना शुरू कर सकता है। भले ही यह वक्त काफी दूर दिख रहा हो, लेकिन अच्छी बात है कि एक बार जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो इसमें तेजी आती जाएगी। हो सकता है कि इस दौरान इलेक्ट्रिक जैसे दूसरे विकल्प भी देखने को मिल जाएं। भारत में भी National Hydrogen programme के तहत काम चल रहा है। देश का लक्ष्य है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

पेंशनर्स की परचेजिंग पावर बाज़ार में डिमांड को मज़बूती देती है

क्या इकॉनमी पर बोझ हैं बुज़ुर्ग

दीपांकर गुप्ता

बुजुर्गों के प्रति भेदभाव को लेकर एक जोरदार अफवाह फैली हुई है। हमसे कहा जा रहा है कि बुजुर्ग लंबा जीने की जिद पाले हुए हैं। इससे उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, जिसका बोझ युवा नहीं उठा सकते। यह बात न केवल आर्थिक रूप से गलत है, बल्कि इंसानों में पाई जाने वाली मौलिक विशेषता को भी कम करके आंकती है।

AI Image

उम्र की कीमत

- इंसानों में उम्र के साथ बढ़ता है सम्मान
- ज्यादा अनुभवी पर होता है अधिक भरोसा
- तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की इकॉनमी

अनूठा है इंसान | हम इस चीज को अनदेखा कर देते हैं कि केवल हमारी प्रजाति में ही युवाओं पर बुजुर्ग हावी होते हैं। आनुवंशिक रूप से इंसानों के सबसे करीब silverback गोरिल्ला हैं। उनमें भी नेतृत्व को युवा प्रतिद्वंद्वियों के आगे झुकना पड़ता है। युवा ज्यादा मजबूत और समूह की मादाओं के लिए अधिक आकर्षक होते हैं। इस मामले में हम इंसान प्रकृति में अनूठे हैं। यहां बुजुर्गों की अधिक चलती है। अमेरिका में इस समय 75 बरस से अधिक उम्र के दो पुरुष धरती पर सबसे शक्तिशाली पद के लिए एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात की जाए तो वहां पके बालों वाले CEO ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं।

इकॉनमी में योगदान | हमारे लिए उम्र सम्मान दिलाती है, अपमान नहीं जैसा कि गोरिल्लाओं में होता है। लेकिन, सवाल है कि रिटायरमेंट और कमजोर होते शरीर का क्या? इसका जवाब है कि उस समय भी बुजुर्ग योगदान देते रहते हैं। वे अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। दवा उद्योग अपनी दवाएं बेचने के लिए बुजुर्गों पर निर्भर है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, अमेरिका में हाइपरटेंशन की दवा lisinopril हर साल लगभग 9 करोड़ बार प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी तरह से भारत में हर बरस करीब ढाई लाख घुटना प्रत्यारोपण होते हैं।

बुजुर्गों का बाज़ार | बुजुर्गों पर आधारित बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान है कि अगले सात बरसों में यह मार्केट सालाना 6.2% बढ़ सकता है। भारत में इस तरह का बाजार अब भी एक नई चीज है, लेकिन 2030 तक इसके 12 बिलियन डॉलर का हो जाने की उम्मीद है। अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है, तो भारत में बुजुर्गों की खर्च करने की क्षमता 2050 तक एक ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।

सरकार की मदद | बुजुर्ग आबादी अपने पेंशन फंड के जरिये भी इकॉनमी में योगदान देती है। इस फंड से सरकार को कम ब्याज दर पर लंबी अवधि में निवेश के लिए पैसा मिलता है। कई non-OECD देशों में पेंशन फंड की ग्रोथ ने GDP को भी पीछे छोड़ दिया है। कनाडा से लेकर युगांडा और भारत तक, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पेंशन फंड से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप करने में मदद की जा रही।

अमीर उपभोक्ता | दुनियाभर में बुजुर्ग सबसे अमीर आयु वर्ग हैं। साल 2020 में कुल उपभोक्ता वर्ग 3.9 बिलियन था। 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 5.6 बिलियन हो जाएगा। उस वक्त तक 76% बुजुर्ग इस उपभोक्ता वर्ग में शामिल होंगे। किसी भी और कैटिगरी की तुलना में उनकी संख्या 11% अधिक होगी।

खर्च में आगे | बुजुर्गों की खर्च करने की शक्ति बहुत बड़ी है। अमेरिकन थिंकटैंक Brookings की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 में बुजुर्ग 8.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे थे। 2030 तक उनकी खर्च करनेकी क्षमता 15 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। जापान में बूढ़ी होती आबादी को लेकर बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन वहां खर्च में pensioners का योगदान 40% से ज्यादा है। 2002 से यह डेटा डबल हो चुका है। सिल्वर इकॉनमी । अमेरिका में 1965 से पहले पैदा हुए लोग साल-दर-साल अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कुछ अमेरिकी silver economy को अपना गुप्त हथियार कहते हैं। यह इकॉनमी बुजुर्गों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं की होती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब देश की अर्थव्यवस्था inflation, deflation और दूसरी आर्थिक दिक्कतों में घिर जाती है। कोविड के दौरान इस सिल्वर इकॉनमी ने कई देशों के लिए सिल्वर बुलेट का काम किया होगा और संकट से उबारने में मदद की होगी।

सरकारी प्रयास | वरिष्ठ नागरिकों की अंगुली पकड़कर डिजिटल हेल्थ मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में साल 2027 तक स्वास्थ्य सेवाओं के 1.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बुजुर्गों के लिए Senior Age Growth Engine या SAGE की शुरुआत की है। इसका काम है बुजुर्गों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ावा देना।

परिवार में भूमिका | बुजुर्गों के कई दूसरे फायदे भी हैं, खासकर भारत में। यहां लगभग 48% परिवार संयुक्त हैं। इन परिवारों में वरिष्ठ नागरिक ऐसे तरीकों से योगदान करते हैं, जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जिसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। इसमें पोते-पोतियों का पालन-पोषण करना और घर को संभालना शामिल है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में हर बुजुर्ग घर के बच्चों को लोरियां ही सुना रहा है। यहां एक तिहाई वरिष्ठ नागरिक अब भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनिश्चित तारीख तक टाल दिया है। हो सकता है कि उनकी रफ्तार कम हो, लेकिन अब भी वे दौड़ में बने हुए हैं।

युवाओं पर जिम्मेदारी | बूढ़े गोरिल्ला के विपरीत इंसान अधिक उम्र में भी अपना योगदान देते हैं। इसके बाद भी उन्हें प्रगति में बाधक माना जाता है। हां, वे उतना उत्पादन नहीं करते, लेकिन खपत से उसकी भरपाई कर देते हैं। अब यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे आगे आएं और उत्पादन करें।

(लेखक समाजशास्त्री हैं)

चीन से कैसा डर

US और चीन के बीच आर्थिक दबदबे की एक जंग लैटिन अमेरिका में भी लड़ी जा रही। इस लड़ाई में चीन आगे दिख रहा है। किस तरह से उसने अपना व्यापार जमाया, पश्चिम कैसे पीछे हुआ, क्या डर है - समझते हैं इन पॉइंट में :

AI image

कैसे कसा शिकंजा

2002 में लैटिन अमेरिकी देशों संग चीन का ट्रेड 18 बिलियन डॉलर था। 2023 में यह 450 बिलियन पार हो गया। चीन सोयाबीन, पेट्रोलियम, कॉपर और दूसरे रॉ मटीरियल खरीदता है। बदले में तैयार प्रॉडक्ट भेजता है।

US क्यों पिछड़ा

फैसलों में देरी वजह है। US के साथ उरुग्वे का समझौता नहीं हो पाया तो वह चीन के पाले में चला गया। Mercosur के साथ EU का समझौता भी अटका हुआ है। चीन निवेशक बन मदद कर रहा है।

ट्रेड से चिंता क्यों

पेइचिंग के साथ व्यापार को लेकर यह चिंता जताई जा रही है कि वह अपने यहां के सस्ते सामानों से लैटिन अमेरिका के मार्केट को पाट रहा है। वह इस क्षेत्र के 21 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। कई के साथ बात चल रही है। ये सभी उसके Belt and Road Initiative का हिस्सा हैं। व्यापार बढ़ाने की आड़ में वह देशों को BRI में शामिल कर रहा है।

कर्ज का जाल

BRI का हिस्सा बनाकर चीन धड़ाधड़ कर्ज बांट रहा है। कर्ज देने के मामले में पिछले डेढ़ दशक से चीन के बैंक इस रीजन में सबसे आगे हैं। डिवेलपमेंट और ट्रेड के नाम पर लैटिन अमेरिका की सरकारों को चीन अब तक 137 बिलियन डॉलर दे चुका है।

खतरा कितना बड़ा

चीनी कर्ज की शर्तें गुप्त होती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई लैटिन अमेरिकी देश कर्ज की शर्तों को रिवाइज करना चाहते हैं। प्रभाव वाले देशों में चीन अपने मतलब के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। इससे सुरक्षा को लेकर चिंता जगी है।

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

लिखने का अब कोई असर नहीं दिख रहा

*'काशी का अस्सी' जैसी कालजयी कृति के रचनाकार काशीनाथ सिंह अब 87 वर्ष के हो चुके हैं, और स्वस्थ हैं। **प्रो. अनिल कुमार सिंह** ने उनसे समय, साहित्य, संसार और सिद्धांतों पर लंबी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :*

Shital Verma

सप्ताह का इंटरव्यू

काशीनाथ सिंह

> ये खतरे जो आज आ गए हैं और चल रहे हैं 21वीं सदी में, ऐसे खतरे की कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने। यह जरूर कहूंगा कि इन सबके बीच राहुल गांधी जो कर रहा है, कहीं कोई घपला नहीं किया उसने। वैचारिक घपला भी नहीं किया है। आज नहीं तो कल हो सकता है वह महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की परंपरा में आए

■ इस साल हरिशंकर परसाई का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है...।

परसाई रेलीवेंट रहेंगे। आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। जिस तरह की चीजों को लेकर वह आम जनता की समस्याओं पर लिखा करते थे और पार्टियों पर प्रहार किया करते थे, वो सारी चीजें आज भी अपूर्ण हैं।

■ आप जीवन भर प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे हैं। पार्टियों की बात करें तो आपको क्या लगता है, वामपंथी पार्टियों, वामपंथी राजनीति या प्रगतिशील लेखक संघ की क्या भूमिका है? अभी वे समय के साथ कितना चल पा रहे हैं?

सारी राजनीतिक पार्टियां उन सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, जिन पर वे बनी थीं। सब की सब छोड़ चुकी हैं। सब सत्ता में सीधे भागीदारी चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। सब कुछ एक तरह की नौकरी है।

■ लेखक संगठनों की पहल नहीं दिखती है। लोग पॉप्युलर पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं। इतना सारा लिखा जा रहा है, फिर भी समाज में कोई बौद्धिक उद्वेलन क्यों नहीं दिखाई देता?

जब लिटरेरी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, तब उसका सिद्धांत हुआ करता था मार्क्सवाद का। चाहे जनवादी लेखक संघ हो, प्रगतिशील लेखक संघ हो या जन संस्कृति मंच हो, इनकी प्रासंगिकता खत्म तो नहीं हुई, पर कम हो गई।

■ एक तो राजनीति दूर गई लेखकों से, फिर साहित्य-संस्कृति कर्म भी। क्या आपको लगता है कि गणेश परिक्रमा करके जो लीडरशिप में आए हैं, वे विश्वास नहीं हासिल कर पाए लोगों का? क्या ऐसे लोगों की बात का कोई प्रभाव पड़ता है?

कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कि इन सारे लेखक संगठनों का जनता से कोई संपर्क नहीं रह गया है।

■ लोगों के बीच एक संस्कृतिकर्मी के रूप में जाने की परंपरा खत्म हो गई। अब तो दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, उसी को सबसे बड़ा प्रतिरोध मान लेते हैं। आपको क्या लगता है, इसकी वजह से फर्क पड़ा है?

लिखने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। छपने वाले भी ज्यादा हो गए हैं। चीजें पढ़ी जा रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। हां, उनका इंपैक्ट किसी के निजी जीवन पर पड़ता हो तो हो, उसका कोई सामाजिक रूप दिखाई नहीं पड़ता है।

■ आपको लिखते हुए आधी सदी से भी ज्यादा हो रहा है। देश की राजनीतिक स्थितियां कितनी बदली हैं? आज के समय को आप कैसे देखते हैं?

देखो, ये खतरे जो आज आ गए हैं और चल रहे हैं 21वीं सदी में, ऐसे खतरे की कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने। यह जरूर कहूंगा कि इन सबके बीच राहुल गांधी जो कर रहा है, संभवतः सही रास्ते पर चलता रहा ईमानदारी से। यह भी कह सकता हूं कि कहीं कोई घपला नहीं किया उसने। वैचारिक घपला भी नहीं किया है। आज नहीं तो कल हो सकता है वह महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की परंपरा में आए। काफी ज्यादा उम्मीदें रखी है मैंने। पार्टी में बदलाव लाएगा तो वह देश की राजनीति बदल सकता है।

■ 1967-68 में जब पूरी दुनिया में छात्र राजनीति का उभार था, उसी वक्त आपका उपन्यास 'अपना मोर्चा' आया था। उसमें छात्र राजनीति की एक दिशा दिखाई देती है...।

उस समय पूरी दुनिया में छात्र राजनीति का उभार था। फ्रांस में छात्रों ने खुद आंदोलन की अगुवाई की थी। जापान में आंदोलन हुए थे, कोरिया में हो रहे थे। इन्हीं कारणों से उस उपन्यास का जापानी और कोरियाई में अनुवाद भी हुआ।

■ लोगों को कुछ वैचारिक या भाषिक उत्तेजना से भरा हुआ चाहिए। एक रचनाकार की जो तटस्थ रचनाशीलता है या जो भाषा का विस्तार है, वह नहीं चाहिए। क्या यही वजह है कि आजकल लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है?

दरअसल पूंजीवादी देशों में साहित्य का जो हाल है, वही स्थिति इसकी भारत में भी हो गई है। 'अपना मोर्चा' का जिक्र तुमने किया, वरना आज उसका जिक्र कोई करता नहीं। हां, चूंकि नरेंद्र मोदी काशी से जुड़े हैं, इसलिए 'काशी का अस्सी' पर कुछ नाटक-वाटक हुआ, उससे जुड़ाव चल रहा है लोगों का।

■ नई पीढ़ी के बारे में आपकी क्या राय है? साहित्य और शब्दों के प्रति इसके कमिटमेंट को आप कैसे देखते हैं?

जिनके बारे में नहीं लिखा जा रहा था, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, हमें लगता है कि नई पीढ़ी उसे सामने लाई है। जैसे आदिवासी जीवन है, जनजीवन है- ये चीजें जो आ रही हैं उनके बीच से, ये आकृष्ट कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं। 60 के जमाने में जब हम भी आदिवासी थे गांव में, तो जो गांव के लोग थे, वे चीजें आ रही हैं। लेकिन ये जो ज्ञान बघार रहे हैं कविताओं में लोग, इनमें मेरी दिलचस्पी नहीं है।

■ आपकी एक लंबी कहानी थी महुआ चरित्र। उसे लेकर काफी विवादास्पद स्वर भी थे। एक होता है सहज जीवन का चित्रण, और एक होता है पॉलिटिकली लोडेड। इससे क्या फर्क पड़ता है?

अनिल, क्या बात है आज? किस मूड में हो भाई तुम? हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी दिलचस्पी मुझमें होगी, या तुम मेरी चीजें पढ़ रहे होगे। तुमसे बातें करके अच्छा लगा। हमारे साथ के अधिकांश लोग जा चुके हैं। ज्ञानरंजन जीवित रह गए हैं। बाकी तो सब के सब चले गए।

■ क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल?

मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं पांच-छह साल से। परेशान हूं। इस बीच सुभाष राय की किताब 'अक्क महादेवी' पढ़ी मैंने। वह बहुत महत्वपूर्ण किताब है। शांति पर्व में कविता संग्रह दिया था। प्रतिरोध की कविताएं भी हैं। कुछ कविताएं निजी ज्यादा लगती हैं।

मार-मार कर सब बनते राजा

पिछले दिनों एक समर कैंप में कहानी सुनाने के लिए जाना हुआ। एक बड़े हाल में बहुत से बच्चे थे। कइयों के माता-पिता भी साथ आए थे। आम तौर पर बच्चों को वे कहानियां पसंद नहीं आतीं, जो उन्हें किसी किताब से सुनाई जाएं। वे उन कहानियों को पसंद करते हैं, जो उनके साथ बुनी जाएं। जिन्हें आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी हो। मैंने भी कुछ ऐसा ही करते हुए एक कहानी शुरू की, जिसमें एक जंगल था। जंगल में एक गुफा थी। उसमें एक शेर रहता था। शेर जंगल के दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता था। फिर.. फिर क्या हुआ? एक बच्चे ने कहा- एक दिन वहां एक ड्रेगन आ गया। ड्रेगन के मुंह से आग निकल रही थी। एक बच्ची बोली- ड्रेगन के डर से सारे जानवर भाग गए, छिप गए। आगे क्या हुआ?

एक बच्चे ने जोर से कहा- ड्रेगन चलते-चलते शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। ड्रेगन गुफा के बाहर खड़ा हो गया। उसके मुंह की लपटें गुफा के अंदर जाने लगीं। शेर बाहर आया तो ड्रेगन उस पर झपटा और शेर को मार डाला। फिर दूसरे बच्चे ने कहानी आगे बढ़ाई- अब ड्रेगन जंगल का राजा बन गया। वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। सारे जानवर उससे परेशान थे। थोड़े दिनों बाद वहां एक टी रेक्स (मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति) आया। ड्रेगन उस पर भी झपटा। लेकिन टी रेक्स के नुकीले दांतों के आगे उसकी एक न चली और टी रेक्स ने उसे मार डाला।

खुद अपनी आंख से

क्षमा शर्मा

यह कहानी बच्चों ने बुनी। देखने वाली बात यह थी कि इस कहानी में सब एक-दूसरे को मार रहे थे। इसमें ऐसा भी हो सकता था कि ड्रेगन शेर का दोस्त बन जाता और दोनों मिलकर टी रेक्स का मुकाबला करते और उसे जंगल से भगा देते। या टी रेक्स की जगह कोई और जानवर होता जो जंगल में शांति का संदेश देता। आखिर बच्चों को इतनी मारामारी और हिंसा कैसे पसंद आने लगी, जिसमें प्रेम और मिल-जुलकर रहने की कोई जगह ही नहीं बची?

क्या इसकी एक वजह यह हो सकती है कि बच्चे तमाम माध्यमों जैसे कि टीवी , कंप्यूटर, फिल्मों में हिंसा से भरे दृश्य ही देख रहे हैं? अधिकांश कार्टून भी ऐसे ही होते हैं। घर के बड़े इस पर ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा क्या देख रहा है। इन दिनों बच्चों के लिए माता-पिता के पास भी बहुत कम समय बचा है। जीवन की आपाधापी ने बच्चों को केंद्र में नहीं रहने दिया है। अरसे से विशेषज्ञ इस ओर इंगित कर रहे हैं कि बच्चे अगर बचपन से ही हिंसा से भरे दृश्य देखते हैं, तो हिंसा उनके जीवन का अंग बन जाती है।

बच्चों की कहानियों का मतलब चाहे सीधे-सीधे तरीके से उन्हें उपदेश देना न हो, मगर जीवन के अच्छे मूल्यों के प्रति उनमें सुरुचि जगाना जरूर होता है। ऐसे संस्कार बच्चों को घर और स्कूल से तो मिल ही सकते हैं। तमाम माध्यमों को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ियों से खिलवाड़ न करें। बच्चे को हिंसा और नफरत सिखाने के मुकाबले उनमें कोमल चीजों के प्रति लगाव जगाएं। तभी समाज के प्रति भी सही दायित्व को निभाया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग सेशंस भी इसमें कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

चलते-चलते...

अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने एक डिवाइस डिवेलप कर लचीले रोबॉट बनाए हैं। इसे बनाने में रबर का इस्तेमाल हुआ और 3D प्रिंटर की मदद ली गई। यह डिवाइस बिल्कुल किसी इंसानी मांसपेशी जैसी है, जो सिकुड़ और फैल सकती है। इंजीनियरों ने इससे एक रोबॉट बनाकर उसका सफल प्रयोग किया है। मटीरियल से बने रोबॉट ज्यादा सुरक्षित होंगे।

रीडर्स मेल

फैसले का सम्मान

12 जुलाई का संपादकीय 'कानून को मिला तेवर' पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब इन महिलाओं को भी पति के तलाक देने के बाद गुजरा भत्ता लेने का हक मिल गया है। इस फैसले से समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे इस बात को बल मिलता है कि भारत का संविधान किसी पंथ, मजहब विशेष के हिसाब से नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। अब समाज की जिम्मेदारी है कि इन महिलाओं को जागरूक करे ताकि वे अपने हित के लिए आवाज बुलंद कर सकें। यह भी कहा जा सकता है कि जब संविधान में हर धर्म-जाति के लोगों को एक समान अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान है, तो सबके लिए समान कानून लागू करने में सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर कोई रीती-रिवाज या परंपरा किसी पर अत्याचार का कारण बने, तो उस पर हस्तक्षेप करना और न्याय दिलाना सरकार और समाज, दोनों की जिम्मेदारी बनती है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

AI की ज़रूरत

यह पत्र 12 जुलाई के लेख 'कला जगत AI से इतना डर क्यों रहा है' से संबंधित है। रोजी-रोटी जाने का डर किन्हें नहीं सताता? लेकिन विज्ञान के नफा-नुकसान पर भी गौर करने की जरूरत है। सिर्फ एक पहलू को देखकर AI को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। जब विकास की बात होगी, तो बदलाव होना स्वाभाविक है। इस बदलाव से किसी को फायदा मिलता है, किसी के लिए वह चुनौती बन जाता है। आजकल AI की खूब चर्चा हो रही है। इससे डरने नहीं, बल्कि इसे अपनाने की जरूरत है। जब कंप्यूटर आया, तब भी बातें उड़ी थीं कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लोगों ने कहा था कि इंसानों का सारा काम मशीनें करने लगेंगी। कंप्यूटर से हमारा काम आसान ही हुआ है। इसने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। कई ऐसे सेक्टर खड़े हो गए, जिनमें बड़ी तादाद में प्रफेशनल्स काम कर रहे हैं। आर्टिफिशल टेक्नॉलजी भी इसी तरह की क्रांति ला सकती है।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संविधान हत्या दिवस

केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी कर यही स्पष्ट किया कि वह विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी कि भाजपा संविधान बदलने का इरादा रखती है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि मोदी सरकार ने 49 साल पहले 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल थोपे जाने के इंदिरा गांधी के मनमाने फैसले को संविधान को कुचलने वाले कदम के रूप में स्मरण करने का निर्णय केवल इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में देश भर में घूम-घूम कर यह दुष्प्रचार कर लोगों को बरगलाया कि यदि भाजपा का चार सौ पार का नारा सही सिद्ध हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। यह निर्णय संभवतः इसलिए भी लिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी कांग्रेस और उसके साथी दल यह खोखला दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने संविधान की रक्षा की। निःसंदेह 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन शायद मोदी सरकार के लिए ऐसा कोई फैसला लेना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि अभी हाल में जब आपातकाल की बरसी पर इंदिरा सरकार की ओर से की गईं ज्यादतियों का स्मरण किया जा रहा था तो कांग्रेस ने यही दिखाया कि उसे यह रास नहीं आ रहा है। हद तो तब हो गई, जब आपातकाल के विरोध में लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस के नकारात्मक रवैये को देखते हुए इसकी आवश्यकता स्वतः रेखांकित होने लगी थी कि उस काले दौर को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने तो आपातकाल के अलावा भी संविधान की अनदेखी करने वाले फैसले लिए हैं। क्या यह एक तथ्य नहीं कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के फैसले को पलटना संविधान का नग्न निरादर ही था? सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से देश को यह अच्छी तरह स्मरण भी हो आया। कांग्रेस संविधान को भाजपा और विशेष रूप से मोदी सरकार से खतरे का कितना ही हौवा खड़ा करे, सच यह है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन उसने ही किए हैं और वह भी विपक्ष की अनदेखी करके। इसके विपरीत मोदी सरकार ने बीते दस वर्षों में जो भी संविधान संशोधन किए, उनमें से हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया-वह चाहे जीएसटी संबंधी हो या फिर निर्धन सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का।

विनम्रता कमजोरी नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी अधिकारी से किसी काम को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए पैर तक पकड़ने का प्रस्ताव देते हैं तो इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया होती है। विपक्ष की नजर में यह मुख्यमंत्री की कमजोरी है तो शालीन व्यवहार के पक्षधर लोग इसमें नीतीश की विनम्रता की पराकाष्ठा देखते हैं। यह सही भी है कि विनयशीलता भी शक्ति संपन्न लोगों का आभूषण है। कमजोरों के पास तो विनम्र रहने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहता है। यह आम लोगों पर निर्भर करता है कि वे मुख्यमंत्री की विनयशीलता को किस रूप में ग्रहण करते हैं। कमजोरी नहीं होती विनम्रता लेकिन, मुख्यमंत्री जिस समूह को काम करवाने के लिए पैर तक छूने का प्रस्ताव देते हैं, उस समूह को तो इसकी गंभीरता समझनी ही चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में अगर मुख्यमंत्री क्रोधित हो जाएं तो शक्तिसंपन्न अफसरशाही के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। हाल के दिनों में जिन दो कार्यों में सुस्ती को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के पांव पकड़ने या छूने की इच्छा की है, उनके कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी का कोई कारण नजर नहीं आता है। किसी काम में धन की कमी सबसे बड़ी बाधा मानी जा सकती है। लेकिन, विशेष भूमि सर्वेक्षण और गंगा पथ के निर्माण में धन की कमी को कभी बाधा के रूप में नहीं देखा गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए जितने मानव संसाधन की मांग की, सरकार ने उनके नियोजन के लिए धन दिया। धन के मामले में यही व्यवहार गंगा पथ के साथ भी किया गया। इसके बावजूद अगर समय पर काम पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से कार्यान्वयन के लिए निर्मित तंत्र में ही खोट है। भूमि सर्वेक्षण का विषय संवेदनशील है और इसके न पूरा होने से पूरा सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है।

> यह आम लोगों पर निर्भर करता है कि वे मुख्यमंत्री की विनयशीलता को किस रूप में ग्रहण करते हैं

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अब मोदी सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर देना चाहिए?

आज का सवाल
क्या आपातकाल के स्मरण में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला सही है?

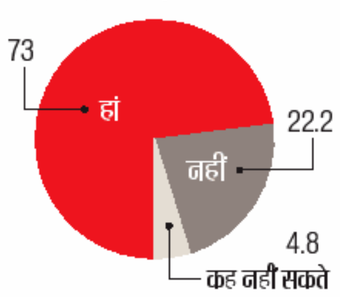

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मतांतरण की खतरनाक चुनौती

डा. ऋतु सारस्वत

किसी व्यक्ति के मतांतरण से न केवल मतांतरित हुआ वह व्यक्ति, अपितु पूरा समाज प्रभावित होता है

बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मतांतरण पर कठोर टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा, 'यदि मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी।' न्यायालय ने यह भी कहा कि मत प्रचार-प्रसार की तो छूट है, लेकिन मतांतरण की अनुमति नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है कि मतांतरण के संबंध में न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पूर्व नवंबर 2022 में भी उच्चतम अदालत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जबरन मतांतरण के संबंध में कहा था 'यह अंततः राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों के अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है।' देश के विभिन्न न्यायालयों ने जबरन मतांतरण को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके पीछे तथ्यात्मक एवं ठोस कारण हैं।

यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके 'पथ' जिसे संवैधानिक एवं न्यायिक भाषा में 'धर्म' भी कहा जाता है, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। विश्व भर में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है, जो किसी न किसी पंथ के अनुयायी हैं और अपने मत विशेष में न केवल आस्था रखते हैं, बल्कि उसे 'जीवन निर्देशक' के रूप में स्वीकार करके अपनी जीवन प्रणाली को उसकी मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुरूप संचालित करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ही नहीं अधिकांश देशों में 'पंथ' मात्र आस्था का विषय नहीं, अपितु व्यक्ति की पहचान का द्योतक भी है और इस पहचान को परिवर्तित करने का निर्णय यदि एकाएक हो तो कई प्रश्नों का खड़ा होना स्वाभाविक है। मतांतरण पर कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, जो मुख्य रूप से इस तथ्य पर केंद्रित हैं कि कैसे एक व्यक्ति के मतांतरण से न केवल वह व्यक्ति, अपितु पूरा समाज प्रभावित होता है। 'द आक्सफोर्ड हैंडबुक आफ रिलीजियस कन्वर्जन' पुस्तक मतांतरण की गतिशीलता की व्यापक खोज प्रस्तुत करती है। इसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे मतांतरण सदियों से दुनिया भर में समाजों, संस्कृतियों और व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित करता आया है। पुस्तक के संपादक लुइस आर. रेंबो लिखते हैं कि मतांतरण का प्रभाव केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। रेंबो ने मतांतरण के संबंध में कहा है कि इसके तमाम कारणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कारक 'संकटावस्था' है। चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक या फिर मनोवैज्ञानिक।

इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि मतांतरण शायद ही कभी केवल धार्मिक विश्वासों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में बदलने तक सीमित रहा हो। सत्य तो यह है कि मतांतरण प्रायः 'पंथ' विशेष द्वारा

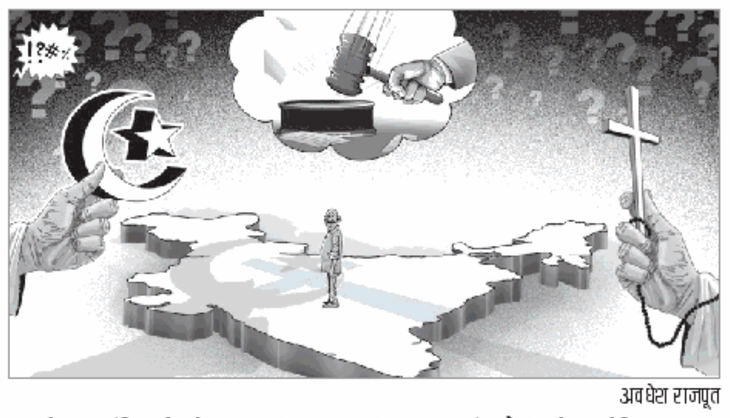

अवधेश राजपूत

अपनी जनसांख्यिकी को बढ़ाकर 'प्रभुत्व' स्थापित करने की मंशा से कराया जाता है, ताकि राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर वह दबाव समूह के रूप में कार्य कर सके और अपने मनोनुकूल व्यवस्थाओं को प्रभावित करे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके शिकार मुख्यतः हाशिए पर खड़े वे लोग होते हैं, जो सामाजिक भेदभाव का दंश झेल चुके हैं अथवा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक प्रलोभन एवं सामाजिक उत्थान के मकड़जाल के रूप में मतांतरण की रणनीति स्वतंत्रता पूर्व से ही भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी, जिसने भारत की जनसांख्यिकी को बहुत हद तक प्रभावित भी किया।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 'शेयर आफ रिलीजियस माइनारिटी ए क्रास कंट्री एनालिसिस' बताती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14.95 प्रतिशत तथा ईसाई आबादी का 2.24 प्रतिशत से बढ़कर 2.36 प्रतिशत हुआ है। आंकड़ों की यह तस्वीर स्वयं में बहुत कुछ स्पष्ट कर रही है। 'साम दाम दंड भेद' की रणनीति अपनाकर मतांतरण की मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए 1936 में रायगढ़ रियासत द्वारा 'रायगढ़ मतांतरण अधिनियम' पारित किया गया। ऐसे ही कानून उदयपुर, कोटा और जोधपुर आदि द्वारा भी बनाए गए। बड़े पैमाने पर मतांतरण की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश ने 1954 में एक समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट ने उजागर किया कि निर्धन लोगों को बरगलाकर मतांतरण कराया जा रहा है। परिणामस्वरूप, स्वतंत्र भारत में पहला मतांतरण विरोधी कानून मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित किया गया, जिसे 'मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967' के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा मतांतरण को दंडनीय अपराध माना गया था। इसके बाद ओडिशा ने 'उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968' पारित किया। इन दोनों अधिनियमों को उनके संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी गई थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 'रेव. स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य' (1974) मामले में अधिनियम की वैधता को कायम रखा। उच्च न्यायालय ने माना कि 'बड़े पैमाने पर मतांतरण में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता है...।' उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। शीर्ष न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विचारों से सहमति प्रकट की और कहा कि 'अनुच्छेद 25 (1) के तहत किसी के मत का प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति को अपने मजहब में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है।' मतांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक और ऐतिहासिक मामला 'हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधि., 2006' है। यह अधिनियम अपने पूर्ववर्तियों से एक कदम आगे गया। इसमें जोड़ी गई धारा-4 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले सूचना देनी होगी, जो मतांतरण की सत्यता की जांच करेगा।

न्यायालय की टिप्पणियों, उनके निर्णयों और कानूनी उठापटक से इतर हमें उन सामाजिक भूमिकाओं को भी जांचने की आवश्यकता है, जिनके चलते आज भी छल-कपट और लोभ-लालच से मतांतरण हो रहा है। यह भी जरूरी है कि उन खामियों पर खुले रूप से चर्चा की जाए, जो हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को मतांतरण की ओर धकेलती हैं। यह भी स्मरण रहे कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं के योजनाबद्ध मतांतरण पर स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि 'एक हिंदू का मतांतरण केवल एक हिंदू का कम होना नहीं, बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है।'

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)
response@jagran.com

शाहबानो की याद दिलाने वाला फैसला

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का मामला फिर चर्चा में है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि हर मत-मजहब की महिलाओं को भरण-पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उपासना पद्धति इसमें कोई रुकावट नहीं बनती। जैसा कि होता आया है, इसका स्वागत के साथ विरोध भी होने लगा। विरोध करने वालों की ओर से कहा जाने लगा कि एक ही पंथ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अदालत ने पंथों से परे सभी महिलाओं की बात की है और यह भी कहा है कि गुजारा भत्ता दान नहीं, हर तलाकशुदा महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पतियों के लिए जरूरी है कि वे पत्नियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। पति-पत्नी के नाम से संयुक्त खाते खुलवाए जाएं और एटीएम के प्रयोग का अधिकार भी महिलाओं को हो, लेकिन विरोध करने वालों को यह कहां समझ में आने वाला है। वे तो अच्छे फैसले को भी मजहब पर खतरे के रूप में प्रचारित करने लगते हैं। कई बार तो उन्हें लोगों को बरगलाने में कामयाबी भी मिल जाती है। तीन तलाक के मामले में भी इसी तरह का विरोध देखा गया था।

अफसोस है कि महिला हितों के लिए काम करने वाले संगठनों और रात-दिन अल्पसंख्यकों और महिलाओं के समर्थन में गुहार लगाने वाले लेखक-लेखिकाओं की कोई मुखर आवाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में नहीं सुनाई दी। हां, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाली जकिया सोमन और अंबर जैदी, नाइश हसन आदि ने जरूर इस फैसले का समर्थन किया। कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इसे अच्छा फैसला बताया, लेकिन कुछ ने इसे 'दीन में दखल' करार दिया। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड शरिया का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है। कुछ और भी संगठन विरोध के स्वर उभार रहे हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग महिलाओं का श्रम तो चाहते हैं, मगर उन्हें कोई अधिकार नहीं देना चाहते? वे मजहब के कोड़े से अक्सर महिलाओं को पीटते हैं और उसे सही भी बताते हैं। अधिकांश मजहब बात तो मानवता की करते हैं, पर महिलाओं के मामले में उनकी मानवता पता नहीं कहां गुम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शाहबानो, उसके साथ हुए अन्याय और वोट बैंक की राजनीति के चलते कट्टरपंथियों के समक्ष समर्पण का स्मरण हो आया। शाहबानो

शमा शर्मा

यह अफसोस की बात है कि लगभग 39 साल बाद भी कट्टर लोगों के विचार वही हैं, जो पहले थे

महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ● फाइल

मामले में उच्चतम न्यायालय ने यही फैसला दिया था कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मुसलमानों की नाराजगी देखते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट दिया था।

उस समय अधिकांश महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि कट्टरपंथी उनसे नाराज हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लगभग 39 साल बाद कट्टर लोगों के विचार वही हैं, जो पहले थे। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1986 में पलट दिया गया था। इसके एक साल बाद 1987 में राजस्थान के दिवराला में रूपकंवर सती हो गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 23 दिन बाद इस मसले पर कुछ बोले थे। जब भी महिलाओं के हितों की बात आती है, कट्टरपंथी एक हो जाते हैं। कई राजनीतिक दलों को लगने लगता है कि कहीं उनके वोटों का नुकसान न हो जाए, इसलिए वे मौन धारण कर लेते हैं। नेता हमेशा कट्टरपंथियों को ही पूरी कौम का प्रतिनिधि मानते हैं। एक बार अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा था कि सरकार उदारवादी मुसलमानों के मुकाबले कट्टरपंथियों की बात सुनती है। यह कट्टरपंथियों का ही असर था कि कई वर्षों बाद शाहबानो से जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि कोर्ट ने उसके समर्थन में फैसला देकर गलत किया। बाद में उसने यह भी कहा कि अगर वह ऐसा न कहती तो देश में खून की नदियां बह जातीं। यह कितने दुख की बात है कि उच्चतम न्यायालय महिलाओं के हित में कोई फैसला दे और उस कारण से खून की नदियां बहने का डर उसे ही सताने लगे, जिसके पक्ष में फैसला दिया गया हो।

जब सच्चर कमेटी का उद्धरण देते हुए यह कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है तो क्या उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल नहीं हैं, लेकिन कट्टरपंथी कई बार अपने समर्थन में कुछ महिलाओं को भी खड़ा कर लेते हैं। तीन तलाक और हिजाब के मामले में उन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसी महिलाओं का तर्क होता है कि उन्हें मजहब की बात माननी है, न कि न्यायालय की। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दशकों पहले 'वायस आफ द वायसलेस' नामक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसे सैयदा हमीद ने तैयार किया था। इसमें मुसलमान महिलाओं की स्थिति का इतना दर्दनाक चित्रण था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। सैयदा हमीद ने देश भर की तमाम मुसलमान महिलाओं से बात की थी। ये अभागी महिलाएं बीमार, बदहाल और गरीबी से परेशान थीं। इनमें से बहुत सी कोई साधन न होते हुए भी कई-कई बच्चों को पालने के लिए मजबूर थीं, क्योंकि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। कट्टरपंथी संगठनों के नेता कह रहे हैं वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे। आज नहीं तो कल, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब महिलाएं ही ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मजहबी मान्यताओं ने महिलाओं का जैसा शोषण और नुकसान किया है, वह किसी से छिपा नहीं। कट्टरपंथी अक्सर संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन आखिर यह किस तरह से संविधान को मानना और उसकी रक्षा करना है कि यदि अदालत महिलाओं के पक्ष में कोई फैसला दे तो उसके विरोध में खड़े हो जाया जाए?

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म का मार्ग

धर्म की मर्यादा को भंग करना दैवीय आज्ञा की अवज्ञा है। धर्म के मार्ग से विचलन नियति की गति की अवहेलना एवं उपेक्षा है। माया-मोह ही प्रायः व्यक्ति को धर्म की राह से विलग करने का निमित्त बनते हैं। स्मरण रहे कि माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि यह बड़ी चतुराई से व्यक्ति के भीतर अभिमान और मोह उत्पन्न कर उसे पतन की राह पर मोड़ देती है। जैसे ही व्यक्ति को मान, धन, पद और बल प्राप्त होते हैं तब माया उसे घेर कर छलती है। व्यक्ति अपने समस्त ऐश्वर्य-वैभव को अपना मान लेने की भूल कर बैठता है। जबकि देखने-सुनने और अनुभव करने में जो भी संसार आकर्षित कर रहा है, वह सब नश्वर है। यह कभी न भूलें कि वास्तविक आनंद केवल भगवद्भक्ति में निहित है।

अंतःकरण की चार वृत्तियां-मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार तथा दसों इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाना ही भगवद्भक्ति है। धर्म की मर्यादा को छोड़ देना ही प्रभु अवज्ञा है। समुद्र, चंद्र और सूर्य आदि सभी धर्म की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं करते हैं। जो स्वधर्म का परित्याग करके पूजा-अर्चना करते हैं, उनकी स्तुति को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान को धर्म और उसकी मर्यादा अतिशय प्रिय है। धर्म साधन और साध्य दोनों ही है। धर्म का मन, वचन और कर्म से प्रसन्नतापूर्वक पालन करना ही प्रभु की भक्ति है। जो भी दैवीय कृपा से हमें लोक में उपलब्ध हुआ है, उसका निष्काम भाव से प्रसन्नतापूर्वक सदुपयोग ही भगवद्भक्ति है।

संप्रति, स्वेच्छाचार से ही आज मानव का वैचारिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक पतन हो रहा है। इस कारण चारों ओर अशांति और परस्पर विद्रोह हावी है। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हम पर प्रसन्न हों तो हमें धर्म और उसकी मर्यादा का सर्वथा और सर्वत्र पालन करना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है। यही भक्ति धर्म के मार्ग की ओर उन्मुख करती है। धर्म का मार्ग ही ईश्वर से एकाकार कराकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

जवाबदेह बनें जनप्रतिनिधि

'चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है सरकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. एके वर्मा ने नए कार्यकाल में मोदी सरकार के समक्ष संभावित चुनौतियों एवं उनके समाधानों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो यह मानने में कोई संकोच नहीं कि इस बार उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में लेखक ने सिलसिलेवार चुनौतियों को पेश कर उनके संभावित परिदृश्य का भी बखूबी आकलन किया है। निःसंदेह प्रधानमंत्री मोदी को सहयोगी दलों से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने समीकरणों को दुरुस्त करना होगा, लेकिन उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने दल के जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह एवं जिम्मेदार बनाने की होगी। पिछले कुछ समय से यही देखने में आया है कि भाजपा नेता यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे ही उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी, लेकिन इस बार के चुनावों में यह धारणा कुछ ध्वस्त होती दिखी। यह तो प्रधानमंत्री की व्यापक लोकप्रियता थी कि दस साल की सरकार के बाद भी वह अपने नेतृत्व में इतनी सीटें ले आने में सफल रहे कि सहजता से उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बन गई। इसलिए नए कार्यकाल में प्रधानमंत्री को अपने सांसदों को भी सक्रिय रखना होगा कि वे जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की तत्परता दिखाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी को हावी होती जा रही नौकरशाही की भी कोई काट तलाशनी होगी, क्योंकि अक्सर नौकरशाहों की संवेदनहीनता का खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ता है।

आशुतोष मणि त्रिपाठी, आजमगढ़

मां के नाम पेड़ और उजड़ते पहाड़

एक ओर इन दिनों देश भर में अपनी मां के नाम पेड़ लगाने की होड़ लगी है। साथ में हमें प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारी मां की तरह हमेशा हमें संभालती है, हमें पोषित करती है, हमें सुरक्षित रखती है। पेड़ों और पहाड़ों का महत्व समझने के लिए हमें समय-समय पर पेड़-पौधों और पहाड़ों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। आज 'भारत का मुकुट' कहा जाने वाला हिमालय लगातार उजड़ रहा है। इसका कारण है, पेड़ों की अनवरत कटाई और वहां विकास का पर्याय बन चुका पर्यटन। पहाड़ों की प्राकृतिक सुषमा को निहारने के लिए आने वालों से लेकर इस पर्वत शृंखला में स्थित आस्था के केंद्रों के दर्शन को लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, परंतु वे पर्वतों की नैसर्गिकता को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ राजमार्ग कई दिनों से भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। पेड़ और पहाड़ों की बढ़ती दुर्दशा के पीछे कई कारण हैं, जैसे वन्य जीवों के निवास स्थलों का संकुचन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग। पर्वतों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, रोमांचक खेल आदि के नाम पर लाखों पेड़ों को काटा गया। रास्ते चौड़े करने के लिए भी उनकी बलि ली गई। हमें प्रकृति का महत्व समझना होगा, उसकी सुरक्षा में हमें मिलकर प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

रुपेश राय, दरभंगा, बिहार

अनुकूल बने खाद्य प्रसंस्करण नीति

खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में कहना है कि अभी तक इससे जुड़ी कोई नीति सफल नहीं हो सकी है। अगर नीति का निर्धारण सही होता, तो आज बिहार का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाता, बल्कि दूसरे राज्य के लोग यहां मजदूरी करने आते। बिहार में एक भी झुग्गी झोपड़ी नजर नहीं आती। इन झोपड़ियों में रहने वालों को अच्छे मकानों में रहने का अवसर प्राप्त होता और उसी मकान के आधे भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए छोटी-छोटी मशीनें लगी होतीं। जैसे बिजली से चलने वाला जाता, ओखली, मूसल, चावल, दाल, मसाला, कंसार, प्याज, लहसून, अदरक, सरसों और फलों के पेस्ट या पाउडर बनाए जाते। इनके बाजार की व्यवस्था होने से गांवों का कायापलट हो सकता है। इसके लिए हर पंचायत में इंडस्ट्रियल, कामर्शियल पार्क खोलने के लिए बहुमंजिला भवन बनवाना होगा। एक अनुमान के अनुसार बिहार की आठ हजार पंचायतों में ऐसे भवन बनाने में पांच वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस भवन में स्कूल, अस्पताल, कैंटीन, आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। आरक्षण का झंझट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके लाभार्थी अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले मेहनतकश लोग होंगे। इसके लिए मैंने एक डीपीआर राज्य सरकार को समर्पित किया था, परंतु जमीन अनुपलब्ध रहने के कारण नीति नहीं बन सकी।

बिनय कुमार, अवकाश प्राप्त अभियंता

पोस्ट

आखिर कानून के छात्रों को मनुस्मृति क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? यह दुनिया में बनाई गई शुरुआती विधि संहिताओं में से एक है और इसका अध्ययन होना चाहिए।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

बिहार का पूरा समाजवादी परिवार अंबानी के यहां भव्य शादी समारोह में शामिल होने जा रहा है। यही परिवार लोगों को रोज ऐसी 'मनोहर कहानियां' सुनाता रहता है कि मोदी ने यह देश अंबानी को बेच दिया है।

बालियान@Baliyan_x

भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन यह आयोजन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा और नाना प्रकार की यातनाओं को सहन किया।

मनोहर सिंह राठौर@Manohar18666755

भारत में आयकर का मौजूदा ढांचा वेतनभोगी मध्य वर्ग के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है। यदि सरकार को यह लगता है कि यह वर्ग उसका बंधुआ वोट बैंक है तो यह उसकी भारी भूल होगी। महसूस होता है कि भारत में ईमानदारी से पैसा कमाना कोई अपराध हो गया है।

सुशांत झा@jhasushant

जनपथ

करते सीना ठोंक कर संविधान की बात,
फिर तो सुप्रिम कोर्ट का जरा थामिये हाथ।
जरा थामिये हाथ फैसला जो है आया,
उसका स्वागत आप कीजिए बढ़ कर भाया।
मिले 'गुजारा' आप दुआ से झोली भरते,
किंतु न हक़ की बात आप बहनों की करते!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 92

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 13 जुलाई 2024

शारीरिक चोट कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, लेकिन विश्वासघात का घाव जीवन भर नहीं भरता। -मिनेका इवासाकी

ऐसे वक्त में, जब घरेलू बाजार कई चुनौतियों से जूझ रहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की इस टिप्पणी से, कि नीतिगत दरों में कटौती की बात करना जल्दबाजी होगी, केंद्रीय बैंक के सतर्क रुख का ही पता चलता है, जो विकास और महंगाई में संतुलन कायम रखना चाहता है।

संतुलन की बात

मौजूदा समय में जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता बनी हुई है और घरेलू बाजार भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर का यह कहना कि नीतिगत दर में कटौती की बात करना जल्दबाजी होगी, आर्थिक स्थिरता की दिशा में देश के केंद्रीय बैंक की सतर्कता को ही दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि मौसम के असामान्य बर्ताव को देखते हुए सब्जियों वगैरह के दाम और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में, महंगाई दर के पांच फीसदी से ज्यादा रहने की वजह से ब्याज दर में कटौती पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल, देश में खाद्य और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर मुद्रास्फीति पर पड़ता है। अगर मुद्रास्फीति की दर अनियंत्रित होती है, तो यह आम लोगों के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर सकती है। उच्च ब्याज दरों का मतलब है महंगा कर्ज और ईएमआई की ऊंची दरें, जो आम उपभोक्ताओं व छोटे व्यवसायों पर वित्तीय बोझ बढ़ा सकती है। वहीं, निम्न ब्याज दरों का अर्थ है सस्ता कर्ज, लेकिन इससे मुद्रास्फीति बढ़ने की भी आशंका होती है। ऐसे में, केंद्रीय बैंक का यह कदम विवेकपूर्ण है कि वह पहले मुद्रास्फीति की स्थिरता सुनिश्चित करे और फिर ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव पर विचार करे। इससे निवेशकों को भी यह आश्वासन मिलता है कि केंद्रीय बैंक एक स्थिर और पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में कटौती तभी करता है, जब उसे लगता है कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने की जरूरत है। चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर पिछले वर्ष से आश्चर्यजनक रूप से मजबूत तो रही ही है, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भी जीडीपी का अनुमान सात से बढ़ाकर 7.2 फीसदी कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि यह लगातार चौथा साल होगा, जब भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी से ज्यादा होगी। ऐसे में, यह आशंका सही नहीं कही जा सकती कि दरों में बदलाव का न होना देश की आर्थिक वृद्धि को रोक रहा है।

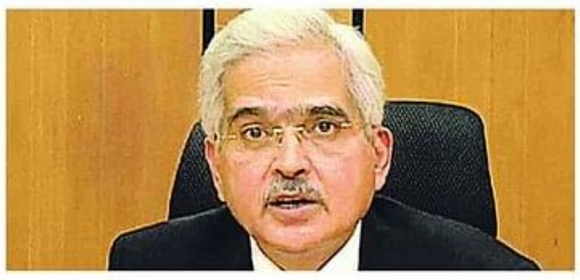

निस्संदेह, महंगाई को चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर शीघ्रता से लाने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करना होगा। लेकिन, केंद्रीय बैंक का रुख दर्शाता है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए या यों कहें कि विकास और महंगाई में तालमेल बनाए रखने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगामी बजट में गठबंधन सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता को कैसे प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर यह अनुमान से ज्यादा रहता है, तो इससे मुद्रास्फीति और ब्याज दर, दोनों पर असर पड़ेगा।

आखिर बाबा चलते क्यों हैं?

हाथरस मामले ने एक बार फिर कथित बाबाओं को चर्चा में ला दिया है। ऐसे कथित गुरुओं की जीवन-शैली पारंपरिक संतों जैसी नहीं है और न ही उनके उद्‌बोधनों से कोई विशेष पांडित्य प्रकट होता है। फिर भी आम लोग भावनात्मक सुरक्षा के लिए ऐसे बाबाओं की शरण में पहुंचते हैं।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में गत दिनों एक सत्संग में भगदड़ मचने से 121 भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। अधिकांश मृतक दलित थे। आम तौर पर किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में दलित उत्पीड़न, हत्या, दुर्घटना का मामला राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है। परंतु हाथरस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अव्यवस्था-लापरवाही बरतने के केंद्र में 'भोले बाबा' उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह का सत्संग प्रकरण है। बाबा स्वयं भी दलित समाज से आते हैं। चूंकि यह घटना 'दलित बनाम सवर्ण' या 'जातिगत तनाव' संबंधी नैरेटिव के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस पर मौन की दहाड़ है। परंतु असली विचारयोग्य विषय कुछ और है।

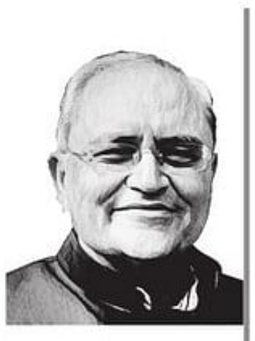

बलवीर पुंज
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

हाथरस मामले ने एक बार फिर ऐसे बाबाओं को चर्चा में ला दिया है। आखिर नारायण साकार हरि जैसे कथित गुरुओं से लाखों-करोड़ की संख्या में लोग क्यों जुड़ जाते हैं? इनकी जीवन-शैली, वेशभूषा और आचार-व्यवहार भारत के पारंपरिक संतों जैसी नहीं है और उनके उद्‌बोधनों से कोई विशेष पांडित्य भी प्रकट नहीं होता है। फिर क्या कारण है कि इन 'साधु-संतों' के लिए उनके अनुयायी मरने-मारने को भी तैयार रहते हैं? कई राजनीतिक दल भी उनके अनैतिक व गैर-कानूनी कार्यों में या तो प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग देते हैं या फिर चुप्पी साधे रखते हैं।

यह उपक्रम न तो एक समाज तक सीमित है और न ही एक देश तक। देश के कई क्षेत्रों में आयोजित चंगाई सभाओं में पादरी दृष्टिबाधित-दिव्यांग और रोगी व्यक्ति को अपने 'करिश्मे' से ठीक करने का दावा करते हैं। ईसाई बहुल अमेरिका-ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ इस्लामी दुनिया में भी पीर-फकीर का तिलिस्म फैला हुआ है, जिससे वहां का सत्ता-अधिष्ठान भी प्रभावित है। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी तीसरी बेगम पीर बुशरा मेनका की 'रूहानी ताकत' की खूब चर्चा रही है।

लेकिन भारत में बाबाओं की सफलता की वजह अलग है। इसका एक बड़ा कारण शासकीय विफलता है। कोई भी व्यवस्था जितनी अक्षम और भ्रष्ट होगी, समाज में उतनी ही अनिश्चितता और असंतोष बढ़ेगा। यह स्थिति ऐसे बाबाओं के लिए सबसे अनुकूल होती है। सरकार चाहे किसी की हो, उसके अधीनस्थ तंत्र अक्सर संवेदनहीन होता है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा दशकों से अपनी जरूरतों (राशन-चिकित्सा-शिक्षा सहित) की पूर्ति के लिए सरकारी उपक्रमों पर निर्भर है। परंतु जन-सरोकार के लिए गठित सार्वजनिक निगम, थाना, बैंक, अस्पताल, स्कूल इत्यादि घूसखोरी, धांधली और उत्पीड़न के पर्याय बन चुके हैं। ऐसे में जनता स्वयं को उपेक्षित व अपमानित महसूस करती है। बीते कुछ वर्षों में नकद धन हस्तांतरण से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, और लाभार्थियों को बिना सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाए सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परंतु शेष व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

वर्षों पुरानी शासकीय प्रणाली और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था की अक्षमता-विफलता का लाभ स्वयंभू 'चमत्कारी' बाबाओं को मिलता है। देश भर में ऐसे बाबाओं के कई सौ एकड़ में फैले शिविरों में निशुल्क या सस्ती चिकित्सा प्रणाली, दवा केंद्र, शिक्षा, खेल-उद्यान आदि उपलब्ध हैं, जिन्हें पाकर उनके करोड़ों अनुयायी स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हैं। यह लोगों को स्वयंभू संतों से जोड़ने में बड़ा कारक है।

आधुनिकता और निजी स्वतंत्रता के नाम पर शासकीय व्यवस्था नशा-धूम्रपान और लिव-इन संबंधों (समलैंगिकता सहित) को सशर्त स्वीकृति देती है। परंतु समाज का एक बड़ा वर्ग इन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। भले ही बाबाओं का निजी जीवन कैसा हो, परंतु इन विषयों पर वे व्यापक जनभावना को जनसमूह से साझा करते हैं। परिणामस्वरूप बाबाओं की लोकप्रियता बनी रहती है।

मानवीय जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और कई मामलों में मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। उपभोक्तावादी दौर में अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य से ऊपर धन-पद अर्जित करने और सुख-सुविधा पाने की लालसा बढ़ गई है। वह लालसा पूरी नहीं होने पर भी कई लोग इन बाबाओं की शरण में चले जाते हैं, जो भले ही उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हों, परंतु अपने आभामंडल से उन्हें मानसिक संतुष्टि जरूर प्रदान करते हैं। यही नहीं, बढ़ते शहरीकरण के कारण वे बिरादरियां और अन्य सामाजिक संरचनाएं भी तेजी से टूट रही हैं, जो कुछ दशक पहले तक व्यक्ति को पहचान व सुरक्षा का भाव देती रही हैं। वर्तमान समय में उसी भावनात्मक सुरक्षा का अभाव है, जिसकी पूर्ति करने में स्वयंभू बाबा और उनकी मंडली बड़ी भूमिका निभाती हैं।

आधुनिक शासकीय व्यवस्था अक्सर मानवीय आवश्यकताओं—रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर नहीं जाती। ठीक है कि प्रत्येक मानव की यह मूल आवश्यकता है। परंतु उनकी एक और जरूरत भी होती है, जिसे हम अध्यात्म, भावनात्मक या फिर 'अपनेपन की भावना' के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके प्रति राजकीय उदासीनता भी लोगों को स्वयंभू 'साधु-संतों' से जोड़ रही है।

भारतीय जीवन-पद्धति और उसकी शैली के केंद्र में आध्यात्मिकता है, जो किसी मजहबी दर्शन जैसी संकीर्ण नहीं है। वैदिक सनातन संस्कृति प्रदत्त इस चेतना को गत कई सदियों से अनेकों महानुभावों (सिख परंपरा, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गांधीजी, विनोबा भावे सहित) ने आगे बढ़ाया है। परंतु छद्म-धर्मनिरपेक्षता के नाम पर स्वतंत्र भारत में जैसी विकृत व्यवस्था स्थापित की गई, उसमें सत्ता-अधिष्ठान द्वारा आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करना 'सांप्रदायिक' चश्मे से देखा जाने लगा। शासन-व्यवस्था और समाज के बीच के इस खालीपन को स्वघोषित 'संत' या 'गुरु' अपने निजी लाभ के लिए बड़ी चतुराई, छल-फरेब और अपने विशेष प्रभावों से भर देते हैं।

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में कर्म की प्रधानता बताई गई है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि हम इसे अपने जीवन का सार बना लें, तो समाज में ऐसे बाबाओं की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन जो आर्थिक खाई और शासकीय तंत्र की प्रकृति है, उसके चलते क्या ऐसा निकट भविष्य में संभव है?

edit@amarujala.com

जीवन धारा

महर्षि अरविंद

शत्रु बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये शत्रु हैं- हमारा स्वार्थ, दुर्बलता और भावुकता। जब तक हम अपनी इन कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक अपने उद्‌देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत ईश्वर है

राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, जिसका स्रोत ईश्वर है। राष्ट्रवाद एक पंथ है, जिसे आपको जीना होगा। यदि आप राष्ट्रवादी बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर धार्मिक भावना का होना जरूरी है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि आप ईश्वर के उपकरण हैं। राष्ट्रवाद में किसी प्रकार के द्वेष, खिन्नता, कड़वाहट या आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिकता पर आधारित मानव एकता के आदर्श को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अध्यात्मवाद ही राष्ट्रवाद का इकलौता सुरक्षा कवच है। राजनीति में लोगों का दिल से महान और उन्मुक्त होना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष के बजाय संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मीकरण जरूरी है। सरकार और समाज की मशीनरी के प्रयोग से अपने परिवेश को बेहतर बनाने एवं स्वप्न देख रहे मनुष्यों की यह पापमय स्पर्धा व्यर्थ है, क्योंकि बाह्य परिवेश को सुधारने के लिए अंतरात्मा की शुद्धता आवश्यक है। हमारा आचरण सहज व सरल और बौद्धिक रूप से चेतन हो। जो लोग कहते हैं कि भारत को एक राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे पहले जाति और धार्मिक मतभेदों को नष्ट करना होगा, उनकी धारणाएं हमारे राष्ट्र के चरित्र के बारे में काफी धुंधली और भ्रमित हैं। हमारा इतिहास अन्य देशों की तुलना में कई मायनों में भिन्न रहा है। भारतीय लोगों की संरचना पूरी दुनिया में अद्वितीय रही है। अतीत पर दृष्टि डालें, तो कई राष्ट्रों का विकास विभिन्न जनजातियों के एकत्रीकरण और समावेशन से हुआ है। यह बहुत पहले की प्रक्रिया है, किंतु भारत सिर्फ जनजातियों का मिलन स्थल नहीं रहा है, बल्कि अपनी विकसित सामाजिक और धार्मिक रेखाओं और मूल जातियों तथा विशिष्ट प्रकार की संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। भारतीय राष्ट्र का चरित्र और संरचना, यूरोपीय राष्ट्रों से बहुत भिन्न है।

जीवन की वास्तविक पूर्णता जीवन के भौतिक पक्ष को नकार कर नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से ही संभव है। जीवन में भौतिक पक्ष का निषेध करने के कारण ही भारत को भौतिक परतंत्रता अंगीकार करनी पड़ी। हमें अपने वैयक्तिक जीवन की तरह राष्ट्रीय जीवन में भी आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों का समायोजन करना होगा। जीवन जीवन होता है। भले वह एक बिल्ली का हो या फिर कुत्ते या मनुष्य का। बिल्ली और मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इन्सान के बीच मानवीय अवधारणा के लाभ का है। शत्रु कोई बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये शत्रु हैं-हमारा स्वार्थ, दुर्बलता और भावुकता। जब तक हम अपनी इन कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक अपने उद्‌देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत कर दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा।

सच्चे अध्यात्म की राह

सूत्र

आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन तीनों ही अलग हैं। हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तीनों को एक साथ मिलाने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन सामान्य बात है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन चेतना के परिवर्तन से सीधे आगे बढ़ता है। यह वह चेतना होती है, जिसमें व्यक्ति अपने सच्चे अस्तित्व को पहचानता है। इसलिए राष्ट्रवाद ही सच्चा अध्यात्म है और राजनीतिक स्वतंत्रता ईश्वरीकृत कार्य।

दूसरा पहलू

वाशिंगटन में हुए नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी की पोशाक चर्चा का केंद्र रही।

युद्धरत यूक्रेन की प्रथम महिला और फैशन

दुनिया भर के दर्जनों नेता जब वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे, तो उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी थे, जिन्होंने रूसी युद्ध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगातार सहायता देने की दरख्वास्त भी की। वहां उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का भी थीं, जो 2022 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी थीं। उस समय ओलेना ने पूर्वी यूक्रेन की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सूट पहना था, जो तब रूसी हमले की जद में था।

इस बार भी जेलेंस्का ने खास मकसद से परिधान चुना था। जेलेंस्का की स्टाइलिस्ट नताशा कर्मेंस्का बताती हैं, जेलेंस्का ने यह दिखाने के लिए फैशन का उपयोग किया है कि युद्ध पीड़ित एक देश की प्रथम महिला की पोशाक कैसे दुनिया के नजरिये को प्रभावित करती है। वह कहती हैं कि हमारे लिए फैशन यूक्रेनी लोगों, डिजाइनरों और वहां की प्रतिभा के बारे में बताने का एक उपकरण है। यह सार्वजनिक मौकों पर गंभीर चीजों के बारे में बताने का एक सौम्य तरीका है। हमने राष्ट्र की प्रथम महिला के परिधानों के जरिये विभिन्न यूक्रेनी ब्रांडों को दिखाया है, ताकि दुनिया को हमारे लचीलेपन का पता चले कि हम युद्ध के दौरान भी अपना काम जारी रखते हैं।

वेनेशा फ्रीडमैन

जेलेंस्का ने यह दिखाने के लिए फैशन को जरिया बनाया है कि एक युद्ध पीड़ित देश की प्रथम महिला की पोशाक कैसे दुनिया के नजरिये को प्रभावित करती है।

जेलेंस्का ने रात्रिभोज में जो काली और सफेद पोशाक पहनी थी, वह जान-बूझकर चुनी गई थी, ताकि यूक्रेन की सभी महिलाओं की ताकत के साथ परिष्कार और स्त्रीत्व के संयोजन को दर्शाया जा सके।

ओलेना जेलेंस्का जब पहले दिन वाशिंगटन के होलोडोमोर मेमोरियल गईं, तो उन्होंने गप्टुवलन्या की एक कढ़ाई वाली पोशाक पहनी थी, जिसे वैश्यवंका कहा जाता था, जो यूक्रेन के सांस्कृतिक कोड का प्रतीक है और काली कढ़ाई स्मारक की दर्दनाक पीड़ा को दर्शाती थी। नताशा कहती हैं कि जेलेंस्का ने रात्रिभोज में जो काली और सफेद पोशाक पहनी थी, वह हमने जान-बूझकर चुनी थी, ताकि यूक्रेन की सभी महिलाओं की ताकत के साथ परिष्कार और स्त्रीत्व के संयोजन को दर्शाया जा सके। वह कहती हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ, तो जेलेंस्का ने मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट न रखने का फैसला किया, क्योंकि वह समय इन सब चीजों के लिए ठीक नहीं था। बाद में जब वह राजनेताओं के साथ बाहर मिलने जाने लगीं, तो उन्होंने कपड़ों पर ध्यान देना शुरू किया। नताशा कहती हैं कि राष्ट्रपति की पत्नी क्या पहनती हैं, इस पर पहले कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन ओलेना हमारी ऐसी पहली प्रथम महिला हैं, जो स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक कपड़े पहनने के अलावा, अपनी सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान समकालीन यूक्रेनी डिजाइनरों के बनाए परिधान पहनकर अपनी पहचान स्थापित करती हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

जानलेवा प्रदूषण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से प्रतिवर्ष 11.50% मौतें होती हैं। देश के महानगरों में प्रदूषण से होने वाली मौतों में दिल्ली शीर्ष पर है।

बंगलूरू में 2102, वाराणसी में 931, शिमला में 59 मौतें प्रदूषण की वजह से होती हैं। | स्रोत : LANCET

धुंधुकारी जब प्रेत बन गया, तो उसने गोकर्ण से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने गोकर्ण को बताया कि इसे श्रीमद्‌भागवत कथा सुनाओ।

गोकर्ण ने दिलाई धुंधुकारी को मुक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

तुंगभद्रा नदी किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धुंधुली कलह करती थी। उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण जंगल में गए। वहां पर वह एक महात्मा से मिले और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की।

महात्मा ने कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। काफी आग्रह के बाद संत ने ब्राह्मण को फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन उसे पवित्रता के साथ रहना होगा। ब्राह्मण ने जाकर पत्नी को फल दिया। लेकिन धुंधुली ने सोचा कि उसे नियमपूर्वक रहना होगा, इससे तो बांझ ही अच्छी हूं। धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया और अपनी गर्भवती बहन से कहा कि तुझे जो पुत्र हो, उसे मुझे दे देना। धुंधुली ने अपनी बहन के पुत्र को ले लिया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा गया। वहीं, गाय को भी इन्सान जैसा बछड़ा हुआ। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधुकारी बड़ा होकर व्यसन और वेश्यावृत्ति में पड़ गया।

गोकर्ण धर्म-कर्म के अनुसार रहते थे। माता-पिता की मौत के बाद धुंधुकारी पांच वेश्याओं को घर ले आया। उन्होंने मिलकर एक दिन धुंधुकारी की हत्या कर दी। इससे धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मुक्ति के लिए विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सूर्यदेव ही कोई उपाय बताएंगे। सूर्यदेव ने कहा कि इसको सात दिन तक श्रीमद्‌भागवत कथा सुनाओ, तब मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण ने श्रीमद्‌भागवत कथा सुनाकर धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 नवंबर, 1958

नेहरू और वरिष्ठ नेता नई कार्यकारिणी समिति में नहीं होंगे

नेहरूजी व वरिष्ठ नेता नयी कार्यकारिणी समिति में न होंगे

गणतन्त्र दिवस की परेड की तैयारियां

कांग्रेस में नए लोगों को जगह देने के लिए अनेक वयोवृद्ध नेता इस बार कार्यकारिणी से बाहर रहकर देश का नेतृत्व करेंगे। गुवाहाटी अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री पं. नेहरू व कई वयोवृद्ध नेता कार्यकारिणी से बाहर रहेंगे।

किसानों पर जलवायु संकट का कहर

फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों की सख्त जरूरत है।

सीमा जावेद | **मुद्दा**

पिछले दो वर्षों से लगातार मौसम का कहर अन्नदाताओं पर टूट रहा है। इस साल पड़ी अभूतपूर्व गर्मी जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का साफ संकेत है। इसने भारत में फसलों की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले पांच वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं ने फसल और उपज के नुकसान के रूप में 60 फीसदी से अधिक सीमांत (दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और मंझोले) किसानों को प्रभावित किया है।

डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) द्वारा 'भारत के सीमांत किसानों की स्थिति 2024' पर जारी दूसरी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी गर्मी, सूखा, बेमौसम बारिश और बाढ़ से उनकी पैदावार को नुकसान हो रहा है। इस अध्ययन में साफ तौर पर बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग लगातार छोटे व मंझोले किसानों पर

प्रहार कर रहे हैं और उनकी फसलों की उत्पादकता में निरंतर गिरावट आ रही है।

गौरतलब है कि साल 2022 में हीटवेव के शुरुआती रौद्र रूप ने भारत में गेहूं की फसल को प्रभावित किया और उत्पादन की मात्रा साल 2021 में 10.959 करोड़ टन से घटकर 10.77 करोड़ टन रह गई। इसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को बाध्य किया। वर्ष 2023 में भी इसी वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ, और लक्ष्य से लगभग तीस लाख टन कम उत्पादन हुआ। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का बदलता मिजाज पिछले कुछ वर्षों से खेती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जो किसानों के लिए मुसीबत बन चुका है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में गेहूं और मक्के की खेती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों सहित अन्य क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बात कही गई है।

वैज्ञानिकों की मानें, तो यदि जलवायु परिवर्तन की दर इसी गति से बढ़ती रही, तो भविष्य में कई फल मिलने में दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। आने वाले वर्षों में केले के उत्पादन पर भी नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अगर तापमान में एक डिग्री की वृद्धि होती है, तो गेहूं उत्पादन में करीब तीन से चार फीसदी कमी आएगी।

तापमान में चार-पांच डिग्री वृद्धि से उत्पादन में 15-20 फीसदी की कमी आ सकती है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा चक्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें तबाह हो रही हैं। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धान के उत्पादन में भी 10 से 30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, और मक्का की पैदावार में भी 25 से 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से फसल की पैदावार कम होने के साथ उपज की पोषण गुणवत्ता भी घट जाती है। कम वर्षा की वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और दालों जैसी फसलों की बुआई देर से हो सकी। कई उत्तरी राज्यों में धान के खेत अक्सर बाढ़ के कारण जलमग्न रहते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 19.9 प्रतिशत है। यह क्षेत्र भारत के 42.6 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। लिहाजा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत संचालित मुख्य अभियानों में से एक है। तापमान में वृद्धि और पानी की उपलब्धता में बदलाव, पूरे कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में सिंचित कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में, हमें जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और आजीविका में विविधता लाने की जरूरत है। फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि (सीएसए) प्रौद्योगिकियों की सख्त जरूरत है, जिसमें एक सतत दृष्टिकोण शामिल है। एक प्रभावी जलवायु के प्रति अनुकूल कृषि वाले दृष्टिकोण से हम भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम कर सकते हैं।

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सिर्फ छुट्टी नहीं, जिम्मेदारी की भावना भी है जरूरी

किसी भी संतान से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने माता-पिता की उपेक्षा करे। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन भागमभाग वाली जिंदगी और दूसरे कारणों से संतानें माता-पिता से दूरियां भी बनाने लगी हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने अपने कार्मिकों को अपने माता-पिता या सास-श्वसुर के साथ वक्त बिताने के लिए दो दिन का अवकाश देने का अनूठा फैसला किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये विशेष छुट्टियां संबंधित कार्मिक अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये छुट्टियां नवम्बर में पहले से ही तय अवकाशों के साथ दी गई हैं ताकि ज्यादा समय तक माता-पिता का साथ मिल सके।

यह सच है कि आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। नौकरी के लिए लोगों को अपने माता-पिता से भी दूर रहना पड़ता है। छुट्टियां कम मिलने से वे अपने माता-पिता के साथ वक्त नहीं गुजार पाते। इस लिहाज से सरकार का फैसला उचित ही लगता है। लेकिन, यह भी कटु सत्य है कि कई लोग अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, लेकिन उनका अपने माता-पिता के साथ सही व्यवहार नहीं है। कई जानबूझकर अपने माता-पिता से दूर रहते हैं। बड़ी संख्या में माता-पिता अपने बच्चों से उपेक्षित और प्रताड़ित हो रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से अपनी संतानों के बर्ताव को लेकर अदालतों तक में पहुंचने वाले मामले तो वे हैं, जहां इस उत्पीड़न की इंतहा होने लगती है। माता-पिता को जीवन के अंतिम पड़ाव में संतानों की जरूरत ज्यादा होती है। यह भी सच है कि उन्हें सुख-सुविधाओं की दरकार इतनी नहीं होती। बस वे तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी सामान्य देखभाल होती रहे। उनके खान-पान व वक्त जरूरत पर उपचार और दवाइयों का इंतजाम हो जाए। लेकिन, जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें यह तस्वीर भी दिखती है कि खुद भले ही सम्पन्न हों लेकिन बच्चों को अपने माता-पिता को यह मुट्ठी भर सुख देना भी गवारा नहीं होता। हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। लोकलाज के डर से अधिकांश माता-पिता तो अपनी संतानों की उपेक्षा को भी नियति समझ कर चुप्पी साध लेते हैं। साफ है कि भरण-पोषण को लेकर बने सख्त कानून-कायदों का भी डर नहीं है। ऐसे मामलों में असम सरकार का ताजा फैसला बुजुर्गों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। हां, कमाने-खाने कहीं दूर गए व कामकाज की व्यस्तता की वजह से घर नहीं आने वाले ऐसे सरकारी कार्मिकों को जरूर मदद मिल सकती है, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।

सबसे बड़ा सवाल लोगों की मानसिकता और माता-पिता से जुड़ाव का है। जो कार्मिक माता-पिता से जानबूझकर दूरी बनाना चाहते हैं और उनकी देखभाल से बचना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी छुट्टियां अपने काम निपटाने में ही खर्च होंगी। किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए व्यक्ति में इच्छाशक्ति और त्याग की भावना होना जरूरी होता है।

प्राणकला और वाक्कला ही निर्माण का आधार बनती हैं। प्राण कला से अक्षर-प्राण सृष्टि तथा वाक् से पदार्थ सृष्टि होती है। वाक् व्यापक है, शान्त है, एक है। शब्द व्याप्य है, विविध भावों से उत्पन्न होने वाले हैं। शब्द की उत्पत्ति का कारण वाक् है। सृष्टि में कोई स्थान वाक् से रिक्त नहीं है।

वाक् ही सृष्टि

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

रहस्यपूर्ण शब्द है रस। नित्य प्रवाहित रहने वाला तत्त्व है। प्रवाह ही फैलाव है–विस्तार है–आनन्द है। प्रवाह का उपादान गतिमान प्राण होता है। जीवन में इसके पर्यायवाची भी अनन्त हैं। जिन विषयों से इन्द्रियों को तृप्ति मिलती है, उनको रसीला कहा जाता है। यद्यपि इन्द्रियां स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करतीं। ग्रहण तो मन करता है। आत्मा करता है। कोई भी शास्त्रीय नृत्य, संगीत हो, हमें भावविभोर कर देता है। हम खो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। साहित्य, कला आदि विषय भी हमको अभिभूत कर देते हैं। यहां तक कि सद्पुरुषों के वचनों से हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जीवन का यह पहला निष्कर्ष है कि हर कर्म रसमय है।

जीवन का सुख 'रस' में है। नीरस जीवन मृत्यु का पर्याय है। **''रसो वै सः''**- रस ही ब्रह्म है। चूंकि जीवन का प्रत्येक अंग ब्रह्म है, अतः सर्वत्र रस का बोध बना रहना चाहिए। कर्म भी ब्रह्म का व्यावहारिक रूप है, अतः कर्म का भी प्रत्येक अंग रसमय हो। कर्म आनन्ददायक हो। कर्म का आनन्द ही पूर्ण मनोयोग है, भक्ति है। कर्म की इच्छा मन में उठती है। मन ईश्वर का मन्दिर है।

मन सूक्ष्मतर है। यह प्राण और वाक् के बिना नहीं रहता। प्राण सूक्ष्म तथा वाक् स्थूल है। सृष्टि में ये ही ऋक्-यजुः व साम हैं। यह वेदत्रयी अग्नि वेद है। कामना, तप और श्रमरूप तीन कर्मों से अग्निवेद से आपः बना। यही चौथा अथर्ववेद है। यजुः को द्विब्रह्म तथा अथर्व को षड्ब्रह्म कहा जाता है। षड्ब्रह्म रूप अथर्व में भृगु (अप्-वायु-सोम) तथा अंगिरा (अग्नि-यम-आदित्य) रहते हैं। इस प्रकार ऋक्-यत्-जूः-साम-अप्-वायु-सोम-अग्नि-यम-आदित्य की समष्टि को विराट् कहा जाता है। समस्त जगत के पदार्थों में ये दस तत्त्व विद्यमान रहते हैं। गीता में कृष्ण अपने विराट् रूप का दर्शन करवाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे गुड़ाकेश! आज तुम मेरे शरीर में चर और अचर सहित सारे जगत को देखो और इसके अतिरिक्त भी तुम अपने मन में जो शंका धारण किए हुए हो, उसका उत्तर भी देख लो। तुमने ठीक ही कहा कि तुम अपने इन्हीं प्राकृतिक नेत्रों से मेरे ऐश्वर्य रूप को देखने में समर्थ नहीं हो सकोगे अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। उन चक्षुओं से मेरे ईश्वर संबंधी योग को देखो–

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि।।
(गीता 11.7)
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।।
(गीता 11.8)

विराट् ही वेद है। ऋक्-साम का इन्द्र से सम्बन्ध है, यजुः का विष्णु से। यजुः के यत् रूप प्राणों में क्षोभ हुआ मन की कामना से। इससे वाक् (आकाश-जू) का प्रादुर्भाव होता है। पंचपर्वा विश्व में यह वाक् मन और प्राण से संबंधित होकर व्याप्त रहता है। पांचों पर्वों में उसका स्वरूप भिन्न-भिन्न रहता है। स्वयंभू के मूल तत्त्व ऋक्-यजुः (यत्-जू) व साम हैं, अतः इस लोक की वाक् को सत्यावाक् या वेदवाक् कहते हैं। परमेष्ठी अम्भस् (आपः) लोक है अतः यहां विवत वाक् आम्भ्रणी कहलाती है। सूर्य का छन्द बृहती है और यह पृथ्वी व चन्द्रमा की अपेक्षा बड़े साम वाला है, अतः यहां बृहती वाक् है। चन्द्रमा की वाक् सुब्रह्मण्या कही जाती है क्योंकि चन्द्रमा सोमलोक है। सोम को ही सुब्रह्म भी कहा जाता है। पृथ्वी की वाक् को अनुष्टुप् कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी अग्निलोक है और इसका छन्द अनुष्टुप् है।

विज्ञान कहता है कि रसमय सृष्टि में केवल दो ही तत्त्व हैं–पदार्थ और ऊर्जा। यही हमारे लिए प्रकृति एवं पुरुष हैं, ब्रह्म और माया हैं। ब्रह्म ज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, प्रकृति यज्ञशास्त्र है, रसायन शास्त्र है। ब्रह्म अग्नि है, प्रकृति सोम है–सौम्या है। अग्नि में सोमाहुति ही प्रजोत्पत्ति का कारण है। अग्नि पुरुष का स्वरूप है किन्तु वह शोणित में (स्त्री के) रहता है। सोम स्त्री का स्वरूप है किन्तु वह पुरुष के शुक्र में रहता है। यजुः रूप अग्नि आधार बनता है–द्विब्रह्म है। आपोरूप सोम आधेय बनता है। आपः षड्ब्रह्म है। यजुःरूपा योनि, स्थिति-गत्यात्मक, में मातरिश्वा वायु द्वारा रेतोरूप षड्ब्रह्म की आहुति होती है। एक नए स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, जिसे 'महान्' कहते हैं। अव्यक्त तत्त्व का यही महान् व्यक्त भाव है।

अग्नि में सोम की आहुति से दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक स्नेह-संकोचमयी सृष्टि, जो घनता युक्त पदार्थ सृष्टि होती है। इसकी प्रथम कृति षोडशी पुरुष में अभिव्यक्त होती है। अथर्वा रूप क्षारीय भृगु से दूसरी आग्नेय सृष्टि होती है। इसमें भृगु-अंगिरा तत्त्व साथ रहते हैं। इनमें जिसकी यज्ञ में प्रधानता रहती है, वैसी ही सृष्टि होती है। वैसे अग्नि में सोम की तीन स्थितियों (आपः, वायु, सोम) से सृष्टि भी आप्य, वायव्य और सौम्य होती है। स्वयंभू की सृष्टि मौलिक है। परमेष्ठी याज्ञिक सृष्टि का मूल है। पुरुष यजुः है, यत् एवं जूः है। प्रसारधर्मा-आग्नेय है। सुब्रह्म सौम्य है–अथर्वा है, स्नेहनधर्मा है। परमेष्ठी का अप् ही सुब्रह्म है। अप् का अग्नि में योग या सोम का वायु द्वारा अग्नि में आधान ही सृष्टिकारक यज्ञ होता है। परमेष्ठी के भृगु व अंगिरा से क्रमशः लक्ष्मी व सरस्वती वाक् प्रादुर्भूत होते हैं। ये ही अर्थ वाक् और शब्दवाक् कहलाते हैं।

सृष्टि का आधार अव्यय की अविद्या/कर्म कलाएं होती हैं, इनमें प्राणकला और वाक्कला ही निर्माण का आधार बनती हैं। प्राण कला से अक्षर-प्राण सृष्टि तथा वाक् से पदार्थ सृष्टि होती है। वाक् व्यापक है, शान्त है, एक है। शब्द व्याप्य है, विविध भावों से उत्पन्न होने वाले हैं। शब्द की उत्पत्ति का कारण वाक् है। सृष्टि में कोई स्थान वाक् से रिक्त नहीं है। यही वाक् की व्यापकता है। वाक् में आघात लगने से तरंगें उठकर कान तक पहुंचती हैं तथा कर्ण विवर पर धक्का मारती हैं। इस आघात से **''संयोग-विभाग-शब्देभ्यः शब्दोत्पत्तिः''** के अनुसार शब्द पैदा हो जाता है। **''शपं-आक्रोशं-ददाति''** यही शब्द की उत्पत्ति है। शब्द धक्का देता है। वाक् शान्त है। शब्द बिना वाक् के रह भी नहीं सकता। वाक् और शब्द ही दाम्पत्य भाव में वृषा एवं योषा हैं। वाक् को अमृतवाक् तथा शब्द का मर्त्यावाक् कहा जाता है। वाक् इन्द्र तथा शब्द इन्द्रपत्नी कहलाते हैं। संसार में प्रधानता मर्त्यभाग की ही है। शब्द तन्मात्रा (आकाश का गुण) ही सृष्टि मूल है।

वेद वाक् से परात्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर पुरुष का रूप षोडशी पुरुष बनता है। विश्व की प्रत्येक वाक् स्वरूप के केन्द्र में षोडशी पुरुष रहता है। शब्द वाक् की अधिष्ठात्री सरस्वती है तथा अर्थवाक् की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है। शब्द वाक् में परा-पश्यन्ति-मध्यमा-वैखरी–चार भेद रहते हैं। अर्थवाक् अन्न है, भोगने की वस्तु होती है। सोम निर्मित होती है। लक्ष्मी-सरस्वती मूल में दो नहीं हैं। अर्थ और शब्द साथ ही रहते हैं। सच तो यह है कि उत्पन्न भी साथ ही होते हैं। अर्थ के साथ आकृति भी है और शब्द भी उसी का रूप बताता है। जैसे हाथी अर्थ है, हाथी शब्द भी है।

हमारी स्थूल सृष्टि अन्न से होती है। जीवात्मा का यात्रा मार्ग अन्न ही है अतः अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। दूसरी ओर शब्द भी परावाक् से निकलता है। शब्द भी ब्रह्म है। जीवन की विचित्रता देखिए! अन्न ग्रहण का माध्यम रसना है और वाक् विसर्जन का माध्यम भी जिहवा ही है। ब्रह्म ही अन्न रूप अर्थवाक् के रूप में शरीर में प्रवेश करता है और शब्दवाक् रूप में जीवन का संचालन करता है। शब्दों में निहित मंत्रशक्ति से भी लक्ष्मी को उत्पन्न किया जा सकता है। श्राप और वरदान रूप दिव्य कार्य किए जा सकते हैं। जैसे पुरुष में स्त्री एवं स्त्री में पुरुष रहता है, वैसे ही लक्ष्मी और सरस्वती में भी अविनाभाव है। जिह्वा मुख्य द्वार है इनका। **क्रमशः**

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

शरीर ही ब्रह्माण्ड

हमारी स्थूल सृष्टि अन्न से होती है। जीवात्मा का यात्रा मार्ग अन्न ही है अतः अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। दूसरी ओर शब्द भी परावाक् से निकलता है। शब्द भी ब्रह्म है। जीवन की विचित्रता देखिए! अन्न ग्रहण का माध्यम रसना है और वाक् विसर्जन का माध्यम भी जिहवा ही है। ब्रह्म ही अन्न रूप अर्थवाक् के रूप में शरीर में प्रवेश करता है और शब्दवाक् रूप में जीवन का संचालन करता है।

कैनसस सिटी: आकर्षित करता है सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी का यह अंदाज

यूनाइटेड स्टेट्स के मिसौरी राज्य के डाउनटाउन कैनसस सिटी की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है सार्वजनिक पुस्तकालय की केंद्रीय शाखा के लिए तैयार पार्किंग गैराज का यह आगे का हिस्सा। साइनबोर्ड माइलर से ढका हुआ यह हिस्सा ऐसा प्रतीत होता है मानो एक शेल्फ में पुस्तकें सजाकर रखी गई हों। इस मामले में 'पुस्तकें' 25 फीट ऊंची और नौ फीट चौड़ी हैं। 'पुस्तकों' के पीछे का गैराज 2006 में अतिरिक्त डाउनटाउन पार्किंग की आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया गया था। नई संरचना को सुंदर बनाने के तरीकों पर समुदाय से सुझाव आमंत्रित किए गए और अंततः बुकशेल्फ का विचार विकसित हुआ। समुदाय के सदस्यों और संरक्षकों से प्रदर्शित किए जाने वाले शीर्षकों पर वोट करने के लिए कहा गया और फिर साहित्य की 22 कालजयी रचनाएं चुनी गईं। इन शीर्षकों में जे.आर.आर. टोल्किन की 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' और रे ब्रैडबरी की 'फॉरेनहाइट 451' प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सोशल ट्रेंड: छात्र-छात्राओं की एकाग्रता का स्तर गिर रहा, चुनौती से निपटने में शिक्षण संस्थाओं की अहम भूमिका

फोन पास रहे या दूर, 'नोमोफोबिया' ने बढ़ाए मन के फितूर

प्रो. मनोज सक्सेना
अधिष्ठाता व विभागाध्यक्ष
शिक्षा स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

डॉ. सुमित चौहान
प्राचार्य, अवस्थी शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला
@patrika.com

यह महत्त्वपूर्ण है कि छात्र-छात्राएं अपने स्मार्टफोन के उपयोग के प्रति सचेत रहें, सीमाएं निर्धारित करें और अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

आज की बढ़ती डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन के बिना एक दिन गुजारने की कल्पना कठिन है। हम इनका उपयोग हर चीज के लिए करते हैं - जैसे मौसम की जांच करने से लेकर दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहने तक। पर कुछ लोगों के लिए अपने फोन के बिना रहने का विचार अत्यधिक चिंता का कारण बन गया है। इस डर को नोमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत नया शब्द है।

नोमोफोबिया शब्द का अर्थ नो-मोबाइल-फोन-फोबिया है। मोबाइल फोन के बिना रहने का यह डर भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है। आज की तेज-तर्रार प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में हमारे स्मार्टफोन दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। हम उनका उपयोग संचार और मनोरंजन के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई तरह से करते हैं। पर क्या होता है जब हम अपने फोन के बिना होते हैं? कई भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए फोन के बिना रहने का विचार भय और चिंता की भावना को उत्पन्न करता है जिसका नतीजा है नोमोफोबिया। डिजिटल तकनीक की यह देन एक ऐसी चिंता है जिसका सामना लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल न कर पाने के दौरान करते हैं। फोन में सिग्नल न होना, बैटरी खत्म होने का डर या कुछ समय तक नोटिफिकेशन न मिलने से भी वे चिंतित हो जाते हैं और यह चिंता उनमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करती है। युवा पीढ़ी में यह समस्या आम देखी जा रही है।

नोमोफोबिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, पर सामान्य संकेतों में बार-बार फोन चेक करना, बैटरी कम होने चिड़चिड़ा महसूस करना और जेब में फोन न होते हुए भी फोन के कंपन को महसूस करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त नोमोफोबिया छात्रों की नींद के पैटर्न को भी बाधित करता है क्योंकि उन्हें देर रात में भी अपने उपकरणों की लगातार जांच करने की जरूरत महसूस होती है। इससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र विकास प्रभावित होता है, क्योंकि हम सामाजिक संपर्क के लिए अपने फोन पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। इस निर्भरता से छात्र-छात्राओं के एकाग्रता के स्तर में भी कमी हो रही है।

नोमोफोबिया से निपटने के लिए शिक्षण संस्थानों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। उन्हें छात्रों को स्मार्टफोन के उपयोग के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। जब फोन के उपयोग की बात आती है तो सीमाएं निर्धारित करना और स्वस्थ आदतें स्थापित करना भी महत्त्वपूर्ण हैं जैसे फोन से ब्रेक लेना, ऐसी गतिविधियों में शामिल होना, जिनमें स्क्रीन शामिल नहीं हो और फोन पर ऐसी ऐप्स या सुविधाओं का उपयोग करना जो स्क्रीन समय को ट्रैक करती हों व उपयोग की सीमा निर्धारित करती हों। इससे आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आप अपने डिवाइस पर कितना समय बिता रहे हैं। यह बदलाव लाने में मददगार हो सकता है। स्मार्टफोन ने निस्संदेह हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है, यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि वे सिर्फ उपकरण हैं और वास्तविक मानवीय कनेक्शन का प्रतिस्थापन नहीं हैं। हम अपने मानवीय जीवन व डिजिटल दुनिया में एक स्वस्थ संतुलन बना सकते हैं।

कुल मिलाकर नोमोफोबिया तनाव और चिंता देकर अकेलेपन व अलगाव की भावना को बढ़ा रहा है और शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित करके विशेष रूप से छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उनके लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने स्मार्टफोन के उपयोग के प्रति सचेत रहें, सीमाएं निर्धारित करें और अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उचित कदम उठाएं।

आर्ट एंड कल्चर

जीवन को पोषित करती है कला-रूपों में अभिव्यक्त संस्कृति

आषाढ़ शास्त्रीय संगीत के मल्हार राग से भी जुड़ा हुआ है। राग मल्हार माने मूसलाधार बारिश। यह वक्र राग है। स्वर लगते हैं तो सीधे-सरल नहीं।

आषाढ़ माने वर्षा ऋतु की शुरुआत। असल में आषाढ़ सृजन के लिए उकसाने वाला महीना है। बरखा की बूंदें तन-मन को भिगोती सदा ही नया कुछ रचने को प्रेरित करती है। आषाढ़ अध्यात्म से आत्म चिंतन की ओर ले जाता माह भी है। बौद्ध साहित्य से जुड़ी थेर गाथाओं में एकांत से उपजी साधना का सार है। अंतर-उजास से जुड़ी अनुभूतियों में प्रकृति से जुड़ा मन जैसे यहां गाता है। यह बौद्ध भिक्षुओं के अनुभव हैं। वर्षा ऋतु से जुड़े अनुभव देखें, 'हे देव! मन भर बरसो। मेरी कुटी सुखदाई है। झंझावात जब मेघों को उड़ा ले जाता है, तब मेरे मन में निष्काम भाव जगते हैं। हे देव! जी भर बरसो।'

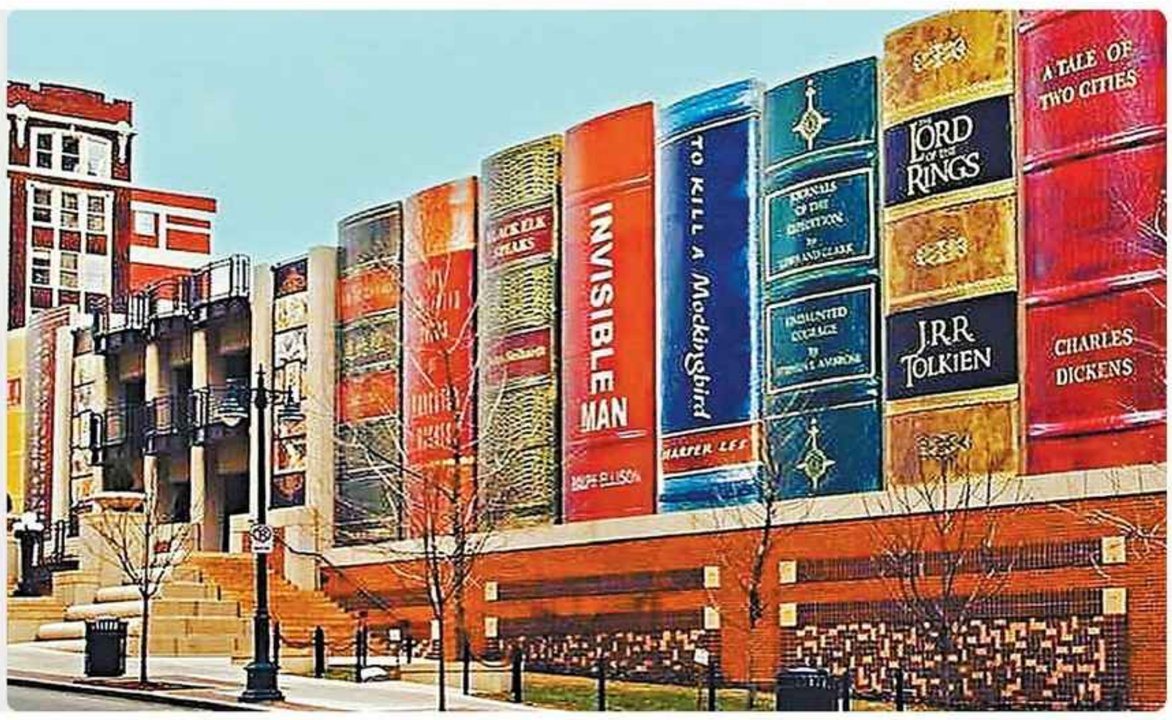

कालिदास तो प्रकृति से जुड़ी मानव संवेदना के सबसे बड़े कवि हैं। इसी आषाढ़ माह के प्रथम दिन आकाश पर उन्होंने उमडते-घुमडते मेघ देखे और प्रियतमा के लिए छटपटाते विरही यक्ष के आलोक में उन्होंने कालजयी 'मेघदूत' रच दिया। राजस्थानी बूंदी चित्रकला शैली के बहुत से चित्रों में आषाढ़ मास के मेघाच्छन्न आकाश की सुंदर दृश्यावली में संगमरमर के भवन के छज्जे और कृष्ण-राधा का प्रणय अंकन भी तो मन को मोहने वाला है।

डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक
@patrika.com

आषाढ़ शास्त्रीय संगीत के मल्हार राग से भी जुड़ा हुआ है। राग मल्हार माने मूसलाधार बारिश। यह वक्र राग है। स्वर लगते हैं तो सीधे-सरल नहीं। धैर्य के साथ धीर भी और गंभीर भी। मूसलाधार वर्षा की तरह। मेघ बरसते हैं तो मन हरखता है। आषाढ़ में मेघ बुलाने के लिए भी तो कितने-कितने जतन होते रहे हैं। 'रंग मल्हार' इसी की परिणति है। राजस्थान के ख्यात कलाकार विद्यासागर उपाध्याय और विनय शर्मा ने मिलकर वर्ष 2010 में इसे जयपुर में व्योम आर्ट गैलरी में एक रूप प्रदान किया था। आरंभ में पचास कलाकार एकत्र हुए और छातों को कैनवस बनाते हुए उन पर बादलों को रिझाने के लिए चित्र सिरजे गए। सफेद कैनवस के छातों पर रंग-रेखाओं का सुंदर संसार रचा गया। इसके बाद तो हर साल यह आयोजन होने लगा। लालटेन, पंखी, ग्लोब, मास्क, फिरकी, ध्वजा आदि में रंग-रेखाएं निरंतर सजती रहीं। इस बार का 'रंग मल्हार' एप्रन को केन्द्र में रखकर आयोजित हुआ। भारत भर के अलग-अलग नगरों और दूसरे देशों में भी कलाकारों ने 'रंग मल्हार' मनाते हुए एप्रन पर भाव-संवेदनाओं का आकाश उकेरा। रंग-रेखाओं से ही नहीं अन्य माध्यमों से भी एप्रन पर छवियों का अंकन हुआ। सोशल मीडिया के जरिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे साकार हुआ, संस्कृति कला-रूपों में अभिव्यक्ति पाकर जीवन को ऐसे ही पोषित करती है।

'रंग मल्हार' में निहित कला की विचार-दृष्टि महती है। इसलिए कि इसके जरिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में कला से जुड़ी सांस्कृतिक दृष्टि रूपायित हो रही है। इसलिए भी कि यह वर्षा के आमंत्रण से जुड़े विशिष्ट भारतीय कला दर्शन को इंगित पहल है।

आपकी बात

अनावश्यक उपयोग न करें

बच्चों में मोबाइल का बढ़ता उपयोग कई तरह के विकार उत्पन्न कर रहा है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए माता-पिता भी मोबाइल का अनावश्यक उपयोग न करें। मोबाइल की ब्राइटनेस ज्यादा न रखें और आंखों से दूरी का भी ध्यान रखें। मोबाइल देखते-देखते न सोएं। मोबाइल का सदुपयोग वरदान है और दुरुपयोग अभिशाप।

-मुकेश भटनागर, भिलाई, छत्तीसगढ़

अभिभावकों की जिम्मेदारी

हर तकनीक के फायदे और नुकसान होते हैं। मोबाइल पर भी यह बात लागू होती है। मोबाइल के अति उपयोग से खासकर बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावक अपने साथ बच्चों के लिए भी मोबाइल प्रयोग का समय निर्धारित करें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेलें।

-नरेश कानूनगो, देवास, मप्र

बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ें

बच्चों के माता-पिता को मोबाइल जैसे मामले में अधिक सावधान रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर ज्यादा व्यस्त न रहे। बच्चों में किताबों, अखबार और पारम्परिक खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करना चाहिए। साथ ही उनका बुजुर्गों के साथ जुड़ाव पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए।

-मनीषा कुमावत, राजगढ़, चूरू

बच्चों को गुमराह होने से बचाएं

बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहकर अपना समय और बचपन नष्ट कर रहे हैं।मोबाइल के कारण उनका का विकास अवरुद्ध हो रहा है और गलत राह पर जा रहे हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। बच्चों को गुमराह होने से बचाने के लिए आपत्तिजनक वेबसाइट्स पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

-नीता टहिलियानी, जयपुर

आज का सवाल

आपदा प्रबंधन तंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

कल का सवाल था: बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जा सकता है?

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 13 जुलाई, 2024

कल्पमेधा

सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता, जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है।
– जेम्स एलन

आंदोलन और अवरोध

किसान आंदोलन को दबाने की जैसी कोशिश हरियाणा सरकार ने की, वैसी देश में कहीं नहीं देखी गई। तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी थीं। फिर जब तीनों कानूनों को वापस लेते वक्त केंद्र सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे न किए जाने पर, पांच महीने पहले, दूसरी बार पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया तो हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा पर उन्हें रोक दिया। राजमार्ग पर दीवारें खड़ी कर दी गईं, मोटी-मोटी कीलें गाड़ दी गईं। किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया, तो कई दिन तक उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, ताकि वे वापस लौट जाएं। उस दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से गोलीबारी भी की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। राजमार्ग पर अवरोध खड़े किए जाने की वजह से रोजाना हजारों आम लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस इलाके के व्यापारियों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने वहां के उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार एक हफ्ते के भीतर राजमार्ग से अवरोधक हटा ले।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि हरियाणा सरकार को इस तरह राजमार्गों पर बाधा खड़ी करने का कोई हक नहीं है। राज्य सरकार की तो यातायात को सुगम बनाने की जिम्मेदारी होती है। दरअसल, गोलीबारी में मारे गए युवक की न्यायिक जांच कराने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। उसी की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शंभू सीमा से अवरोधक तुरंत हटाए जाएं। किसान भी नागरिक होते हैं और उन्हें सरकार के सामने अपनी मांग रखने का हक है। इसी तरह तीन कानूनों के विरोध में उठे आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बड़ी-बड़ी कीलें ठोंक दी गई थीं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और राजमार्गों को किसी भी रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। मगर लगता है कि अदालतों के बार-बार यह रेखांकित करने के बावजूद सरकारों को इस लोकतांत्रिक तकाजे की कोई परवाह नहीं है।

किसान कोई किसी दूसरे देश के सिपाही तो हैं नहीं कि उनके दिल्ली पर हमला कर देने का खतरा है। उन्होंने तो लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर अपनी मांगें रखने की अनुमति मांगी थी। मगर हरियाणा सरकार ने उनके साथ अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी। ये सवाल अब भी अपनी जगह बने हुए हैं कि तीन कानूनों को वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने जिन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, वे अभी तक पूरी क्यों नहीं की गईं। राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा संसद में उठाया था, मगर उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसानों की सबसे अहम मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाने को लेकर है। इसका वादा प्रधानमंत्री ने भी किया था, मगर इस दिशा में कोई पहल नजर नहीं आई। इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेने और कर्ज माफी की मांग है। सरकार अपने वादों पर भी आगे कदम नहीं बढ़ा रही, तो आंदोलन तो सिर उठाएंगे ही।

लापरवाही की बाढ़

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों से कभी लोगों के पानी के लिए तरसने की खबर आती है, तो कभी यहां के कुछ क्षेत्रों में पानी भर जाता है। पिछले महीने दिल्ली के कई हिस्सों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। तब दिल्ली सरकार का कहना था कि हरियाणा से यमुना में उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब यमुना की एक नहर में इतना पानी आ गया कि दिल्ली के बवाना में तटबंध टूट गए और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। यहां लोगों के लिए पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बाढ़ से जलशोधन संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। सरकार इस समस्या से जल्द निजात दिलाने का दावा कर रही है, लेकिन क्या समय रहते इस खतरे को टाला नहीं जा सकता था? दरअसल, हर साल बरसात में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना रहता है। पिछले साल भी यमुना के उफान से राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। जब सब कुछ पहले से अंदाजा रहता है, तो बाढ़ से बचने के दीर्घकालिक उपायों पर काम क्यों नहीं किया जाता?

दिल्ली के बवाना में जिस नहर के तटबंध टूटने से पानी भरा है, वह हरियाणा के करनाल से यमुना नदी से निकलने वाली मुनक नहर का हिस्सा है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि इस नहर की देखरेख का जिम्मा हरियाणा सरकार का है। पर जो नहर दिल्ली से होकर जा रही है, क्या उसकी निगरानी करने का कर्तव्य यहां के शासन-प्रशासन का नहीं बनता है? दिल्ली सरकार का कहना है कि संबंधित इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के बाद हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच की जाएगी। अगर इस नहर की नियमित निगरानी की जाती, तो इसके तटबंध टूटने से बचाने के उपाय समय रहते किए जा सकते थे। आशंका है कि ज्यादा बरसात के समय यमुना और इससे निकलने वाली नहरों में जलस्तर और खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सरकारों को बाढ़ के संभावित खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां

पिछले सात वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में सत्तर से अधिक परीक्षाओं के पर्चाफोड़ हुए हैं, जिससे करीब दो करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पर्चाफोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं।

ब्रजेश कुमार तिवारी

सर्वोच्च न्यायालय अब चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। पिछले महीने नतीजे घोषित होने के बाद से ही राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की साख पर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि नीट-यूजी का पर्चाफोड़ हुआ है। इस साल नीट-यूजी के लिए तेईस लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।

पर्चाफोड़ की इस घटना ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। हाल ही में लगातार चार परीक्षाओं- नीट-यूजी, यूजीसी-नेट, सीएसआइआर-नेट और अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षाएं या तो रद्द या स्थगित कर दी गईं, जिससे करीब सैंतीस लाख अभ्यर्थी और उनके अभिभावक सीधे प्रभावित हुए हैं। इन पर्चाफोड़ से न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। पूरी जांच के बाद ही परतें खुलेंगी, पर एनटीए पर उठ रहे सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है निजी एजंसियों को दिया जाने वाला ठेका।

भारत में अक्सर पर्चाफोड़ की खबरें आती रहती हैं। यह बीमारी कोई नई नहीं है, इसके चलते पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। 1997 में आइआइटी जेईई और 2011 में आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पर्चे भी बाहर आ चुके हैं। यह एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। मीडिया रपटों के मुताबिक पिछले सात वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में सत्तर से अधिक परीक्षाओं के पर्चाफोड़ हुए हैं, जिससे करीब दो करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पर्चाफोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथ ही, मां-बाप द्वारा पेट काट कर भेजा गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। सरकारें इसे लेकर गंभीर रहीं हैं, फिर भी पर्चाफोड़ रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहां नीयत और नीति दोनों की है, जिसका जवाब ये युवा उम्मीदवार कई सालों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक दूसरा पर्चाफोड़ हो जाता है।

राज्यों में भले सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं, मगर पर्चाफोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं, पद सालों-साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और जो होती भी है, वह पर्चाफोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पर्चाफोड़ की अलग-अलग विधि होती है, जैसे असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ सेकंड में पूरा पर्चा वाट्सएप पर प्रसारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश पर्चाफोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कपंनी के सर्वर में सेंधमारी की थी, जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में परिवहन निगम की जिस कंपनी को पर्चे छापने के बाद गोदामों में रखने की जिम्मेदारी दी गई, उसकी मिलीभगत से पर्चाफोड़ किया गया था। कई बार परीक्षा केंद्रों से भी पर्चाफोड़ किया जा चुका है।

पर्चाफोड़ न रोक पाना एक अक्षम्य अपराध है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का अपराध है। भारत की लगभग 65 फीसद आबादी युवा है। उनके सपने बड़े हैं। वे परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं, तमाम कठिनाइयों

> राज्यों में भले सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं, मगर पर्चाफोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा ही है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं, पद सालों-साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और जो होती भी है, वह पर्चाफोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पर्चाफोड़ की अलग-अलग विधि होती है, जैसे असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ सेकंड में पूरा पर्चा वाट्सएप पर प्रसारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश पर्चाफोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कपंनी के सर्वर में सेंधमारी की थी, जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

एवं अभावों से लड़ते-जूझते कई-कई वर्षों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जी-तोड़ तैयारी करते हैं। हालांकि पर्चाफोड़ और नकल कराने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा का कड़ा प्रावधान है। कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। हर साल सिविल सेवा परीक्षा में दस लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं, फिर भी यूपीएससी सुरक्षित परीक्षा आयोजित करता है। जहां तक आनलाइन पर्चे की बात है, प्रौद्योगिकी-आधारित परीक्षा/ आनलाइन परीक्षाओं के निरंतर उपयोग से इसमें रिसाव का खतरा रहेगा। खतरा बढ़ना तय है, अब एआइ का समय है, ऐसे में यह भविष्य में बड़ा खतरा होगा। अगर गृह मंत्रालय की वेबसाइट में सेंधमारी हो सकती है, तो ये परीक्षाएं कैसे सुरक्षित मानी जा सकती हैं?

पर्चाफोड़ अब अकेली, व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर के घोटाले नहीं रह गए हैं। जैसे-जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर तेजी से बढ़ा है, अनियमितता की प्रकृति भी बहुत बड़ी हो गई है। भर्ती आयोगों में राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। केंद्राध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने चाहिए। पर्चा तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर वितरण तक सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय हो। अधिकतर परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में होते हैं, उनमें से कई मानक के अनुरूप नहीं हैं। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक परीक्षा के पर्चाफोड़ का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है, इससे राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।

पारित अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि तीन साल है, जिसे दस साल करना चाहिए। वहीं, निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसमें समयबद्ध जांच का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवार को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए छात्र कमरतोड़ मेहनत करते हैं। मगर ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का हौसला अब हार रहा है। आज उनके अंदर निराशा है और इससे उनके परिवार का मनोबल भी टूट रहा है। परीक्षा एजंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो या एक घंटे पहले साफ्ट कापी को 'कोड लाक' के माध्यम से सीधे भेजा जाए और परीक्षा केंद्र में मौजूद अभ्यर्थियों को वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाए। इस विधि से प्रश्नपत्र प्रेस छपाई से थोड़े महंगे जरूर होंगे, पर सुरक्षित होंगे। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्चा बनाने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर उसको भी बंद किया जाए। पर्चा तैयार होने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो।

सन्नाटे से संवाद

शिखर चंद जैन

दुनिया मेरे आगे

कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। कई जगह यह भी कहा जाता है कि दीवारें बोलती हैं। मगर ये बातें और कहावतें अब पुरानी हो गई हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इंसान ने भी सुनना और बोलना बंद कर दिया है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि एक ही जगह बैठे परिजन एक दूसरे से वाट्सएप पर संदेशों के जरिए या मोबाइल फोन के माध्यम से बातें करते दिख जाते हैं। इस डिजिटल दुनिया में आदमी इंसानियत, भावनाओं और संवेदनाओं से मानो शून्य होता जा रहा है। संवाद करने की कला, एक दूसरे की भावनाओं का आदर, किसी की तकलीफ, क्रोध, दुख या खुशी को चेहरा देखकर पहचानने की कला लुप्त होती जा रही है।

डर यह है कि कहीं हम एक दिन इंसान को सामने देख कर भी पहचानना, उसकी बातों को समझना और सुनना, अभिवादन करना या अपनी भावनाएं प्रकट करना भूल न जाएं! जब हम लंबे समय तक चलते-फिरते नहीं, हाथ-पैरों का उपयोग नहीं करते तो वे सुन्न पड़ने लगते हैं और शिथिल होने लगते हैं, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ऐसा ही दिमाग के मामले में भी होता है। मशीनरी भी लंबे समय तक न चले तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इसीलिए चिंता है कि हमारी जीभ, स्वर-तंत्र, दिमाग का भावनात्मक हिस्सा भी इसी शिथिलता का शिकार न हो जाए।

विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसे हमारी शारीरिक मांसपेशियां होती हैं, ठीक वैसे ही सामाजिक मांसपेशियां भी होती हैं। जब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते तो ये सुन्न होने लगती हैं। संवाद या बातचीत कम करने पर हमारी याददाश्त और दिमागी सक्रियता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना बहुत हद तक संभव है। हमने देखा भी होगा कि घर के बुजुर्ग लंबे समय तक अकेले रहने के कारण और जब उनसे कोई संवाद नहीं करता, बच्चे दूर हो जाते हैं और जीवनसाथी से बिछोह हो चुका होता है, वे कई बार चाहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों और हाव-भाव का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अकेलापन उनसे उनका स्वाभाविक व्यवहार छीन लेता है।

> आदमी अकेला होता जा रहा है। इस अकेलेपन का चयन वह खुद करता है, फिर अकेलेपन से दुखी होता है। राशन, कपड़े भोजन ही नहीं, शिक्षा और चिकित्सा भी 'आनलाइन' होने लगी है। मगर इस क्रम में इंसान की जिंदगी 'आफलाइन' होने यानी पटरी से उतरने लगी है।

संवादहीनता, अकेलेपन और संवेदनहीनता का ऐसा ही उदाहरण युवाओं में भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जो अकेलापन और उपेक्षित महसूस करने के कारण अवसाद में चले जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वे युवा होते हैं जो इलेक्ट्रानिक उपकरणों, इंटरनेट और स्मार्टफोन के जाल में फंस कर वास्तविक दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। ये स्नेह या प्यार भरे स्पर्श, सुखद या मनमोहक दृश्य और मधुर व अपनेपन भरी आवाज के जादुई प्रभाव को महसूस ही नहीं कर पाते।

आजकल पति-पत्नी के बीच 'साइलेंट ट्रीटमेंट' यानी चुप्पी और अबोला या शीत युद्ध की विषैली प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तरफ परस्पर बातचीत करने और अपनी आशंकाएं, नाराजगी, डर या समस्याएं साझा करने से मन हल्का होता है, वहीं पति-पत्नी के बीच यह अबोला शीतयुद्ध उनके संबंध, घर के माहौल, सेहत और बच्चों के मिजाज को बिगाड़ने वाला साबित होता है। संवादहीनता और चुप्पी के कई दुष्प्रभाव होते हैं। कई बार हम किसी के प्रति नाराजगी जताने या उसे सजा देने के लिए उससे बात करना बंद कर देते हैं। कभी-कभी यह सिलसिला लंबा खिंच जाता है तो इसके कई दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं।

बीस साल तक 'आस्ट्रेसिज्म' यानी बहिष्कार का अध्ययन करने वाले परड्यु यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर किपलिंग विलियम्स का कहना है कि किसी व्यक्ति की अनदेखी करना, अपनी गतिविधियों या आम दिनचर्या से उसे दूर रखना और उसकी किसी बात का जवाब न देना अक्सर उसके प्रति नाराजगी जताने और उसे सजा देने के लिए किया जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति को न सिर्फ भावनात्मक, बल्कि शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकता है। बहिष्कार को प्रभावित व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। वह इसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। चुप्पी, बहिष्कार या 'साइलेंट ट्रीटमेंट' के असर से प्रभावित व्यक्ति के दिमाग का वह हिस्सा (एंटीरियर सिंगुलेट कोरटेक्स) सक्रिय हो जाता है जो शारीरिक पीड़ा के दौरान होता है। कम्युनिकेशन स्टडीज के प्रोफेसर पाल श्रोडेट ने अपने एक विश्लेषण में पाया कि 'साइलेंट ट्रीटमेंट' से किसी भी रिश्ते को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। इसके प्रभाव से युगल के बीच अंतरंगता खत्म होती है और स्वस्थ व सार्थक संवाद की स्थिति नहीं रहती। युगल के बीच गुस्सा जताने का यह बहुत आम तरीका है, लेकिन इसका प्रभाव झगड़े से कहीं ज्यादा नुकसानदायक होता है।

एक समय था जब लोग पारिवारिक शादी या अन्य अनुष्ठानों में दो-तीन दिन इकट्ठा ठहरते थे। एक ही कमरे, हाल या शामियाने में कई लोग एक साथ रहते और खूब गप करते थे। अब कोई दूर से जाता भी है तो होटल में अलग कमरे दे दिए जाते हैं। रिश्तेदार की मृत्यु पर शोक की घड़ी में भी बहुत मुश्किल से कोई घंटे-आधे घंटे ठहरता है या बातचीत करता है। पहले लोग सामान लेने बाजार जाते थे तो दो-चार लोगों से बातचीत होती थी। अब आनलाइन खरीदारी के कारण वह सिलसिला भी बंद होता जा रहा है। आदमी अकेला होता जा रहा है। इस अकेलेपन का चयन वह खुद करता है, फिर अकेलेपन से दुखी होता है। राशन, कपड़े भोजन ही नहीं, शिक्षा और चिकित्सा भी 'आनलाइन' होने लगी है। मगर इस क्रम में इंसान की जिंदगी 'आफलाइन' होने यानी पटरी से उतरने लगी है। अगर हम एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जरूरत है लोगों से मिलने-जुलने और संवाद की। संवाद के माध्यम से ही संवेदनाएं और भावनाएं पुनर्जीवित की जा सकती हैं।

भूख के सामने

गरीब की थाली से गायब होते पोषक तत्त्व अपने आप में एक बड़ी समस्या है। वहीं जब बात बच्चों की हो तो यह किसी संकट से कम नहीं। यह हैरानी की बात है कि आज पांच वर्ष या उससे कम आयु के हर चौथे बच्चे को पोषक भोजन नहीं मिल पा रहा है। दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु के करोड़ों बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये वे बच्चे हैं, जिनके पास पर्याप्त पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं है। भारत में जहां 40 फीसद बच्चे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गंभीर खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं, वहीं 36 फीसद बच्चे ऐसे हैं जो इस खाद्य निर्धनता के मध्यम स्तर का सामना करने को मजबूर हैं। देखा जाए तो गंभीर खाद्य निर्धनता का सामना करने वाले इन बच्चों के जानलेवा कुपोषण से पीड़ित होने की आशंका 50 फीसद तक अधिक होती है। ये तथ्य संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी नई रपट 'चाइल्ड फूड पावर्टीः न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड' में सामने आए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक जब बच्चों को अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में स्वस्थ, पोषण और विविधता से भरपूर पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति को खाद्य निर्धनता के रूप में जाना जाता है।

– प्रसिद्ध यादव, पटना

आपदा से पहले

भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसका पूर्वप्रबंधन किया जाए तो जानमाल का नुकसान कम किया जा सकता है। जो भी विकास कार्य किए जाते हैं, उन पर भूकम्प तबाही लाकर सब मटियामेट कर देता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार हिमालयन प्लेट के संधि स्थल पर सर्वाधिक दबाव बन रहा है। उनका मानना है कि जब कभी भूगर्भीय संरचना में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण धरती में से ऊष्मा उत्सर्जित होकर निकलती है, वह भूकम्प आने का एक लक्षण दर्शाती है। भूकम्प के खतरे को देखते हुए अभी से बचाव के प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। जहां भूकम्प के छोटे-बड़े झटके आते हैं और भूगर्भीय धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती हो, वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। भूकम्प को रोका तो नहीं जा सकता, मगर उससे विनाश को कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी प्रदेशों में भूकम्प अवरोधी संरचना और अन्य कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार

पुनरावृत्ति न हो

हाथरस में हाल में एक सत्संग समागम में लाखों लोगों के जुटने और वहां हुई भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत पीड़ित परिजनों, देश की एक बड़ी क्षति है। प्रशासन की कथित सक्रियता के बावजूद भोले बाबा और उसके अनुयायी इतने बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने में सफल रहे, लेकिन न केवल आयोजकों के स्तर पर, बल्कि खुद प्रशासन की ओर से भी घोर लापरवाही बरती गई। नतीजतन तमाम कायदे-कानूनों को धता बताते हुए लगाए गए अस्थायी तंबू में अराजकता का माहौल देखने को मिला। अनहोनी की स्थिति में न तो वहां एंबुलेंस पहुंचने के लिए खुला रास्ता था और न ही आपातकालीन निकास की ठोस कार्ययोजना थी। अब त्वरित अदालत के माध्यम से दोषियों को यथाशीघ्र सख्त दंड मिलना चाहिए। बड़े स्तर पर उन्माद से भरे आयोजनों की अनुमति देने से पूर्व शासन-प्रशासन को समूची व्यवस्था का सिंहावलोकन कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे हृदय विदारक घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो।

– युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

भविष्य के लिए

'बूंद बूंद भविष्य' (दुनिया मेरे आगे, 4 जुलाई) पढ़ा। मानसून का आगमन हो चुका है और हर तरफ नजारों के खुशनुमा होने की उम्मीद की जाती है। कुदरती लिहाज से देखें तो हरियाली मन मोह रही है और यही मौका है जब हम मिलकर खूब पौधे लगाएं, क्योंकि बरसात के पानी में पौधे आसानी से बड़े होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं और फिर कई साल ये मानव समाज को फायदा पहुंचाते रहेंगे। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोककर हमें स्वस्थ और लंबा जीवन प्रदान करेंगे। यों भी हमारी संस्कृति में पेड़-पौधों का काफी महत्त्व है। दुनिया भर में आबोहवा की जो हालत होती जा रही है, उसमें यथासंभव पौधों को लगाकर ही जीवन की उम्मीद की जा सकेगी। वृक्षों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि ये प्रकृति के सर्वोत्तम उपहारों में से एक है।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

बिम्सटेक के विकास में भारत के लिए अवसर

दरकार
आर.के. सिन्हा

भारत को ब्रिटेन की नई सरकार से यह भी उम्मीद रहेगी कि पिछले साल भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार तत्वों पर अब कठोर एक्शन लिया जाए। ऋषि सुनक सरकार ने भी खालिस्तान समर्थक संगठनों पर चाबुक चलानी शुरू कर दी थी। ये संगठन ब्रिटेन में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। इन संगठनों में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन वगैरह शामिल हैं। खालिस्तानी फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए बनाई एसटीएफ ने खालिस्तान समर्थकों के 300 से ज्यादा बैंक खाते सील किए हैं। भारत-ब्रिटेन संबंधों में बेहतरी तभी आएगी, जब वहां खालिस्तानी समर्थक कसे जाएंगे।

भारत को बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) को मजबूत करने पर खास ध्यान देना चाहिए। बिम्सटेक के सभी सदस्य देश भारत के मित्र पड़ोसी देश हैं। सात सदस्यीय बिम्सटेक में पांच दक्षिण एशियाई देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान और दो दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमा व थाईलैंड शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक ताकतवर भारत ही है, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। सभी के साथ भारत के मधुर संबंध हैं, हालांकि ये देश चीन के प्रभाव में भी हैं। भारत बिम्सटेक का न केवल विकास इंजन बन सकता है, बल्कि वह सदस्य देशों को सामरिक सुरक्षा भी दे सकता है। जब भारत की ग्लोबल भूमिका बढ़ने की बात आती है, ऐसे ही छोटे-छोटे कदमों से वह भूमिका का विस्तार कर सकता है। वर्ष 1997 में बिम्सटेक की स्थापना हुई है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, इसके बावजूद भारत ने इस बहुपक्षीय संगठन के मंच से अपने पड़ोसी देशों के विकास में बड़ा योगदान नहीं दिया है। मोदी सरकार के आने के बाद से बिम्सटेक को प्राथमिकता दी जा रही है, जो चीन से मुकाबला की दृष्टि से जरूरी कदम है। बिम्सटेक क्षेत्र न केवल संसाधन के लिहाज से बल्कि सामरिक सुरक्षा के लिहाज से भी भारत के लिए अहम है। एशिया की तेजी से बदलती भू-रणनीतिक स्थिति में भारत के पास बंगाल की खाड़ी का लाभ उठाकर अधिक मुखर और सक्षम चीन को नियंत्रित करनक का अवसर है। भारत का दायित्व है कि सभी की संप्रभुता का सम्मान करते हुए बिम्सटेक देशों के विकास में अपना योगदान दे और सुरक्षा भी प्रदान करे। चूंकि भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का भी आर्थिक वर्चस्व है, इसलिए भारत को चाहिए कि वह चीनी पैठ अपने पड़ोस तक न होने दे। बिम्सटेक के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में हुई, इसके अंतिम दिन विदेश मंत्रियों ने पीएम नरेन्द्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्सटेक की भूमिका पर जोर दिया। बिम्सटेक ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया है। इस वर्ष सितम्बर में बिम्सटेक का शिखर सम्मेलन थाईलैंड में होना है, जिसमें सहयोग बढ़ाने के अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स की तर्ज पर भारत को बिम्सटेक बैंक के गठन को लेकर पहल करनी चाहिए, इसमें भारत को एक बड़ा कोष बनाना चाहिए। यह बैंक बिम्सटेक देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, डिजिटल इन्फ्रा को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन करने आदि में अहम योगदान कर सकता है। यह बैंक भारत को पड़ोसी फर्स्ट व एक्ट ईस्ट की नीति के संवर्धन में सहयोग करेगा। इन देशों को विश्वास में लेकर सैन्य सुरक्षा का मार्ग भी भारत प्रशस्त कर सकता है। बिम्स्टेक छोटा पर व्यापक भारतीय प्रभाव वाला मंच बन सकता है। बिम्स्टेक आसियान के सदस्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग हेतु भी मंच प्रदान करता है। भारत व म्यांमा को जोड़ने वाली कलादान मल्टीमॉडल परियोजना, म्यांमा होकर भारत को थाईलैंड से जोड़ने वाली एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह के लिए बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता आदि अहम विकास प्रोजेक्ट हैं, जो बिम्सटेक की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। बिम्सटेक देशों के बीच वीजा मुक्त आवाजाही होनी चाहिए।

ब्रिटेन में कसे जाएं खालिस्तानी

ब्रिटेन के हालिया चुनावों में लेबर पार्टी की महत्वपूर्ण जीत से साबित हो गया कि ब्रिटेन की राजनीति में भारतीय प्रवासी समाज की भूमिका बेहद खास है। ब्रिटेन के चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि वहां की राजनीति में भारतीय प्रवासियों की ताकत बढ़ती ही जा रही है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 26 भारतीय मूल के नेता नई संसद के लिए चुने गए हैं। सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की। सुनक की पार्टी की शिवानी राजा ने लीजेस्टर ईस्ट की सीट जीत ली है। लीजेस्टर ईस्ट की लड़ाई में कई दिग्गज शामिल थे, जिनमें पूर्व सांसद क्लाउड वेबे और कीथ वाज शामिल थे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। कीथ वाज भी भारतीय मूल के ही हैं। वे पहले भी संसद के सदस्य रहे हैं। शिवानी राजा शिक्षा की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। वो लंबे समय से कंजरवेटिव पार्टी की एक्टिविस्ट हैं। भारत में जन्मे कनिष्क नारायण पूर्व वेल्स की सीट से जीत गए हैं। वे भी कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवार थे। बिहार के मुजफ्फरपुर के मूल निवासी कनिष्क नारायण 12 साल की उम्र में ब्रिटेन आ गए थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और फिर स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने फेयरहैम और वाटरलूविल सीट जीती है। उनके पिता गोवा के और मां तमिल मूल की हैं। पंजाबी हिन्दू परिवार से संबंध रखने वाले गगन मोहिन्दर फिर से साउथ-वेस्ट हर्टफोर्डशायर सीट से चुनाव जीत गए हैं। निवर्तमान संसद के सदस्य नवेंदु मिश्र लेबर पार्टी की टिकट पर स्टॉकपोर्ट सीट से कामयाब रहे हैं। वो मूलतः कानपुर से हैं। ब्रिटेन की निवर्तमान संसद में भी 15 भारतीय मूल के सांसद थे। ब्रिटेन के आम चुनाव 2024 में, कुल 107 ब्रिटिश-भारतीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे।

भारत-ब्रिटेन संबंधों को देखा जाए तो इसके प्रमुख रूप से पांच आयाम हैं। ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत भी ब्रिटेन में नई परियोजनाएं शुरू करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण आयातक देश है। हालांकि यह भारत को बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारत की कंपनियों की भी बड़ी अहम भूमिका है। भारतीयों की स्वामित्व वाली 700 से ज़्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। टाटा ग्रुप की ही कंपनियों ने ब्रिटेन में हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। वहां हिन्दुजा, लक्ष्मी मित्तल, स्वराज पॉल जैसे बहुत सारे बड़े उद्योगपति रहते स्थायी रूप से रहकर ही देश-विदेश में अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के हज़ारों छात्र ब्रिटेन में पढ़ाई करने भी हर साल जाते हैं। हां, भारत के युवाओं में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पढ़ाई, नौकरी या निवेश करने का चलन भी बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच 200 साल से भी अधिक का पुराना संबंध है। दोनों ही देश सांस्कृतिक संस्थानों और अंग्रेज़ी से माध्यम से जुड़े हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों को मज़बूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले करीब 15

लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। ये प्रवासी भारतीय न केवल ब्रिटेन और भारत के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने भारत की संस्कृति से ब्रिटेन को संपन्न भी किया है। प्रवासी भारतीय ब्रिटेन में हर क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से मौजूद हैं। अब चाहे वो व्यापार, राजनीति, खेल का क्षेत्र हो या कोई और इन्होंने सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुक़ाम हासिल किया है।

भारत को ब्रिटेन की नई सरकार से यह भी उम्मीद रहेगी कि पिछले साल भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार तत्वों पर अब कठोर एक्शन लिया जाए। ऋषि सुनक सरकार ने भी खालिस्तान समर्थक संगठनों पर चाबुक चलानी शुरू कर दी थी। ये संगठन ब्रिटेन में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। इन संगठनों में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालसा टेलीविजन लिमिटेड, खालिस्तानी टेलीविजन चैनल वगैरह शामिल हैं। ब्रिटेन में खालिस्तानी फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स ने खालिस्तान समर्थकों के 300 से ज्यादा बैंक खाते सील करके 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जब्त की है। भारत-ब्रिटेन संबंधों में बेहतरी तभी आएगी, जब वहां खालिस्तानी समर्थक कसे जाएंगे। अब भारत-ब्रिटेन का यह लक्ष्य रहेगा कि दोनों देश व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएं। पिछली 4 जुलाई को ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनावों के परिणाम व्यापक रूप से अपेक्षित थे। कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी को 34 फीसदी वोटों के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों में से 410 सीटों पर जीत मिली। वे अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी भी भारतीय सनातनी परम्पराओं में गहरी आस्था है और वे नियमित रूप से हिन्दू मंदिरों में जाते रहे हैं। हालिया चुनाव परिणाम भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ही प्रस्तुत करते हैं, जो पिछले दो दशकों में लगातार मजबूत होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से बात की और उन्हें पीएम चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विगत शनिवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से बात करते हुए उन्हें लेबर पार्टी की उल्लेखनीय जीत पर बधाई दी। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को मोदी ने भारत आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन के बीच एफटीए को जल्द फाइनल करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई। भारत और ब्रिटेन के बीच आपसी संबंध मजबूत करने के लिहाज से एफटीए का काफी महत्व है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए दोनों ही देश कोशिशें कर रहे हैं। इस बाबत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल गंभीरता से प्रयास करते रहे हैं। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में कुल 26 अध्याय हैं, जिनमें से अधिकतर पर आपसी सहमति बन गई है। अगर एफटीए हो जाता है तो इससे दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार के मौके को बढ़ावा मिलेगा। अभी ब्रिटेन के साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो भारत के पक्ष में ही थोड़ा झुका है। यानी भारत आयात के मुकाबले ब्रिटेन को निर्यात ज्यादा करता है। हालांकि आयात-निर्यात के बीच का यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है।

भविष्य में भारत-ब्रिटेन के साथ संबंधों में लगातार बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। भारत चाहेगा कि नई सरकार ब्रिटेन में भारत विरोधी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाए और पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करे। वैसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का कश्मीर पर रुख जग-जाहिर है। वे कश्मीर विवाद को पूर्णतः भारत का अंदरूनी मामला मानते हैं और कश्मीर में किसी भी तरह के पाकिस्तानी हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ हैं।

(लेखक पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सत्य के प्रति जागने में ही है 'जीवन की महत्ता'

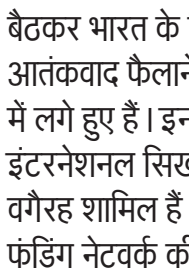

संकलित
दर्शन

प्रत्येक व्यक्ति का इस जगत में आना एक संयोग है और यह संयोग परमात्मा की कृपा की देन है, लेकिन संसार में सभी के आने का संयोग कुछ पाने के लिए है, खोने के लिए नहीं। इसलिए कि खोना आसान है, परंतु पाना बहुत ही कठिन है। संसार में प्रायः लोग सोने वाले हैं, जागने वाले कम। जागने वाले ही कुछ पाते हैं और सोने वाले सब कुछ खो देते हैं। जागने वाले ही इस संसार में जीवित हैं और सोने वाले मृत। सच्चाई के लिए जागना ही है, जड़ता का त्याग। जड़ता के त्याग के बिना पशुता की स्थिति से उबरना संभव नहीं है। जड़ता सुषुप्ति की अवस्था है और जड़ता का त्याग जागृतावस्था। जागृतावस्था में जीवन के उत्थान, विकास, महानता प्राप्ति का संयोग है और सुषुप्तावस्था में मृत्यु, पतन, अवनति, निंदा, दुखभरी स्थिति है। जागने में भलाई है और सोने में बुराई है। यह पतन की ओर ले जाने वाला है। व्यक्ति जन्म के समय न कुछ लेकर आता और न ही मृत्यु के समय कुछ लेकर जाता है। झूठ बोलकर की गई सारी कमाई यहीं रह जाती हैं, लेकिन सत्य की कमाई सदा साथ रहती है। त्याग, प्रेम, सत्य, जिम्मेदारी के प्रति जागना ही जीवन में सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही पुण्य की कमाई है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। परमात्मा तो सिर्फ सत्य मार्ग पर चलने वाले का साथ देता है और कुमार्गगामी को दंड भी देता है। सत्य के प्रति सजगता ही चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना होता है। इसके विपरीत असत्य के प्रति चेतना की जागृति विनाश, पतन का मूल है। परमात्मा प्रदत्त यह काया क्षणभंगुर है, पर इसके अंदर स्थित आत्मा अविनाशी है।

गुरु का स्थान श्रेष्ठ

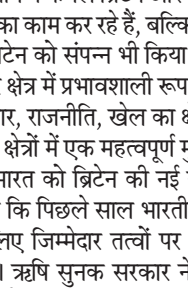

संकलित
प्रेरणा

एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री-परिषद् के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे परन्तु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिये। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरूजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, हे गुरुवर क्षमा कीजियेगा, मैं कई महिनो से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है ? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दियाः राजन इसका कारण बहुत ही सीधा सा है.. गुरूजी ने कहाः राजन बात बहुत छोटी है परन्तु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझ से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं परन्तु यहाँ पर आप का और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है।.. गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परन्तु आप स्वंय ऊँचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आप से यह बात नहीं कह पा रहा था।

सारा संसार

मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले के मैहर शहर में त्रिकुटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित मैहर माता मंदिर भारत के सबसे दिव्य मंदिरों में से एक है। मैहर माता का यह प्राचीन मंदिर माँ शारदा देवी की पूजा अर्चना और उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है।

सजगता
डॉ. मोनिका शर्मा

सैर सपाटे में अनुशासन जरूरी

बीते दिनों महाराष्ट्र के लोनावला में भुशी बांध पर सैर-सपाटा करने पहुंचा एक पूरा परिवार झरने के पानी में बह गया। इस अनहोनी के वायरल वीडियो में तेज बहाव के बीच समूह बनाकर खड़े बच्चे-बड़े भय से चीखते देख रहे हैं। पानी की गति इतनी तेज थी कि हादसे में एक ही परिवार के नौ में से पांच सदस्य डूब गए। बरसात ने अभी दस्तक दी ही है, पर देशभर के पर्यटन स्थलों पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में बोकारो में ग्रामीणों ने दामोदर नदी में डूबते चार युवकों की जान बचाई, जो दामोदर नदी में स्नान करते हुए तेज़ बहाव में डूब गए थे। हर वर्ष ही बरसात के मौसम में सैर सपाटे के निकले लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होतीं हैं। इन हादसों का सबसे दुखद पक्ष यह है कि कभी सुरक्षा नियमों की अनदेखी तो कभी अति-आत्मविश्वास के चलते लोगों का जीवन छिन जाता है। तकलीफदेह है कि बरसात के सुहावने मौसम में सैर-सपाटा करते लोग अपनी जान को जोखिम में डालने की गलती करते हैं। इस मौसम में बांध, नदी, झरने वाली जगहों पर ही पर्यटक जाना पसंद करते हैं। ऐसे अधिकतर स्थल आबादी वाली जगहों से दूर होते हैं, जिसके चलते समय पर बचाव दल का पहुंचना भी कठिन होता है। इतना ही नहीं बारिश में ऐसी जगहों पर अचानक पानी का बहाव तेज़ होने की भी संभावना रहती है। कहां और किस तरह दुर्घटना हो जाए यह समझना कठिन होता है। कहीं चट्टान वाली जगह पर फिसलन की आशंका रहती है तो कहीं पानी की गहराई की जानकारी नहीं होती। अचानक तेज वर्षा होने पर कई स्थलों का पानी का बहाव रौद्र रूप ले लेता है। लोनावला में भुशी बांध पर हुए हादसे में पूरा परिवार यूं झरने के पानी की तेज गति की ही अपने चपेट में आ गया। ध्यातव्य है कि अधिकतर मामलों में लोग भारी बरसात के अलर्ट, दुर्घटना स्थल से जुड़ी चेतावनियों और पर्यटन स्थल पर सुरक्षा को लेकर जारी नियमावली को भी नहीं मानते। पहाड़ी क्षेत्र हो या नदी-समुद्र जोखिमपूर्ण हिस्सों में भी पहुंच जाते हैं, जबकि प्रशासनिक अमले द्वारा समय-समय पर मानसून के मौसम में सैर सपाटे के दौरान ऐहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। सैलानियों की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थलों पर सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों वाले बोर्ड लगाए जाते हैं। कई स्थलों को प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। बावजूद इसके पर्यटक स्थलों पर न केवल सतर्कता की कमी ही देखने को मिलती है, बल्कि नियमों की अनदेखी की जाती है। हालिया बरसों में वर्चुअल दुनिया का दिखावा भी पर्यटन स्थलों पर होने वाले हादसे का कारण बना है। रील-वीडियो बनाने, विशेष तरह की तस्वीरें खींचने और अजब-गजब करतब करने के इरादे से की गई गतिविधियां दुर्घटनाओं को न्योता देने वाली साबित होती हैं। बीते दिनों गुजरात के कच्छ में मुंद्रा समुद्र तट पर इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्टंट के करने के लिए समुद्र में उतारी दो गाड़ियों को पानी के तेज़ बहाव ने डुबो ही दिया था कि लोगों की मदद से उनकी जिंदगी बच सकी। इन्हीं दिनों बिहार के समस्तीपुर में रील बनाने के जुनून में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से तीन किशोरों की जान चली गई है। यह वाकई पीड़ादायी है कि आभासी दुनिया में विशेष उपस्थिति दर्ज करवाने के फेर में भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, जबकि इन्हीं तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल मौसम की सही जानकारी लेने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह की दुर्घटनाओं पर सजगता से ही लगाम लग सकती है। नियमों का पालन और सैर-सपाटे के समय भी अनुशासन का भाव ही जीवन सहेज सकता है।

(लेखिका फ्रीलांसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

रथ यात्रा उत्सव

पुरी में शुक्रवार को वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के तहत भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा, बहुदा यात्रा की तैयारियों के दौरान पुलिसकर्मी एक रथ खींचते हुए।

आज की पाती

बेरोजगारों को मिले मौका

हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक तकनीक ने बेरोजगारी की समस्या के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। इसलिए अब सरकारों को ऐसी नीतियों को अपने वोट बैंक के लिए लगाम कसने की जरूरत है जो बेरोजगारी को बढ़ाती हों। हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है, ताकि हर बेरोजगार को रोजगार मिल सके। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार नहीं देना चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिल सके। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन या एक कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार की मांग करता है तो उन्हें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या इससे उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? शायद नहीं। - संजय पटेल, भाटापारा

ट्रेंड

नीतियों को समावेशी बना रहे

वर्ष 2016 में हमने परिवार विकास मिशन आरंभ किया था। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी इस शुरुआत के सकारात्मक परिणाम आए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हम अपनी नीतियों को लगातार अधिक समावेशी और प्रभावी बना रहे हैं।

-जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री

मानवाधिकारों के लिए अहम

लैंगिक समानता हासिल करना लोगों के मानवाधिकारों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे तेजी से विकास या गिरावट जैसे सबसे चरम जनसांख्यिकीय परिणामों का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।

-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

सत्य की जीत

झूठे केस लगाकर सच को कब तक क़ैद में रखोगे। पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है।

-संजय सिंह, आप नेता

जैव विविधता पार्क बनाया

हमने पुणे में संरक्षण के लिए एक बंजर भूमि से उड़ान जैव विविधता पार्क बनाया है! दुर्लभ शिव सुमन पौधा, जो एक समय गंभीर रूप से लुप्तप्राय था, वापस लौट रहा है। ब्लू मॉर्मन (तितली) भी यहां पनपती है!

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

करंट अफेयर

यूएई में एक सड़क भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। नगर पालिका और परिवहन विभाग (डीएमटी) ने डॉ. जॉर्ज मैथ्यू के योगदान को मान्यता देने के लिए अबू धाबी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। यह नाम, "यूएई के दूरदर्शी लोगों का सम्मान : स्मृति मार्ग" परियोजना के तहत दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अल मफराक में शेख शाकबूथ मेडिकल सिटी के पास की सड़क अब 'जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट' के नाम से जानी जाएगी। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए डॉ. मैथ्यू ने कहा, "जब मैं पहली बार यूएई पहुंचा था, तब बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा था। राष्ट्रपिता दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से प्रेरित होकर मैंने लोगों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे प्रयासों को मान्यता मिली है।" डॉ. मैथ्यू 1967 में 26 वर्ष की आयु में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे।

ऑफ बीट

चार दिन का सप्ताह हो सकता है कारगर

सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले कई लोगों को यह एक सपने जैसा लग सकता है कि केवल चार दिन काम और एक लंबा सप्ताहांत। जब सप्ताहांत बहुत छोटा लगता है और पूर्णकालिक नौकरी को बचाने का दबाव श्रमिकों को सिरे तक धकेल देता है, तो चार-दिवसीय कार्य सप्ताह बहुत आकर्षक लग सकता है। हालाँकि व्यवहार में ऐसा कैसे होता है, और क्या यह आम बात बन सकती है? खैर, चार-दिवसीय कार्य सप्ताह परीक्षणों के बारे में हालिया खबरें अलग-अलग परिणाम दिखाती हैं। यूके में सबसे बड़े परीक्षण (जिसमें 60 से अधिक कंपनियां और लगभग 3,000 कर्मचारी शामिल थे) के नतीजों से पता चला कि 89% भाग लेने वाली कंपनियां अभी भी चार-दिवसीय सप्ताह लागू कर रही हैं, और 51% ने इसे स्थायी बनाने का फैसला किया है। अध्ययन से पता चलता है कि इस नयी व्यवस्था से कर्मचारियों की थकान में कमी आई और कम लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, जो अन्य अध्ययनों के अनुरूप है। कुछ दिन पहले, सुपरमार्केट श्रृंखला एस्डा ने इसे जारी न रखने का निर्णय लेते हुए, चार-दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ अपना स्वयं का प्रयोग समाप्त किया। लेकिन साथ ही, साउथ कैंब्रिजशायर काउंसिल ने अपने परीक्षण को सफल घोषित किया है, जिसमें 450 डेस्क कर्मचारी और कचरा संग्रहकर्ता शामिल थे।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

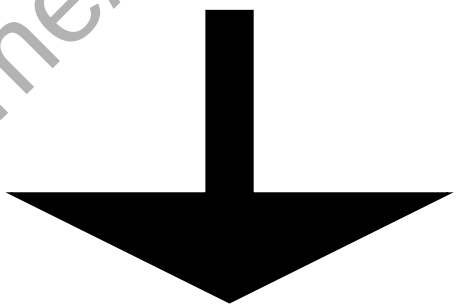

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid